सोशल मीडिया से जुड़ें
Parivehan_Vishesh

RNI No :- DELHIN/2023/86499
DCP Licensing Number :
F.2 (P-2) Press/2023

www.newsparivahan.com

# परिवहन विशेष

वर्ष 02, अंक 261, नई दिल्ली । रविवार, 01 दिसम्बर 2024, मूल्य ₹ 5, पेज 8

देश का पहला ट्रांसपोर्ट दैनिक समाचार पत्र

आज का सुविचार

अगर भाग्य पर भरोसा है तो जो तकदीर में लिखा है वही पाओगे, और अगर खुद पर भरोसा है तो जो चाहोगे वही पाओगे।

03 ग्रेटर कैलाश में पदयात्रा के दौरान केजरीवाल पर फेंका गया 'लिक्विड'
06 कॅरिअर ग्रोथ के लिए कौशल हो आधार
08 अप्रसांगिकता की ओर बढ़ती भारतीय संसद

# सरकार और सरकारी विभागों के प्रमुख प्रदूषण के नाम पर सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी को गुमराह कर दिल्ली की जनता को महंगाई और जुर्माने की मार देकर राजस्व में इजाफा करवाने का कार्य कर रहे है जाने

संजय बाटला

**नई दिल्ली।** आज मौसम पोर्टल के मुताबिक दिल्ली में हवा में लटकते

1. महीन कण पीएम 10 माइक्रोन वाले 364 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर हैं।

2. जिनमे से मोटे पीएम 2.5 माइक्रोन 299 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर हैं।

इसका अर्थ हुआ की दिल्ली की टूटी फूटी सड़कों से सबसे ज़्यादा धूल उड़ कर हवा में मिल रही है।

1. सड़कों और सड़क किनारे पटरियों पर धुल मिट्टी के ढेर पड़े हैं और सरकार इसकी सफाई नहीं करवाना चाहती।

2. सरकार वैक्यूम सेक्शन से भी धूल नहीं उठवा रही है,

3. सरकार पानी छिड़कवाने का दिखावा कर जनता, प्रशासन और न्यायिक प्रणाली की आंखों में सिर्फ धूल झोंक रही है।

4. सरकार को ना तो कोई भी टूटी फूटी सड़क नजर आ रही और ना ही उनकी मरमत करवाना और ना ही इसके लिए अपना कर्तव्य नहीं निभाने वाले मेंटेनेंस इंजीनियरों के खिलाफ कोई कार्यवाही करना,

**अर्थ सब कुछ सरकार की अपनी सोची समझी रणनीति के तहत हो रहा है**

सरकार अपनी ग़लती को छुपाने के साथ जनता, प्रशासन और न्यायिक प्रणाली को

घुमा फिरा कर इस धूल को कंस्ट्रक्शन से उठती धूल बता कर ग्रेप लगाकर प्रदूषण के बहाने से कंस्ट्रक्शन रुकवा कर हज़ारों / लाखो मजदूरों के चूल्हे ठंडे करके मुस्करा रही हैं।

364 में से 65 महीन कण धुंए के है जो ठंड से बचने के लिए गरीबों, मजदूरों, चौकीदारों और गार्ड के कार्य में लगे लोगों द्वारा रात को ठंड के प्रकोप से बचने के लिए लकड़ियों एवम्टायरों को जला कर आग सेकते है के कारण उत्पन्न हो रहा है क्योंकि उनके पास बिजली के हीटर और गर्म कपड़ों की कमी है और सरकार उसे बिजली के हीटर और गर्म कपड़े मुहैया नहीं करवा रही क्योंकि इस उत्पन्न धुएं को पराली का धुआं बता कर किसानों और दूसरे राज्यों पर इल्जाम लगाने का बहाना मिल जाता है और अपनी खामियों को छुपा कर सभी से पल्ला झाड़ रही हैं।

इसमें भी शक नहीं की कुछ अड़यिल किसानों की वजह से पराली का धुआं बनता है पर दिल्ली तक ना के बराबर ही पहुंचता है।

आज भट्ठों की चिमनिया ऊंची होती हैं और उनमें कम्पलीट बर्निंग होकर ही गैसें बाहर निकलती हैं जो चिमनी से एक आध किलोमीटर में ही सिमट जाती हैं और हवा की गति अगर 5 किलोमीटर से ज़्यादा की चल रही हो तो वह हवा में ही मिलकर नगण्य हो जाती हैं पर सरकार प्रदूषण के नाम से भट्ठे बन्द करवाकर ईंटों के रेट बढ़वा देती है।

इंडस्ट्री चलाने के लिए इंडस्ट्री से निकलने वाले धुंए व गैसों के लिए कानून बहुत सख्त हैं और उनके द्वारा फिल्टर ना लगाने पर भारी जुर्माने के साथ फैक्ट्री सील तक हो सकती हैं। लेकिन सरकार उसके बाद भी प्रदूषण का नाम लेकर इंडस्ट्री को बंद करवा कर महंगाई करवा रही है।

1. नाइट्रोजन पेरोक्साइड की मात्रा पेरमिसिबल 10 में से सिर्फ 2 है जो 81 माइक्रोग्राम प्रति मीटर है।

2. सल्फर डाइऑक्साइड 10 में से केवल 1 है जो 60 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर है।

3. ओज़ोन भी 1 है जो केवल 24 माइक्रोग्राम है।

**तीनो को मिला कर मतलब यह निकलता है कि आज के प्रदूषण में ना तो पराली बर्निंग वाली गैस और ना ही ट्रकों के डीज़ल, पेट्रोल और सीएनजी का हिस्सा है।**

दिल्ली परिवहन विभाग दिल्ली में ट्रकों को आने से रोक कर दिल्ली में वस्तुओं की कीमत बढ़वाने में मददगार बन जनता का शोषण कर रहा है।

**एक्युआई उपरोक्त सभी कणों के जोड़ का हवा के प्रति क्यूबिक मीटर में माइक्रोग्राम में नाप होता है।**

हवा चलती रहे और स्पीड 5 किलोमीटर से ज़्यादा हो तो सभी विफताओं के बावजूद एक्यूआई 100 से ऊपर नहीं जा सकता।

तापमान गिरने से डीईडबल्यु पॉइंट 13 तक आना स्वाभाविक है और ह्यूमिडिटी अब 74% है जिस कारण पानी की बूंदों की धुंध बन जाती है। शातिर दिमाग के लोग विडियो बना कर और फ़ोटो खींच कर उसे प्रदूषण बता कर स्कूल दफ्तर बन्द करवा रहें हैं।

ऊपर लिखित तथ्यों से काफी हद तक यह सिद्ध होता है की दिल्ली में प्रदूषण के हालात सरकारी तंत्र की कमजोरी और कामचोरी है ना की वाहन, कंस्ट्रक्शन या इंडस्ट्री। **अगर प्रदूषण नियंत्रित रखना है तो सड़कों की मरम्मत के साथ सफाई सबसे ज्यादा जरूरी हैं जो राज्य सरकार और सरकारी विभागों का कार्य है ना की जनता का।**

# बस मार्शलों की बहाली को लेकर सियासत जारी
# अब कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को सुनाई खरी-खरी

परिवहन विशेष न्यूज

दिल्ली में बस मार्शलों की बहाली को लेकर आम आदमी पार्टी और भाजपा के बीच सियासत जारी है। मार्शल अपनी पुनर्नियुक्ति की मांग को लेकर अनशन पर बैठे हैं लेकिन सरकार उनकी सुध लेने को तैयार नहीं है। कांग्रेस ने इस मामले में दोनों पार्टियों पर निशाना साधा है और मार्शलों की तुरंत बहाली की मांग की है।

**नई दिल्ली।** प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने कहा कि आप सरकार और भाजपा बस मार्शलों की की पुनः नियुक्ति को दिल्ली विधानसभा चुनावों में भुनाने के चक्कर में इनके घरों के चूल्हे बुझा रही हैं।

अपने परिवारजनों के भरण पोषण से परेशान मार्शल दोनों पार्टियों की राजनीति का शिकार हो रहे हैं। यादव ने कहा कि बर्खास्त 10,000 बस मार्शलों को एक नवंबर तक बहाल करने के एलजी के निर्देश के बावजूद, आम आदमी पार्टी सरकार ने अभी तक एलजी के आदेश का पालन नहीं किया है।

**आप सरकार के कानों पर नहीं रेंग रही जूं-कांग्रेस ने AAP को घेरा**

मुख्यमंत्री आतिशी (Atishi) ने मार्शलों को फिर से नियुक्त का मामला एक बार फिर एलजी के पाले में डाल दिया है। उन्होंने कहा कि अपनी पुनर्नियुक्ति की मांग को लेकर अनशन पर बैठे मार्शल भुखमरी की कगार पर हैं लेकिन आप सरकार के कानों पर जूं नही रेंग रही है।

यादव ने कहा कि केजरीवाल और सीएम आतिशी मार्शलों के जीवन के साथ खेल रहे हैं। आतिशी ने विधानसभा में बोलते हुए एलजी से मार्शलों को बहाल करने की मंजूरी मांगी, जबकि एलजी ने आम आदमी पार्टी की सरकार को ऐसा करने का निर्देश पहले ही दिया हुआ है।

**बस मार्शलों की तुरंत की जाए बहाली-कांग्रेस ने की मांग**

उन्होंने कहा कि भाजपा और आम आदमी पार्टी ने मार्शलों पर राजनीति करके इनसे झूठे वादे और दावे किए हैं। कांग्रेस मांग करती है कि बस मार्शलों की तुरंत बहाली की जाए।

दिल्ली विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू (Delhi Assembly Winter Session) हो गया है। वंदे मातरम गीत के साथ 15 मिनट देरी से

विधानसभा सत्र की शुरुआत हुई। सत्र की कार्रवाही के दौरान स्पीकर और विपक्ष के विधायकों के बीच नोकझोंक हुई। पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने सदन में बोलते हुए कहा कि ये लॉरेंस बिश्नोई कौन है, कैसे वह जेल में बैठ कर गैंग कैसे चला रहा है।

इसके बारे में अमित शाह को बताना पड़ेगा। बिश्नोई गैंग, भाऊ ग्रैंड, गोगी गैंग, ऐसे दर्जन भर गैंग दिल्ली के अंदर सक्रिय हैं। कोई बता रहा था इन्होंने अपने एरिया बांट रखे हैं। बता दें भाजपा के विधायकों ने बस मार्शल के मुद्दे उठाए। सदन के हंगामेदार होने के बाद बुधवार के लिए स्थगित कर दी गई।

# डिपो में धूल खा रहीं 100 मोहल्ला बसें: अभी तक सिर्फ ट्रायल, दिल्ली में लास्ट माइल कनेक्टिविटी कैसे होगी मजबूत

परिवहन विशेष न्यूज

दिल्ली सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी मोहल्ला बस योजना अभी तक शुरू नहीं हुई है। जबकि डिपो में 100 बसें आ चुकी है लेकिन इसके बाद भी ट्रायल छह रूट्स पर जारी है। लेकिन योजना लागू नहीं हुई है।

**नई दिल्ली।** दिल्ली सरकार की महत्वाकांक्षी मोहल्ला बस योजना को अभी तक आधिकारिक तौर पर शुरू नहीं किया जा सका है। मौजूदा समय में छह रूटों पर इन बसों का ट्रायल किया जा रहा है। दो माह पहले ही लगभग 100 मोहल्ला बसें आ चुकी हैं जो डिपो में धूल खा रही हैं। इन बसों को ऐसे में क्षेत्रों में चलाने की योजना है कि जहां पर डीटीसी और क्लस्टर बसों की पहुंच नहीं है। यह बसें लास्ट माइल कनेक्टिविटी के लिए महत्वपूर्ण हैं। इनसे न केवल प्रमुख मेट्रो स्टेशन कवर होंगे, बल्कि स्कूल-कॉलेज आदि को भी जोड़ा जाएगा। यह बसें सामान्य बसों से छोटी हैं। ऐसे में यह संकरे क्षेत्रों में भी आसानी से जा सकती हैं, इसलिए इन्हें मोहल्ला बस कहा गया है।

मोहल्ला बसें दिल्ली में लास्ट माइल कनेक्टिविटी को मजबूत करने में बहुत अहम साबित होंगी। इससे लोग निजी वाहनों को छोड़कर सार्वजनिक परिवहन को अपनाएंगे। शुरुआत में बसों को ट्रायल के तौर पर दो रूट पर चलाया गया। इसके बाद संख्या बढ़ाकर छह की गई। इन सभी जगहों पर बीते दो से तीन माह से बसों का संचालन चल रहा है। अधिकारियों का कहना

है कि बसों का ट्रायल भी सफल रहा है। पंजीकरण प्रक्रिया भी पूरी कर ली गई है। बसों में सुरक्षा और निगरानी के लिए जरूरी उपकरणों की फिटिंग की जांच आदि भी की जा चुकी है।

बसों के रूट भी तय कर लिए गए हैं। शुरू में आधिकारिक तौर पर 25 से अधिक रूटों पर इन्हें चलाया जाएगा। योजना के तहत दिल्ली भर में 2000 से अधिक नौ मीटर से कम लंबाई की मोहल्ला बसें चलाने की योजना है। यह सभी बसें इलेक्ट्रिक होंगी। इसमें जीपीएस, पैनिक बटन समेत सुरक्षा के लिए कई बंदोबस्त किए गए हैं।

**अड़चन जल्द होगी दूर**

परिवहन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि बसों को लांच करने से पहले एक सर्टिफिकेट की जरूरत है। इसे लेकर बस निर्माता एजेंसियों के साथ बैठकों का दौर चल रहा है। सूत्रों ने बताया कि स्वदेशी उपकरणों को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार की पहल को ध्यान में रखते हुए इलेक्ट्रिक बसों को खरीदने के लिए जो टेंडर जारी किया गया था, उसमें इंडिजिनाइजेशन से जुड़ी कुछ शर्तें थीं। उसमें यह था कि कौन-कौन से उपकरण आयात किए जा सकते हैं और कौन से नहीं, इसकी सूची केंद्र सरकार ने बनाई हुई है। उसी आधार पर टेंडर दस्तावेज में शर्तें जोड़ी गई थीं, लेकिन जिन दो निर्माताओं से बसें खरीदी गईं, उन्होंने जब इस शर्त को पूरा करने और इंडिजिनाइजेशन का सर्टिफिकेट लेने के लिए एक्सपर्ट एजेंसी आई कैट (इंटरनैशनल सेंटर फॉर ऑटोमोटिव टेक्नॉलजी) से संपर्क किया, तो पता चला कि मार्च के बाद से आई कैट ने इंडिजिनाइजेशन सर्टिफिकेट जारी करना बंद कर दिया है।

# मानकों पर मनमानी कर रहे स्कूल, डीओई की रोक के बावजूद परिवहन के लिए तय किए इतने अकं

शिक्षा निदेशालय ने कुछ मानकों को दाखिला मानकों में शामिल करने पर रोक लगाई है। दाखिले के सौ अंकों के फॉर्मूले में अपनी सुविधा के अनुसार मानक रख स्कूल मनमानी कर रहे हैं।

**नई दिल्ली।** दिल्ली के निजी स्कूलों में नर्सरी, केजी, व पहली कक्षा में दाखिले के लिए आवेदन की दौड़ शुरू हो चुकी है। दाखिले के सौ अंकों के फॉर्मूले में अपनी सुविधा के अनुसार मानक रख स्कूल मनमानी कर रहे हैं। कुछ स्कूलों ने जहां स्कूल परिवहन के लिए पांच से 20 अंक तय किए हैं, तो वहीं कुछ स्कूल अभिभावकों की खेल व संस्कृति में उपलब्धि के लिए भी अंक दे रहे हैं। स्कूलों के अजीबो-गरीब मानक अभिभावकों को परेशान कर रहे हैं।

**मनमानी कर रहे हैं स्कूल**

शिक्षा निदेशालय ने कुछ मानकों को दाखिला मानकों में शामिल करने पर रोक लगाई है। इसके बावजूद कुछ स्कूलों ने मनमानी करते हुए अपनी सुविधा के अनुसार मानक तय किए हैं। इसमें बस रूट पर रहने के अंक, स्कूल परिवहन का इस्तेमाल करने के अंक दिए गए हैं। नियमानुसार स्कूल पड़ोस (नेबरहुड) के आधार पर बच्चे को अंक दे सकते हैं। लेकिन परिवहन के लिए अंक देने पर मनाही है। पूर्वी दिल्ली स्थित भाई परमानंद विद्या मंदिर स्कूल ने वह एरिया जहां स्कूल परिवहन उपलब्ध है, उसे अपने मानकों में 15 अंक के साथ शामिल किया है।

**अभिभावकों की खेल और संस्कृति में उपलब्धियों पर भी दे रहे अंक**

जनरल राजस स्कूल परिवहन के लिए पांच अंक दे रहा है। स्कूल ने अभिभावकों के संगीत व खेल में राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने के लिए भी पांच अंक शामिल किए हैं। साकेत स्थित एपीजे स्कूल ने स्कूल का परिवहन इस्तेमाल करने पर 10 अंक और यदि बच्चा ऐसे क्षेत्र में रहता है जहां परिवहन सुविधा उपलब्ध है, इस मानक के लिए पांच अंक तय किए हैं। रोहिणी स्थित मैक्सफोर्ट स्कूल ने स्कूल परिवहन का उपयोग करने पर 20 अंक तय किए हैं।

# क्या है ब्लैक फ्राइडे और कैसे हुई इसकी शुरुआत? क्यों मिलता है इस दिन भारी डिस्काउंट

सोशल मीडिया पर इन दिनों हर तरफ बस Black Friday का ही जिक्र हो रहा है। इस खास मौके पर कई दुकाने और ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स भारी डिस्काउंट(Black Friday discounts) भी देती हैं। हर दिन हर साल थैंक्सगिविंग के अगले दिन मनाया जाता है। आज इस आर्टिकल में हम आपको बताएंगे कैसे हुए दिन की शुरुआत और इससे जुड़ी सभी खास बातें।

**नई दिल्ली।** ब्लैक फ्राइडे हर साल अमेरिका में मनाया जाता है। यह दिन हर साल थैंक्सगिविंग के बाद आने वाला शुक्रवार को मनाया जाता है। इसी क्रम में इस साल 29 नवंबर को यह दिन सेलिब्रेट किया जाएगा। यह दिन आमतौर क्रिसमस शॉपिंग सीजन की शुरुआत होता है। यही वजह है कि इन दिनों हर शॉपिंग साइट पर आपको भारी डिस्काउंट का ऑफर देखने को मिल रहा है। पिछले कुछ दिनों का आप हर जगह ब्लैक फ्राइडे और इस मौके पर मिलने बारे भारी डिस्काउंट (Black Friday discounts) के बारे में देख रहे होंगे।

ऐसे में सवाल यह उठता है कि आखिर ब्लैक फ्राइड (Black Friday history) और शॉपिंग साइट्स पर मिल रहे डिस्काउंट का एक-दूसरे से क्या कनेक्शन है। आइए आपको इस आर्टिकल में बताते हैं कि क्या है Black Friday और क्या है इसके सेल और डिस्काउंट (Black Friday shopping trends) से कनेक्शन-

**क्या है ब्लैक फ्राइडे?**

ब्लैक फ्राइडे मुख्य रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका में मनाया जाता है। इस दिन को हर साल थैंक्सगिविंग के अलगे दिन मनाते हैं। अमेरिका में प्रचलित यह दिन पिछले कुछ समय से दुनिया के अन्य हिस्सों में मनाया जाने लगा है। इस दिन के साथ ही ऑफिशियली फेस्टिव सीजन यानी क्रिसमस की तैयारियां शुरू हो जाती हैं और ब्लैक फ्राइडे के साथ ही क्रिसमस के लिए खरीदारी भी शुरू हो जाती है। यही वजह है कि इस खास मौके पर दुकानदारों और अलग-अलग शॉपिंग वेबसाइट्स द्वारा लोगों को भारी छूट मिलती है।

**क्यों मनाया जाता है ब्लैक फ्राइडे?**

इस शब्द की शुरुआत 1960 और 1970 के दशक में फिलाडेल्फिया पुलिस ने की थी। दरअसल, इस शब्व का इस्तेमाल पुलिस ने थैंक्सगिविंग के अगले दिन शहर में अराजक दृश्यों का वर्णन करने के लिए किया था। ऐसा इसलिए क्योंकि एक तरफ जहां लोग फेस्टिव माहौल में वीकेंड पर क्रिसमस की खरीदारी और अपने करीबियो के साथ अपनी छुट्टियों का मजा ले रहे थे, तो वहीं सकड़ों पर जमा हुई भारी भीड़ को संभालने के लिए पुलिसकर्मियों को लगातार काम करना पड़ रहा था।

ऐसे में अपने कभी न खत्म होने वाले काम को बताते के मकसद से पुलिसकर्मियों ने इस दिन को ब्लैक फ्राइडे का नाम दिया। हालांकि, खुदरा विक्रेताओं ने इस शब्द के नकारात्मक अर्थ को नापसंद करते हुए इस रब्रिग फ्राइडेर का नाम देने की कोशिश की, लेकिन रब्लैक फ्राइडेर के नाम से भी प्रचलित हो गया।

**वर्तमान में क्या है इस दिन के मायने?**

मौजूद समय में ब्लैक फ्राइडे दुनिया भर में खरीदारी के सबसे महत्वपूर्ण दिनों में से एक माना जाता है। इस दिन दुकानों और ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स दोनों जगहों पर भारी छूट दी पेशकश दी जाती है। अब यह एक सांस्कृतिक और आर्थिक घटना बन गया है, जो उपभोक्तावाद, सौदों और फेस्टिव सीजन में खरीदारी का प्रतीक है। भले ही इस दिन की शुरुआत अराजक या नकारात्मक रही, लेकिन अब यह दुकानदारों और खरीदारों दोनों के लिए एक खास दिन बन गया है।

# सिर्फ सेक्सुअल कॉन्टैक्ट नहीं इन वजहों से भी फैलता है एड्स, बचने के लिए अपनाएं डॉक्टर के बताए टिप्स

हर साल 1 दिसंबर को World Aids Day मनाया जाता है। यह दिन इस बीमारी के प्रति लोगों को जागरूक और इससे पीड़ित लोगों के सम्मान में मनाया जाता है। कई लोगों का मानना है कि सिर्फ शारीरिक संबंध बनाने से यह बीमारी फैलती है। हालांकि यह पूरी तरह सच नहीं है। यह बीमारी अन्य तरीकों से ऊा व्यक्ति को अपना शिकार बना सकती है।

**नई दिल्ली।** एड्स एक खतरनाक बीमारी है, जिसे लेकर आज भी लोगों के मन में कई सारे सवाल मौजूद हैं। ऐसी बीमारियों को लेकर लोगों की अधूरी जानकारी उन्हीं के लिए हानिकारक साबित होती है। ऐसे में इस बीमारी के प्रति लोगों को जागरूक बनाने के मकसद हर साल 1 दिसंबर को World Aids Day मनाया जाता है। यह दिन खासतौर पर लोगों को इस गंभीर बीमारी के लिए जागरूक करने और इस बीमारी से पीड़ित लोगों के सम्मान में मनाया जाता है।

आमतौर पर इस बीमारी के बारे में खुलकर बात करने से लोग हिचकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि लोग इस मिथक पर यकीन करते हैं कि एड्स सिर्फ शारीरिक संबंध यानी सेक्सुअल एक्टिविटी की वजह से लोगों को अपना शिकार बनाता है। हालांकि, यह पूरी तरह सच नहीं है। ऐसे में एड्स डे के मौके पर हम आपको बताएंगे क्या है यह बीमारी और कैसे सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के अलावा यह किन तरीकों से लोगों को अपना शिकार बना सकती हैं। इस बारे में विस्तार से बता रही हैं सीके बिड़ला हॉस्पिटल, गुरुग्राम में ऑब्सटेट्रिक्स और गाइनेकोलॉजी की निदेशक डॉ. आस्था दयाल-

**एड्स क्या है?**

WHO के मुताबिक एड्स एक खतरनाक बीमारी है, जो ह्यूमन इम्युनोडेफिशिएंसी वायरस यानी HIV वायरस के कारण व्यक्ति को अपना शिकार बनाती है। यह वायरस शरीर के इम्यून सिस्टम पर हमला करता है। एक्वायर्ड इम्युनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम (AIDS) एचआईवी वायरस के कारण हुए संक्रमण का लास्ट स्टेज होता है।

**कैसे फैलता है एड्स?**

डॉक्टर बताती हैं कि एड्स यौन संपर्क से फैल सकता हैं। हालांकि, यह शारीरिक संबंध बनाए बिना भी व्यक्ति को अपना शिकार बना सकता है। यह ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस (एचआईवी) के कारण होता है, जो कुछ शारीरिक तरल पदार्थों से फैलता है। इसके फैलने के अन्य तरीकों में एचआईवी संक्रमित खून से दूषित सुई या सिरिंज का इस्तेमाल करना, संक्रमित खून या ब्लड प्रोडक्ट्स के संपर्क में आना और प्रेग्नेंसी, बच्चे के जन्म के दौरान या ब्रेस्टफीडिंग के जरिए एचआईवी पॉजिटिव मां से उसके बच्चे में फैल सकता है।

इसके अलावा अनजाने में या अचानक संक्रमित सुई के चुभने से लगी चोट के कारण हेल्थ केयर वर्कर भी एचआईवी के संपर्क में आ सकते हैं। हालांकि, एचआईवी पीड़ित व्यक्ति के गले मिलने, हाथ मिलाने या साथ खाना खाने से नहीं फैलता है। साथ ही यह हवा, पानी या कीड़े के काटने से भी नहीं फैलता है।

**कैसे करें इससे बचाव?**

- किसी के साथ ही सुई और सीरिंज शेयर करने से बचें।
- सिर्फ चेक किए गए ब्लड प्रोडक्ट्स का ही इस्तेमाल करें।
- अगर आप हेल्थ केयर वर्कर हैं, तो संभावित संक्रामक सामग्रियों से डील करते समय सुरक्षा उपकरण का इस्तेमाल करें।
- एचआईवी से पीड़ित बच्चों को जन्म देने वाली महिलाओं को बच्चे में वायरस फैलने की संभावना को कम करने के लिए मेडिकल केयर लेनी चाहिए।
- एआरटी एचआईवी के इलाज में बेहद प्रभावी है और इसके फैलने की संभावना को कम करता है।
- एचआईवी के बारे में सीखना, सुरक्षित इंजेक्शन लगाना और जागरूकता बढ़ाना इस वायरस को फैलने से रोकने में काफी हद तक मदद कर सकता है।

# डायबिटीज़ के मरीज डाइट में शाम लि करें ये लो कैलोरी वाली सब ज यिां, ब्लड शुगर रहेगा कंट्रोल

Diabetes के मरीजों को अपने खानपान का खास ख याल रखना होता है। उन हें अपनी डाइट में Low Calorie और High fibre वाली सब्जियों को शामि ल करने की सलाह दी जाती है। ये हरी सब्जियां ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में मदद करती हैं। इसके साथ ही इंसुलिन रेजिस्टेंस को भी कम करती हैं। एक हेल दी लाइफस टाइल को अपनाकर डायबिटीज के खतरे को कम किया जा सकता है।

**नई द ल्ली।** आज के समय में Diabetes अपने पांव तेजी से पसार रहा है। डायबिटीज का कोई इलाज नहीं है। आपकी जागरूकता ही आपको बचा सकती है। डायबटिीज के मरीजों को खान पान पर वशिष ध्यान देने की जरूरत होती है। अगर आप भी पूरी जिंदगी दवाओं पर नर्भिर नहीं रहना चाहते हैं तो आपको अपनी Diet में कुछ बदलाव जरूर कर लेना चाहिए। डायबिटीज और Insulin रेजिस्टेंस जैसी स्थितियों में डाइट अहत भूमकिा नभिाता है। ऐसे में Low Calorie और पोषण से भरपूर वाली सब्जियां खाने से न केवल Blood Sugar Level कंट्रोल में रहता है, बल्कि इंसुलिन भी बेहतर होती है। आज हम आपको लो कैलोरीज वाली सब्जयिों के बारे में बताने जा रहे हैं जसिे डायबटिीज के मरीजों को अपनी डाइट में जरूर शामलि करना चाहए। आइए जानते हैं विस्तार से-

**पालक (Spinach)**

आयरन, मैग्नीशियम, और विटामिन K से भरपूर पालक में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बहुत कम पाई जाती है। यह ब्लड शुगर को स्थिर रखने और पाचन में सुधार करने में मदद करता है। आप पालक को सलाद, सूप या सब्जी के रूप में डाइट में शामलि कर सकते हैं।

**लौकी (Bottle Gourd)**

लौकी खाने से हर कसिी को ढेरों फायदे मलिते हैं। इसको आसानी से पचाया भी जा सकता है। लौकी डायबिटीज के मरीजों को जरूर खानी चाहए। क्योंकि इसमें फाइबर, विटामिन C, और पोटैशियम जैसे तत्व पाए जाते हैं। आप इसको सब्जी, रायता या जूस के रूप में डाइट में शामलि कर सकते हैं।

**करेला (Bitter Gourd)**

करेले को डायबिटीज के लिए सुपरफूड माना जाता है। यह ब्लड शुगर को कम करने और इंसुलिन बढ़ाने में मददगार है। इसमें भरपूर मात्रा में पोषक तत्व पाए जाते हैं। डायबटिीज के मरीजों को रोजाना सुबह करेले का जूस पीने की सलाह दी जाती है। आप इसे सब्जी बनाकर भी खा सकते हैं।

**ब्रोकली (Broccoli)**

ब्रोकली एंटीऑक्सीडेंट और फाइबर का बेहतरीन स्रोत है। ब्रोकली खाने से ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल कयिा जा सकता है। इसमें विटामिन C और K के साथ क्रोमियम की भरपूर मात्रा पाई जाती है। आप इसे सलाद, जूस या सब्जी के रूप में खा सकते हैं।

**भिंडी (Lady Finger)**

भिंडी भी फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट का बेहतरीन स्रोत होते हैं। इसमें विटामिन A, C और कैल्शियम जैसे तत्व पाए जाते हैं। जो शुगर के अवशोषण को धीमा कर इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करते हैं। आप इसे सब्जी, रायता के रूप में डाइट में शामिल कर सकते हैं।

**फूलगोभी (Cauliflower)**

फूलगोभी में कार्बोहाइड्रेट कम मात्रा में पाया जाती है। यह लो कैलोरी का होता है। फूलगोभी से ब्लड शुगर को मेंटेन रखा जा सकता है। आप इसका सेवन पराठा, सूप या भुजिया के रूप में कर सकते हैं।

**टमाटर (Tomato)**

टमाटर कम कैलोरी वाली सब्जी होती है। इसमें शुगर भी कम मात्रा में होती है। आपको बता दें कटिमाटर में भरपूर मात्रा में लाइकोपीन और विटामिन C जैसे तत्व पाए जाते हैं। आप इसे सूप, सलाद या सब्जी के रूप में खा सकते हैं।

# क्या आपको पता है भारत के संविधान से जुड़ी 10 हैरान करने वाली बातें

भारत को लोकतांत्रिक देश हमारे संविधान ने बनाया है। यह कोई मामूली दस्तावेज नहीं है बल्कि यह भारत की अखंडता और एकता को बनाए रखने में अहम भूमिका निभाता है। 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ था इसलिए इस दिन को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। आइए जानें इससे जुड़ी रोचक बातें।

**नई दिल्ली।** हर साल 26 नवंबर के दिन संविधान दिवस (National Constitution Day 2024) मनाया जाता है। भारत के लिए यह दिन बेहद खास है और काफी अहमियत रखता है। डॉ. बी. आर. अंबेडर की अध्यक्षता में इसी दिन 1949 में भारत के संविधान को अपनाया गया था। हालांकि, ध्यान देने वाली बात यह है कि इसे लागू 26 जनवरी 1950 को किया था, लेकिन 26 नवंबर को इसलिए खास माना जाता है, क्योंकि इस दिन संविधान को अंतिम स्वरूप दिया गया था।

भारत का संविधान एक ऐसा दस्तावेज है, जिसने भारत को एक लोकतांत्रिक देश बनाया है। यह एक ऐसा दस्तावेज है, जो हमारी विविधता को स्वीकार करता है और सभी नागरिकों को समानता का अधिकार देता है। इसलिए संविधान दिवस हमारे लिए बेहद खास है। आइए इसी मौके (75th Constitution Day of India) पर भारत के संविधान से जुड़ी कुछ ऐसी हैरान करने वाली बातों पर नजर डालते हैं, जिनके बारे में शायद आप नहीं जानते होंगे।

**सबसे लंबा लिखित संविधान**

भारत का संविधान दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है। इसमें 448 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां और 25 भाग हैं। इसकी विशालता का कारण यह है कि इसमें भारत की विविधता और जटिलताओं को अपने भीतर समाए हुए है।

**हाथ से लिखा हुआ**

भारतीय संविधान की मूल प्रति हाथ से लिखी हुई है। इसे प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने इटैलिक स्टाइल राइटिंग में लिखा था। यह प्रति भारत के संसद भवन की सेंट्रल लाइब्रेरी में हीलियम गैस से भरे शीशे के बॉक्स में सुरक्षित रखी हुई है।

**2 साल, 11 महीने और 18 दिन में तैयार**

संविधान सभा ने 2 साल, 11 महीने और 18 दिन में कुल 114 दिन बैठक की थी। इस दौरान उन्होंने संविधान का मसौदा तैयार किया और उसमें कई संशोधन किए।

**2000 से ज्यादा संशोधन**

अंतिम रूप मिलने से पहले भारतीय संविधान के पहले ड्राफ्ट में करीब 2000 संशोधन किए गए थे। यह दर्शाता है कि संविधान को बनाने में कितनी मेहनत और विचार-विमर्श किया गया था।

**15 महिलाओं ने किया हस्ताक्षर**

संविधान पर हस्ताक्षर करने वालों में 15 महिलाएं भी शामिल थीं। यह दर्शाता है कि संविधान सभा में महिलाओं की भागीदारी कितनी महत्वपूर्ण थी।

**अंग्रेजी संस्करण में 117,369 शब्द**

भारतीय संविधान के अंग्रेजी संस्करण में कुल 117,369 शब्द हैं। यह दर्शाता है कि संविधान कितना विशाल है।

**संविधान की आत्मा**

संविधान की आत्मा कही जाने वाली प्रस्तावना को अमेरिकी संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में अब तक 124 बार संशोधन हुआ है, लेकिन प्रस्तावना में कभी कोई बदलाव नहीं किया गया है।

**अशोक चक्र बना राष्ट्रीय चिन्ह**

26 जनवरी 1950 को ही अशोक चक्र को बतौर राष्ट्रीय चिन्ह स्वीकार किया था।

**मौलिक अधिकारों का वर्गीकरण**

भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को छह भागों में बांटा गया है- समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक तथा शिक्षा सम्बंधित अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार।

**कई देशों से प्रेरित**

भारतीय संविधान कई देशों से प्रेरित माना जाता है। इन देशों में ब्रिटेन, अमेरिका, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, कनाडा, जापान और रूस शामिल हैं।

# वनप्लस 13R होने वाला है लॉन्च, मिलेगी 12GB रैम, कमाल का है प्रोसेसर

OnePlus 13R फोन जनवरी 2025 में भारत में लॉन्च हो सकता है। फोन को लॉन्च होने में अभी कुछ दिन बचे हैं, इसी बीच माई स्मार्ट प्राइस ने इस डिवाइस को बेंचमार्किंग प्लैटफॉर्म गीकबेंच पर देख लिया है। गीकबेंच लिस्टिंग के अनुसार फोन का मॉडल नंबर CPH2645 है। 91 मोबाइल्स इंडोनेशिया की रिपोर्ट के अनुसार ये फोन FCC में हो गया है।

वनप्लस अपने नए फोन को लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। कंपनी के इस अपकमिंग फोन का नाम OnePlus 13R है। ये फोन जनवरी 2025 में भारत में लॉन्च हो सकता है। फोन को लॉन्च होने में अभी कुछ दिन बचे हैं, इसी बीच माई स्मार्ट प्राइस ने इस डिवाइस को बेंचमार्किंग प्लैटफॉर्म गीकबेंच पर देख लिया है। गीकबेंच लिस्टिंग के अनुसार फोन का मॉडल नंबर CPH2645 है। 91 मोबाइल्स इंडोनेशिया की रिपोर्ट के अनुसार ये फोन FCC में हो गया है।

गीकबेंच लिस्टिंग की मानें तो फोन में कंपनी प्रोसेसर के तौर पर स्नैपड्रैगन 8 जेन 3 ऑफर करने वाली है। ये फोन 12जीबी तक की रैम से लैस होगा। ओएस की बात करें तो, फोन एंड्राइड 15 पर बेस्ड oxygenOS 15 पर काम करेगा। फोन के दूसरे खास स्पेसिफिकेशन्स का खुलासा FCC लिस्टिंग में हुआ है। इसके अनुसार कंपनी का ये फोन 5860mAh की बैटरी से लैस होगा। ये बैटरी 80 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करेगी। कनेक्टिविटी के लिए फोन में आपको वाई-फाई 7, ब्लूटूथ 5.4 और एनएफसी जैसे ऑप्शन देखने को मिल सकते हैं।

पिछली लीक्स के अनुसार वनप्लस 13R स्मार्टफोन चीन में लॉन्च होने वाले वनप्लस Ace5 का रीब्रैंडेड वर्जन हो सकता है। ये फोन अगले कुछ दिनों में चीन में चीन में लॉन्च हो सकता है। वनप्लस एस 5 के फीचर्स की बात करें तो इसमें कंपनी 16जीबी तक की LPDDRx रैम और 512जीबी तक का UFS 4.0 स्टोरेज दे सकती है। प्रोसेसर के तौर पर फोन में कंपनी स्नैपड्रैगन 8 जेन 3 दे सकती है। फोन में आपको BOE का 1.5K रेजॉलूशन वाला OLED डिस्प्ले दिया जा सकता है।

# सर्दियों में ठंडे फर्श को कैसे रखें गर्म, फॉलो करें टिप्स

सर्दियों के दौरान कई लोगों को सर्दी, खांसी, गले में खराश और कंजेशन जैसी सामान्य स्वास्थ्य समस्याओं से परेशान रहते हैं। ठंड में फर्श पर नंगे पैर चलने से सर्दी-खांसी की समस्या उत्पन्न हो जाती है। ऐसे में आप इन टिप्स के जरिए फर्श को गर्म बना सकते है।

सर्दियों के दौरान ठंड बढ़ने से हर किसी पर असर पड़ता है। बदलते मौसम के कारण कई लोगों को सर्दी, खांसी और गले में खराश जैसी स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ता है। वैसे इन बीमारियों का एक आम कारण ठंडा फर्श है, क्योंकि ठंडी सतह पर चलने से बीमारियां अधिक बढ़ सकती है। सर्दियों के महीनों के दौरान अपने घर को गर्म और आरामदायक बनाए रखने के लिए हम आपको कुछ टिप्स बताने जा रहे हैं।

**घर को गर्म रखने के टिप्स**

- जब सर्दियां आती हैं तो फर्श ठंड हो जाते हैं। ऐसे में फर्शों को गर्म रखने के लिए इन आसान तरीकों जरुर अपनाना होगा। आप अपने फर्श को गर्म रखने के लिए कालीन या गलीचों का प्रयोग कर सकते है। आप पुराने कपड़ों के प्रयोग करके घर में बनी चटाई बना सकते है। जो इस मौसम में ठंड को कम करने में भी मदद कर सकता है।

- सर्दियों को दौरान कई लोग पानी से या फिर ठंडे पानी में भिगोए कपड़े से पोंछकर साफ करते हैं। ऐसा करने से बीमारियों का अधिक खतरा बढ़ जाता है। इसके अलावा अपने फर्श को ठंडे पानी के संपर्क में आए बिना कुशलता पूर्वक साफ करने के लिए वैक्यूम क्लीनर का प्रयोग करें।

- वैसे घर में प्रवेश करने वाली ठंडी हवा फर्श को और भी ठंडा बना सकते है। इससे बचने के लिए खासतौर पर सुबह और शाम के समय दरवाजे और खिड़कियां बंद रखें। ठंडी हवा के प्रवेश को सीमित रखने से आपके घर में गर्माहट बनाए रखने में मदद मिलेगी और फर्श पर ठंडा कम होगा।

# बालों की ग्रोथ के लिए बेहद फायदेमंद है मेथी, जानिए कैसे करें इस्तेमाल

बालों के लिए मेथी काफी ज्यादा फायदेमंद मानी जाती है। वहीं आयुर्वेद में भी मेथी काफी ज्यादा कारगर मानी गई है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि मेथी के इस्तेमाल से बालों के विकास में मदद मिलती है। इसमें प्रोटीन, कार्ब्स, फैट, फाइबर, आयरन और मैग्नीशियम पाया जाता है, जो बालों के लिए कई तरह से काम करता है। झड़ते बालों के लिए मेथी का सेवन काफी लाभकारी माना जाता है। शरीर में आयरन की कमी होने पर बाल तेजी से झड़ते हैं। वहीं मेथी का सेवन करने से शरीर में आयरन की मात्रा बढ़ती है और बालों का झड़ना कम होने लगता है। ऐसे में आज इस आर्टिकल के जरिए हम आपको बताने जा रहे हैं कि मेथी का इस्तेमाल बालों के लिए कैसे किया जाता है।

**हेल्दी बालों के लिए मेथी का इस्तेमाल**

**मेथी पानी**

बालों के लिए मेथी पानी का भी अच्छा होता है। मेथी का बीज खोपड़ी में रक्त के प्रवाह को बढ़ाने में मदद करता है। यह बालों को तेजी से बढ़ाने, स्वस्थ और नए विकास को बढ़ावा देने में भी पोषण देते हैं। इसमें एंटीऑक्सीडेंट और एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं। जो स्कैल्प की जलन, डैंड्रफ और मुंहासों को दूर करने में सहायक होती है।

**मेथी सीरम**

इसके साथ ही आप बालों के लिए मेथी का हेयर सीरम भी बना सकती हैं। इसको बालों में लगाने से ग्रोथ बढ़ाने में मदद मिलती है। यह सीरम आपके बालों को सिल्की बनाने के साथ ही इसको अंदर से स्वस्थ बनाता है।

**मेथी का तेल**

बहुत सारे लोग यह सवाल पूछते हैं कि बालों के लिए मेथी का तेल कैसे बनाएं। क्योंकि मेथी का तेल बालों को घना करता है। इसके लिए आप नारियल तेल या सरसों के तेल में मेथी को पका लें। फिर इस तेल को बालों की जड़ों में अप्लाई करें। इसके बायोएक्टिव एंजाइम्स बालों की ग्रोथ को बढ़ाने में सहायक होता है।

# ग्रेटर कैलाश में पदयात्रा के दौरान केजरीवाल पर फेंका गया 'लिक्विड', आरोपी की पिटाई

**दिल्ली के ग्रेटर कैलाश में पदयात्रा के दौरान अरविंद केजरीवाल पर एक शख्स ने लिक्विड फेंकने की कोशिश की। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है कि भाजपा के लोगों ने केजरीवाल पर हमला किया। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है। इससे पहले आप कार्यकर्ताओं ने आरोपी की जमकर पिटाई कर दी। बताया जा रहा है कि धीरे-धीरे आरोपी केजरीवाल के नजदीक आ गया था।**

परिवहन विशेष न्यूज

**नई दिल्ली।** दिल्ली के ग्रेटर कैलाश इलाके में पदयात्रा के दौरान एक शख्स ने दिल्ली के पूर्व सीएम और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल पर लिक्विड फेंकने की कोशिश की। बाद में उस शख्स को उनके सुरक्षा कर्मचारियों ने पकड़ लिया। आम आदमी पार्टी ने कहा कि भाजपा के लोगों ने केजरीवाल पर हमला किया।

आम आदमी पार्टी ने घटना को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। पार्टी ने कहा- दिल्ली में कानून व्यवस्था बरकरार रखने में नाकाम बीजेपी बौखलाई हुई है। कानून व्यवस्था पर सवाल उठाने पर अरविंद केजरीवाल पर बीजेपी ने हमला करवाया। इससे गृह मंत्री अमित शाह की नाकामी जग जाहिर हुई है।

**सौरभ भारद्वाज ने उठाए गृह मंत्री पर सवाल**

अरविंद केजरीवाल पर हुए हमले पर दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा, ₹बीजेपी नेता सभी राज्यों में रैलियां निकालते हैं, उन पर कभी हमला नहीं होता। अरविंद केजरीवाल पर लगातार हमले हो रहे हैं। नांगलोई और छतरपुर में उन पर हमला हुआ। दिल्ली में कानून-व्यवस्था ध्वस्त हो गई है और केंद्र सरकार और गृह मंत्री कुछ नहीं कर रहे हैं।"

# अजमेर दरगाह मामले में वादी विष्णु गुप्ता को मिली जान से मारने की धमकी, सिर कलम करने का आया कॉल

अजमेर दरगाह संकट मोचन महादेव मंदिर मामले में वादी हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता को जान से मारने की धमकी मिली है। धमकी देने वाला कॉलर कनाडा से है और दूसरा आरोपी भारत से है। कॉलर ने बोला तेरा सर कलम कर दिया जाएगा और गर्दन काट दी जाएगी। तूने अजमेर दरगाह का केस फाइल करके बहुत बड़ी गलती कर दी।

**नई दिल्ली।** अजमेर दरगाह संकट मोचन महादेव मंदिर मामले में वादी हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता को जान से मारने की धमकी मिली है। धमकी देने वाला कॉलर कनाडा से है। वहीं भारत से भी कॉल आया। कॉलर ने बोला, ₹तेरा सर कलम कर दिया जाएगा और 'गर्दन काट दी जाएगी। तूने अजमेर दरगाह का केस फाइल करके बहुत बड़ी गलती कर दी।"

धमकी देने वाले की शिकायत थाना बाराखंबा नई दिल्ली में दर्ज कर दी गई है। इन धमकियों पर विष्णु गुप्ता ने कहा, ₹मैं यहां कहना चाहता हूं, हम ऐसे धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। हम कानून के तहत काम कर रहे हैं और कोर्ट जाना हमारा अधिकार है। हम कोर्ट के माध्यम से अपने मंदिरों को वापस लेकर रहेंगे और अजमेर दरगाह संकट मोचन महादेव मंदिर था है और रहेगा।"

**अजमेर शरीफ को लेकर क्यों है विवाद?**

दरअसल, हिंदू सेना ने अजमेर शरीफ दरगाह के नीचे संकट मोचक महादेव मंदिर होने का दावा किया है। इसको लेकर उन्होंने अदालत में एक याचिका भी डाली, जिस पर कोर्ट सुनवाई के लिए राजी हो गया। इसके बाद राजनीतिक विवाद शुरू हो गया। दरअसल, मथुरा, वाराणसी और धार में मस्जिदों और दरगाहों पर इसी तरह के दावे किए गए हैं।

अजमेर की एक सिविल अदालत न इससे जुड़ी याचिका को स्वीकार करते हुए सभी पक्षों को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई के लिए अगली तारीख 20 दिसंबर जारी की है। अदालत में हिंदू सेवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने वकील शशि रंजन कुमार सिंह के माध्यम से 26 सितम्बर को याचिका दायर की गई थी।

**क्या है अजमेर दरगाह का इतिहास**

ईरान (फारस) के एक सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने अजमेर को अपना घर बनाया था और मुगल सम्राट हुमायूं ने उनके सम्मान में एक दरगाह बनवाई थी। अकबर और उनके पोते शाहजहां ने अजमेर दरगाह परिसर के अंदर मस्जिदें बनवाई थीं। अजमेर शरीफ दरगाह की गिनती भारत की सबसे बड़ी पवित्र धार्मिक स्थलों में की जाती है।

# गाजीपुर मुर्गा मछली मंडी के चेयरमैन भाई मेहरबान कुरैशी का मंडी व्यापारियों ने तीन वर्ष पूर्ण होने पर किया भव्य स्वागत

सुषमा रानी

**नई दिल्ली।** मुर्गा मछली मंडी समिति दिल्ली सरकार की एक महत्वपूर्ण संस्था है जिसमें व्यापारियों से सम्बंधित अनेकों समस्याओं के समाधान हेतु दिल्ली के गवर्नर द्वारा इस संस्था का चेयरमैन नियुक्त किया जाता है, जो एक संवैधानिक पद है। जिसका पहला चेयरमैन वर्ष 1992 में नियुक्त किया गया था, उस वक्त से लेकर अब लगभग 14 चेयरमैन अपना कार्यकाल पूरा कर चुके हैं लेकिन अभी वर्तमान में इस मंडी के चेयरमैन पद का कार्यभार हाजी मेहरबान कुरैशी संभाल रहे है। जिनके कार्यकाल के तीन वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में समिति के सदस्यों व अन्य व्यापारियों द्वारा एक सम्मान कार्यक्रम का आयोजित समिति के कांफ्रेंस हॉल में किया गया। इस मौके पर थाना गाज़ीपुर के अध्यक्ष निर्मल कुमार झा, नज़ीर फ़ूडस के चेयरमैन हाजी आफ़ताब कुरैशी, युवा नेता फ़ैसल मेहरबान, फ़ेस ग्रुप के चेयरमेन डॉ० मुश्ताक़ अंसारी, सीनियर जर्नलिस्ट जावेद रहमानी, फ़िक्की के सचिव सलीम अंसारी आदि मुख्य रूप से मौजूद रहे। इस मौक़े पर मंडी के चेयरमैन हाजी मेहरबान कुरैशी द्वारा पिछले तीन वर्ष में मंडी के उत्थान हेतु किए गए विकास कार्यों की विस्तार से चर्चा की गई। उनके महत्वपूर्ण कार्यों की अगर बात करें तो इन्होंने व्यापारियों के लम्बित पड़े लाइसेंस रिन्यू कराए, पानी की समस्या का समाधान बोरबेल लगवाकर किया, पानी निकासी समस्या का भी समाधान ड्रेन सीवर लाईन चालू कराकर किया, व्यापारियों को एटीएम सुविधा मंडी परिसर में ही आरम्भ कराई, बिजली के खम्बों पर पर्याप्त लाईट व्यवस्था चालू की गई, व्यापारियों व आम नागरिकों के लिए पीने के पानी हेतु आर-ओ- प्लांट लगाया गया तथा वातावरण स्वच्छ रहे इसके मद्देनजर वृक्षारोपण भी किया गया। व्यापारियों की सुविधा हेतु कम्पयूटराईज़ एसएमएस व्यवस्था भी आरम्भ की गई। इसके अतिरिक्त मंडी के अंदर गंदे पानी को साफ करने के लिए ईटीपी प्लांट भी लगाया गया। इस अवसर पर भाई मेहरबान कुरैशी ने समिति के सभी सदस्यों, प्रशासनिक अधिकारी व व्यापारियों का आभार व्यक्त करते हुए बताया कि दिल्ली सरकार के मंत्री गोपाल रॉय के प्रयासों से नया बिजली प्लांट लगवाने में हम सफल हुए और केजरीवाल सरकार की बदोलत ही मुर्गा मंडी के व्यापारियों की नई बिल्डिंग मिली, इसके अलावा उन्होंने कहा कि पिछले तीन वर्षों में यहां के व्यापारियों की मूलभूत समस्याओं का जो निवारण किया गया उसके पीछे मंत्री गोपाल राय की खास रूचि रही जिसके लिए हम उनका व आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल व मुख्य मंत्री अतिथि का विशेष आभार व्यक्त करते हैं।

इस अवसर पर चौधरी हाजी निज़ाम कुरैशी, मौ0 सलीम कुरैशी, सुल्तान अहमद, बिलाल अहमद, कमाल खान, कदीर खान, चौधरी समीरूद्दीन, हाजी सलाहुद्दीन, रिज़वान अहमद, रज़िया बेगम, मौ0 जावेद, उमैद कुरैशी आदि गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थिति थे।

# ग्लोबलस्पा फिट एंड फैब अवॉर्ड्स 2024

सुषमा रानी

**नई दिल्ली।** वेलनेस और लाइफस्टाइल में अग्रणी **ग्लोबलस्पा** ने बहुप्रतीक्षित **ग्लोबलस्पा फिट एंड फैब 2024** का आयोजन नई दिल्ली के **द ललित** में किया। यह प्रतिष्ठित इवेंट उन व्यक्तियों का जश्न मनाने के लिए समर्पित है, जो स्वास्थ्य, फिटनेस और पेशेवर उत्कृष्टता को बेहतरीन ढंग से अपनाते हैं।

वेलनेस और हेल्दी लाइफस्टाइल को बढ़ावा देने के अपने ब्रांड सिद्धांत के तहत, ग्लोबलस्पा फिट एंड फैब शो को प्रस्तुत किया गयाः ऑस्ट्रिया टूरिज्म** द्वारा लक्ज़री डेस्टिनेशन पार्टनर के रूप में, द ललित, नई दिल्ली हॉस्पिटैलिटी पार्टनर के रूप में, गैबिटफिटनेस पार्टनर के रूप में, बीएमडब्ल्यू इंफिनिटी कार्स* लाइफस्टाइल पार्टनर के रूप में, जस्ट हर्ब्स** ब्यूटी पार्टनर के रूप में, और सिल्हूट सैलून* हेयर और मेकअप पार्टनर के रूप में।

इस इवेंट में प्रतिष्ठित जजों का एक पैनल शामिल था, जिसमें थेः राजीव मखनी (टेक गुरु), सुनील सेठी*(एफडीसीआई चेयरमैन), डियाने पांडे (सेलिब्रिटी फिटनेस एक्सपर्ट), गौरव गुप्ता* (गैबिट के संस्थापक और सीईओ), निश्छिंत सिंह* (समग्र स्वास्थ्य और वेलनेस कोच), और *आशीष सोनी* (प्रसिद्ध फैशन डिजाइनर)।

इस साल की गेस्ट लिस्ट में विभिन्न क्षेत्रों के प्रमुख नाम शामिल थे, जिनमें शामिल हैंः

**रिद्धिमा कपूर साहनी, नुसरत भरुचा, चित्रांगदा सिंह, अपारशक्ति खुराना, सैयामी खेर, अमान अली बंगश, संग्राम सिंह, डिजाइनर-और-पुत्र जोड़ी निखिल और विक्हान मेहरा, सुवीर सारन, मालिनी अग्रवाल, शिवानी और साहिल मलिक (दा मिलानो), रोहन भार्गव (कैशकरो), फिटनेस आइकन त्रिपत सिंह, उद्यमी अंकुर वारिकू, पर्वतारोही शीतल राज, और कई अन्य।**

इवेंट में गायिका **आस्था गिल** की एक शानदार परफॉर्मेंस भी शामिल थी, जिसने शाम के जोश और उत्साह को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया।

**ग्लोबलस्पा इंडिया और मिडिल ईस्ट की मुख्य संपादक परिनीता सेठी** ने कहा,

₹भारत की एकमात्र वेलनेस लक्ज़री लाइफस्टाइल मैगज़ीन और प्लेटफॉर्म के रूप में, फिट एंड फैब अवॉर्ड्स उन व्यक्तियों का जश्न मनाते हैं, जो समग्र सफलता का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। ये विजेता फिटनेस, हेल्दी लिविंग और प्रोफेशनल एक्सीलेंस के प्रति अपनी प्रतिबद्धता से प्रेरित करते हैं।

उन्होंने आगे कहा, ग्लोबलस्पा फिट एंड फैब के इस 7वें संस्करण में, हम केवल फिटनेस का नहीं, बल्कि इस विचार का जश्न मनाते हैं कि सेल्फ केयर एक ऐसी आवश्यक चीज़ है, जो लगातार विकसित हो रही दुनिया में जीवन का हिस्सा होनी चाहिए।

वर्षों से, इन अवॉर्ड्स ने अनिल कपूर, करण जौहर, शाहिद कपूर, मलाइका अरोड़ा, शिल्पा शेट्टी, कियारा आडवाणी, और ल्यूक कूटिन्हो जैसे प्रसिद्ध व्यक्तित्वों को सम्मानित किया है, जिससे यह स्वास्थ्य और फिटनेस के क्षेत्र में एक प्रतिष्ठित पहचान बन चुका है।

**फिट एंड फैब** स्वास्थ्य और वेलनेस के प्रति प्रतिबद्धता का जश्न है, जो यह दर्शाता है कि संतुलन और फिटनेस व्यस्त करियर के साथ कैसे सह-अस्तित्व में रह सकते हैं। इस मंच ने अपनी स्थापना से ही अनगिनत व्यक्तियों को वेलनेस को सफलता का अभिन्न हिस्सा मानने के लिए प्रेरित किया है।

# दुविधा में आप, हर सीट पर छह दावेदार, किसे बनाएं उम्मीदवार

**दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के लिए टिकट मांगने वालों की बढ़ती संख्या एक बड़ी चुनौती बन गई है। एक-एक सीट पर पार्टी के छह-छह कार्यकर्ता मजबूती से दावेदारी कर रहे हैं। कईयों ने अपने नाम के पोस्टर और होर्डिंग तक लगवा रखे हैं। पार्टी ने अभी तक किसी को भी इंकार नहीं किया है और न ही यह कहा है कि वे तैयारी ना करें।**

**नई दिल्ली।** आम आदमी पार्टी के लिए दिल्ली विधानसभा का चुनाव इस बार अभी तक का सबसे चुनौतीपूर्ण चुनाव तो है ही, मगर इसके साथ ही पार्टी इस बार टिकट मांगने वालों की बढ़ चुकी संख्या से भी जूझ रही है। इस बार चुनाव लड़ने के लिए दावेदारों की संख्या अधिक बढ़ी है।

एक-एक सीट पर पार्टी के छह-छह कार्यकर्ता मजबूती से दावेदारी कर रहे हैं। जिन सीटों पर पार्टी के विधायक हैं उन सीटों पर भी दावेदार तैयार हैं। कईयों ने अपने नाम के पोस्टर और होर्डिंग तक लगवा रखे हैं। यहां महत्वपूर्ण यह भी है कि पार्टी ने किसी को भी इंकार नहीं किया है और न ही यह कहा है कि वे तैयारी ना करें।

**आप ने चुनाव से तीन माह पहले 11 सीटों पर उतारे उम्मीदवार**

आप में जिस तरह से इस बार टिकट के लिए दावेदारी की जा रही है, वह पहले नहीं रही है। राजनीतिक जानकारों की मानें तों इसका कारण यह भी है कि जिस तरह से आप ने चुनाव से तीन माह पहले 11 सीटों पर टिकट की घोषणा कर दी है, उससे कार्यकर्ताओं में माहौल यह बन गया है कि आप जल्द ही अन्य सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर सकती है।

दूसरे तीन विधायकों की टिकट काट देने से वर्तमान विधायकों वाली सीटों पर भी दावेदार खुल कर बढ़ रहे हैं। यहां यह भी हो रहा है कि पार्टी का कोई मजबूत कार्यकर्ता अपने विधायक से किसी बात से नाराज है और उनसे उसकी शिकायत पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से की है तो उसे भी लगने लगा है कि विधायक की टिकट कटना पक्का है।इस तरह ऐसे कार्यकर्ता स्वयं भी दावेदार हो रहे हैं।

**दूसरे दावेदारों की बढ़ी बेचैनी**

एक सीट पर संभावित प्रत्याशी ने प्रचार तक शुरू कर दिया है। जंगपुरा सीट से दो बार से प्रवीण कुमार विधायक हैं, मगर पार्टी की नेता रीना गुप्ता ने टिकट घोषणा से पहले ही अपना प्रचार शुरू कर दिया है, उन्हें इस सीट पर दावेदार जरूर माना जा रहा है। मगर पार्टी ने अभी तक किसी तरह की घोषणा नहीं की है।

मगर लोगों के फोन पर इस सीट पर चुनाव लड़ने के उनके रिकॉर्डेड संदेश पहुंच रहे हैं। जिसमें उनकी आवाज में कहा जा रहा है कि वह इस सीट पर चुनाव लड़ने जा रही हैं, उनका सहयोग चाहिए है।

उनके इस संदेश से इस सीट पर अन्य दावेदारों की बेचैनी बढ़ गई है। वे पार्टी नेतृत्व से उनकी शिकायत कर चुके हैं।

# स्वाद और संस्कृति का संगम सरस फूड फेस्टिवल का किया जाएगा आयोजन

सुषमा रानी

**नई दिल्ली।** स्वाद और संस्कृति का संगम सरस फूड फेस्टिवल का आयोजन एक दिसंबर से सत्रह दिसंबर तक दिल्ली के दिल कहे जाने वाले कनॉट प्लेस के बाबा खड़क सिंह मार्ग पर किया जा रहा है। *केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा आयोजित और राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान (एनआईआरडीपीआर) तथा कुडुंबश्री द्वारा समर्थित* इस फेस्टिवल में राजधानी के लोगों को एक बार फिर भारतीय संस्कृति व खान पान की झलक दिल्ली के हृदय कहे जाने वाले कनॉट प्लेस में दिखाई देगी। सरस फूड फेस्टिवल के तहत दिल्ली और समीपवर्ती राज्यों के लोग *25 राज्यों* की संस्कृति और स्वाद के संगम के संगम से न केवल रूबरू हो सकेंगे बल्कि इन राज्यों के सामाजिक ताने बाने के बारे में भी जान सकेंगे और वहां की प्रसिद्ध व्यंजनों से परिचित हो सकेंगे और उसका स्वाद ले सकेंगे। यह राजधानी का एक लोकप्रिय उत्सव है जिसमें न केवल दिल्ली बल्कि दिल्ली के बाहर के लोग भी विभिन्न राज्यों के व्यंजन चखने और उसे कैसे बनाते हैं यह जानने के लिए आते हैं। फूड फेस्टिवल के दौरान दिल्ली वाले *25 राज्यों के 300 से अधिक उत्कृष्ट व्यंजनों* *का लुत्फ 30 स्टॉलों* पर उठा सकेंगे।

केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा 01 दिसंबर 2024 से 17 दिसंबर 2024 तक नई दिल्ली में बाबा खड़क सिंह मार्ग स्थित हैंडीक्राफ्ट भवन पर सरस फूड फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है। जिसमें देश भर के 25 राज्यों के क़रीब 150 महिला उद्यमी व स्वयं सहायता समूहों की महिलाएं 30 से अधिक स्टॉलों पर 300 से अधिक उत्कृष्ट व्यंजनों का दिल्ली वालों को स्वाद का जायका चखाएंगी साथ ही अपनी कला का प्रदर्शन भी करेंगी।

ग्रामीण विकास मंत्रालय के मुख्य कार्यक्रम राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत गठित देश भर के स्वयं सहायता समूहों की महिलाएं को न केवल ग्रामीण उत्पाद बनाने में कुशलता हासिल है बल्कि विभिन्न राज्यों के परंपरागत पकवान बनाने में उनको दक्षता और महारथ हासिल है। ये महिलाएं और उनके साथ अपने कार्य क्षेत्र में दक्ष लोग यहां अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे।

कनाट प्लेस स्थित बाबा खड़ग सिंह मार्ग पर 25 राज्यों के स्वाद की संस्कृति महकेगी। यहां के व्यंजन और संस्कृति से लोग रूबरू हो सकेंगे। इसमें मुख्य रूप से राजस्थान की कैर सांगरी, गट्टे की सब्ज़ी, बाजरे की रोटी, बंगाल की हिलसा, फ़िश करी, तेलंगाना का चिकन, केरल की मालाबार बिरयानी, बिहार का लिट्टी चोखा, पंजाब का सरसों का साग और मक्के की रोटी सहित अन्य राज्यों के बेहतरीन स्वादिष्ट पकवान उपलब्ध रहेंगे। इसमें हरियाणा, अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, केरल, असम, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और गुजरात सहित अन्य राज्य हिस्सा ले रहे हैं।

यह सरस फूड फेस्टिवल महिला सशक्तिकरण का अनूठा उदाहरण है जो देश की राजधानी का हृदय कहे जाने वाले कनॉट प्लेस में आयोजित हो रहा है। इसका उद्देश्य न केवल देश की खाद्य संस्कृति से लोगों को परिचित कराना है बल्कि अन्य ग्रामीण महिलाओं को प्रेरित करना भी है। मंत्रालय द्वारा यह प्रयास वृहद स्तर पर आयोजित होता है।

सरस फूड फेस्टिवल में आने वालों के लिए किसी तरह का टिकट नहीं है। यह उत्सव सुबह 11 बजे से रात 10 बजे तक चलेगा। इसमें लोग अपने परिवार के साथ आ सकते हैं।

# 32 लोगों ने हजारों लोगों से करोड़ों ठगे, बनाई टूर पैकेज की फर्जी कंपनी; कर्नाटक-पुणे से शिकायत पर हुआ खुलासा

नोएडा में छुट्टियों के टूर पैकेज के नाम पर धोखाधड़ी करने वालों का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने 32 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये लोगों को हॉलिडे टूर पैकेज की बुकिंग कराते थे फिर पैसे लेकर गायब हो जाते। लोगों को कोई जवाब नहीं देते थे। जानिए कैसे ये कंपनी लोगों को ठग रही थी और क्या है पूरा मामला।

**गुरुग्राम।** नोएडा। पुलिस ने शनिवार को सेक्टर-63 थाना क्षेत्र के ए और एच ब्लॉक में कंट्री हॉलिडे ट्रैवल इंडिया लिमिटेड की ओर से टूर पैकेज की सुविधा के नाम पर धोखाधड़ी करने का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने दो कार्यालयों से 15 पुरूष व 17 महिला स्टाफ को गिरफ्तार किया। शातिर दो साल में करीब हजारों लोगों से करोड़ों रुपये की ठगी कर चुके हैं।

अभी कंपनी का निदेशक विशाल समेत सेल्स व एडमिन टीम के आकाश, दीपक, ज्योति, श्रेयस फरार हैं। दैनिक जागरण ने पुणे के पीड़ित दिव्यांग विनय हरि सिंह की शिकायत को प्रमुखता से प्रकाशित किया था।

**84 हजार रुपये का लिया पैकेज**

डीसीपी सेंट्रल नोएडा शक्तिमोहन अवस्थी ने बताया कि बृहस्पतिवार को आम्रपाली इडेन पार्क की अनिता ने कंट्री हॉलिडे ट्रैवल इंडिया लिमिटेड के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। हॉलिडे बुकिंग के लिए ज्योति और श्रीयश चौधरी ने नौ दिन की यात्रा के लिए आईटीसी के होटल बुकिंग के नाम पर 84 हजार रुपये का पैकेज दिया था।

**कॉलिंग और टेक सेटअफ दोनों थे अलग**

बुकिंग कंफर्म नहीं होने पर पैसे भी वापस नहीं लौटाए थे। जांच के दौरान पांच ऑनलाइन व पुणे से एक अन्य लिखित शिकायत मिली। टीम को ए ब्लॉक में कंपनी का कॉलिंग सेटअफ व एच ब्लॉक में टेक सेटअप (Tech Set up) मिला। मौके से 32 स्टाफ को पकड़ा गया। उनसे चार लैपटॉप, तीन मॉनिटर, चार कीबोर्ड, तीन सीपीयू, तीन माउस, दो राउटर, तीन आईपैड, एक मोबाइल व अन्य सामान बरामद हुआ।

**पैकेज के नाम पैसे लेकर नहीं देते सेवा**

पूछताछ में बताया कि डार्कवेब से डाटा खरीदकर गैजेट्स व वाहन खरीदने वाले लोगों से संपर्क करते। आईटीसी, टेक महिंद्रा, इंडियन होटल जैसी नामी कंपनी से टाईअप होने का दावा करते। देश के अंदर ही टूर एंड ट्रैवल के पैकेज के नाम पर 75 से दो-तीन लाख रुपये तक मैंबरशिप बेचते, लेकिन लोगों को सेवाएं उपलब्ध नहीं कराते थे।

शिकायत मिलने पर लोगों को टरकाते थे और अंत में नंबर को ब्लाक कर देते। पूर्व में मगाडी रोड बैंगलुरू पुलिस की ओर से कंपनी के खाते को फ्रीज कराया जा चुका है। अब सेक्टर 63 थाना पुलिस ने कंपनी के दो खातों को फ्रीज किया है।

**यूपी, बिहार, हरियाणा, दिल्ली का स्टाफ**

गिरफ्तार पुरूष आरोपियों की पहचान दिल्ली कृष्णा नगर के रवनीत सिंह, बिहार मुजफ्फरपुर के प्रत्युश राज उर्फ प्रदोस, गाजियाबाद इंदिरापुरम के सुभांकर, गाजियाबाद विजयनगर के मनोज कुमार, दिल्ली सीमापुरी के दीपक, दिल्ली बदरपुर साइन नगर का योगेश कुमार, नोएडा बहलोलपुर का हर्षित, दिल्ली ओखला का आदिल, गाजियाबाद राहुल विहार का कौशल कुमार, गाजियाबाद न्यू पंचवटी कालोनी का पुष्पेंद्र, दिल्ली कालका जी का सिद्धार्थ, प्रयागराज बामपुर का रंजीत, दिल्ली लक्ष्मी नगर का मनोज कुमार, नोएडा बिसरख का अजय किशोर पाठक, गाजियाबाद सिहानीगेट का अभिषेक के रूप में हुई जबिक महिला आरोपितों की पहचान नोएडा सेक्टर-75 की अंकिता, गाजियाबाद विजयनगर की निकिता, गाजियाबाद खोड़ा की राधा वर्मा, दिल्ली जवालपुरी की अंजलि, दिल्ली करोलबाग की निशा, दिल्ली की साजिमा, गाजियाबाद की गुंजन मौर्या, गाजियाबाद खोड़ा कालोनी की स्वेता, बुलंदशहर यमुनापुरम की भावना, नोएडा सेक्टर 53 की महक मनचंदा, हरियाणा कुरुक्षेत्र की नीलिका, गाजियाबाद बहरामपुर की विनिता सिंह, बुलंदशहर की प्राची, नोएडा बरौला की हिमांशी रावत, गाजियाबाद खोड़ा की नीलम, आकांक्षा व दिल्ली मुबारकपुर की कंचन के रूप में हुई।

## साइबर ठगों को खाता बेचने के मामले में पुलिस का एक्शन, इंडसइंड बैंक का असिस्टेंट मैनेजर समेत तीन गिरफ्तार

**गुरुग्राम।** साइबर ठगों को बैंक खाता बेचने के मामले गुरुग्राम साइबर पुलिस ने इंडसइंड के असिस्टेंट मैनेजर हरविंद्र सिंह समेत तीन आरोपितों को गिरफ्तार किया है। हरिवंद्र दिल्ली के लाजपत नगर स्थित शाखा में काम करता था।

इसे बुधवार को बैंक से गुरुग्राम लाया गया और पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। इसके अलावा दो अन्य आरोपितों की गिरफ्तारी गाजियाबाद से दो दिन पहले की गई थी। इनसे पूछताछ में बैंक कर्मचारी की संलिप्तता सामने आई।

**साइबर थाना पुलिस में मामला दर्ज**

एसीपी साइबर क्राइम प्रियांशु दीवान ने बताया कि 27 जुलाई को एक व्यक्ति ने साइबर थाना ईस्ट में शेयर बाजार में निवेश के नाम पर उसके साथ 35 लाख रुपये की धोखाधड़ी होने की शिकायत दर्ज कराई थी।

यह राशि कई खातों में भेजी गई थी। मामले की जांच के दौरान साइबर पुलिस गाजियाबाद के विक्रम शाही नाम के युवक के पास पहुंची। इसके नाम से खोले गए खाते में भी राशि गई थी।

**साइबर पुलिस ने आरोपी को पकड़ा**

इससे पूछताछ में पता चला कि गाजियाबाद के रहने वाले इसके जानकार योगेंद्र भाटी ने इसके नाम से इंडसइंड बैंक में खाता खुलवाया था। यह करंट खाता फर्जी कैफे व रेस्टोरेंट के नाम पर खोला गया था। योगेंद्र भाटी व विक्रम को 25 नवंबर को पुलिस ने पकड़ा था। इनसे बैंक कर्मचारी हरविंद्र की संलिप्तता की जानकारी मिली। इसके बाद बुधवार को साइबर पुलिस ने इसे भी पकड़ लिया।

हरविंद्र मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बिजनौर के शाहपुर गांव का रहने वाला है और दिल्ली के खानपुर गांव में रहता है। पूछताछ में पता चला कि हरविंद्र 2022 से इंडसइंड बैंक की लाजपत नगर शाखा में असिस्टेंट मैनेजर के रूप में काम कर रहा था। इसने फर्जी दस्तावेजों पर ही खाता खोल दिया। इसके बदले इसे 30 हजार रुपये मिले थे। यह भी पता चला कि योगेंद्र भाटी ने ही इस खाते को आगे साइबर ठगों को बेचा था।

**अलग-अलग ठगी के मामलों में कुल 22 बैंक कर्मचारियों गिरफ्तार**

इसके बदले योगेंद्र व विक्रम को खाते में आने वाली राशि का डेढ़ प्रतिशत मिलता था। बैंक कर्मचारी को दो दिन के रिमांड पर लेकर पूछताछ की जाएगी। उसने अब तक कितने खाते खोले, इसके बारे में भी जानकारी हासिल की जाएगी। साइबर पुलिस ने अब तक अलग-अलग ठगी के मामलों में कुल 22 बैंक कर्मचारियों को गिरफ्तार किया है।

# इस तारीख से अगले दो महीने तक यमुना एक्सप्रेस-वे पर गाड़ी की रफ्तार होगी धीमी

**ग्रेटर नोएडा।** सर्दियों में कोहरे के कारण यमुना एक्सप्रेसवे पर दुर्घटनाओं को रोकने के लिए अधिकतम गति सीमा कम की जाएगी। यमुना प्राधिकरण इसका पत्र जल्द जेपी इन्फ्राटेक को भेजेगा। जिससे की एक्सप्रेसवे पर गति सीमा कम करने के लिए जरूरी इंतजाम 15 दिसंबर से पहले पूर कर लिए जाएं।

यमुना एक्सप्रेसवे पर दुर्घटनाएं लगातार हो रही हैं। सर्दियों में दृश्यता कम होने के कारण दुर्घटनाओं की आशंका और बढ़ जाती है। इसलिए दो माह के लिए एक्सप्रेसवे पर अधिकतम गति सीमा को कम कर दिया जाता है।

**भारी वाहनों के लिए अधिकतम गति सीमा होगी 60 किमी प्रति घंटा**

एक्सप्रेसवे पर हल्के वाहनों के लिए अधिकतम गति सीमा 100 किमी प्रति घंटा और भारी वाहनों के लिए 80 किमी प्रति घंटा है। 15 दिसंबर से हल्के वाहनों के लिए अधिकतम गति सीमा 80 किमी प्रति घंटा और भारी वाहनों के लिए अधिकतम गति सीमा 60 किमी प्रति घंटा हो जाएगी।

यह गति सीमा 15 फरवरी तक लागू रहेगी। इसके आधार पर ही तेज रफ्तार वाहनों पर चालान की कार्रवाई होगी। हादसों को रोकने के लिए इस तरह का आदेश लागू हुआ है। प्राधिकरण अधिकारियों का कहना है कि यमुना एक्सप्रेसवे पर सर्दियों में गति सीमा कम करने के लिए संचालक कंपनी जेपी इन्फ्राटेक को जल्द पत्र जारी किया जाएगा।

**प्राधिकरण से पत्र मिलने के बाद गति सीमा कम करने पर होगा काम**

चालकों को किया जा रहा जागरूक गति सीमा कम होने की जानकारी वाले बोर्ड, साइनेज व पब्लिक एड्रेस सिस्टम के माध्यम से वाहन चालकों को जानकारी देने के इंतजाम कराए जाएंगे। यमुना एक्सप्रेसवे पर जेवर टोल प्लाजा प्रबंधक जेके शर्मा का कहना है कि हर वर्ष एक्सप्रेसवे पर गति सीमा को कम किया जाता है।

प्राधिकरण से पत्र मिलने के बाद गति सीमा कम करने को जरूरी प्रबंध होंगे। गति सीमा में वाहन चलाने को एक्सप्रेसवे पर चालकों को पैंफ्लेट वितरण, पब्लिक एड्रेस सिस्टम के जरिये जागरुक किया जा रहा है।

वहीं पर यमुना प्राधिकरण (Yamuna Authority) की एक मुश्त समाधान योजना जिसे ओटीएस योजना भी कहते हैं। वह आज समाप्त खत्म हो रही है। इसलिए जिस भी आवेदकों को योजना में आवेदन करना है वो शनिवार तक कर लें। बता दें इसको लाने का उद्देश्य बकायेदारों को चक्रवृद्धि ब्याज से राहत देना था। यमुना प्राधिकरण की 82 वीं बोर्ड बैठक में आठ हजार बकायेदारों के लिए इसे लाया गया था।

# FIR के खिलाफ थाने में गिरफ्तारी देंगे अधिवक्ता, लाठीचार्ज के विरोध में एकजुट हुए एडवोकेट

गाजियाबाद में वकीलों पर लाठीचार्ज के विरोध में अधिवक्ता एकजुट हुए हैं। सोमवार को वकील मानव श्रृंखला बनाकर कविनगर थाने जाकर गिरफ्तारी देंगे। जिन वकीलों पर मुकदमा दर्ज किया गया है वे भी गिरफ्तारी देंगे। बार एसोसिएशन ने एक अधिवक्ता को कार्य करता पाए जाने पर सदस्यता निरस्त करते हुए नोटिस जारी किया है। शुक्रवार को थाने में 44 नामजद और करीब 80 अज्ञात अधिवक्ताओं पर केस दर्ज किया गया।

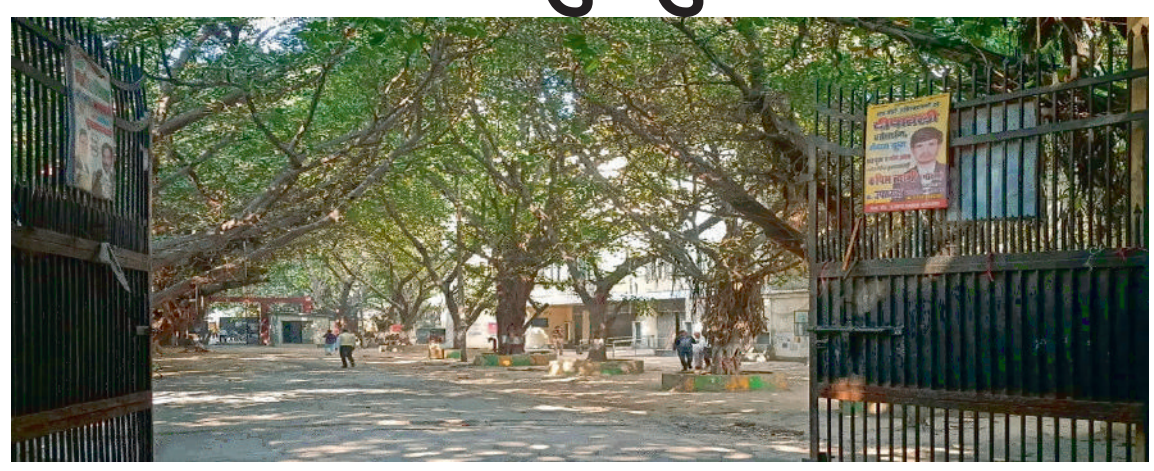

**गाजियाबाद।** जिला जज कोर्ट में 29 अक्टूबर को वकीलों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में अधिवक्ताओं ने शनिवार को हापुड़ चुंगी चौराहे पर मानव श्रृंखला बनाई। वकीलों पर शुक्रवार को दर्ज हुए मुकदमे के विरोध में तय किया गया है कि सोमवार को अधिवक्ता मानव श्रृंखला बनाकर कविनगर थाने जाकर गिरफ्तारी देंगे। जिन वकीलों पर मुकदमा दर्ज किया गया है वह भी गिरफ्तारी देंगे साथ ही अन्य अधिवक्ता भी थाने पहुंचकर पुलिस को गिरफ्तारी देंगे।

बार एसोसिएशन ने एक अधिवक्ता को कार्य करता पाए जाने पर सदस्यता निरस्त करते हुए नोटिस जारी कर दो दिसंबर को जवाब मांगा है।

**वकीलों पर किए जा रहे फर्जी मुकदमे**

बार एसोसिएशन सचिव अमित नेहरा के अनुसार, वकीलों पर आंदोलन के दौरान फर्जी मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। शुक्रवार को ही कविनगर थाने में 44 नामजद और करीब 80 अज्ञात अधिवक्ताओं पर केस दर्ज किया गया है। इसका बार एसोसिएशन विरोध करती है।

**FIR के विरोध में देंगे गिरफ्तारी**

शनिवार को आंदोलन संघर्ष समिति की बैठक में तय किया गया है कि एफआईआर के विरोध में वकील सोमवार को गिरफ्तारी देंगे। सभी अधिवक्ता सोमवार को मानव श्रृंखला बनाकर कविनगर थाने जाएंगे। वकीलों से कहा गया है कि सभी अपने आधार या अन्य पहचान पत्र साथ लेकर जाएंगे। अधिवक्ता पुलिस को गिरफ्तारी देंगे।

**नहीं करेंगे कामकाज**

कचहरी में सोमवार को चैंबर नंबर 251 से 500 तक चैंबर के अधिवक्ता धरना स्थल पर बैठेंगे। इनमें से 11 वरिष्ठ अधिवक्ता क्रमिक अनशन पर बैठेंगे। सोमवार को भी कचहरी में अधिवक्ता कामकाज नहीं करेंगे।

**काम करता पाए जाने पर वकील की सदस्यता निरस्त की**

बार एसोसिएशन ने विधि विरुद्ध कार्यकलाप करने का आरोप लगाते हुए एक अधिवक्ता की सदस्यता निरस्त कर दी है। साथ ही उसे नोटिस जारी कर सदस्यता पांच वर्ष के लिए रद्द करने और चैंबर का आवंटन भी निरस्त करने की चेतावनी देते हुए जवाब मांगा है। जारी नोटिस का जवाब दो दिसंबर तक दिए जाने के लिए निर्देशित किया है।

बार सचिव अमित नेहरा के मुताबिक चंद्रकांत शर्मा अधिवक्ता के रूप में गाजियाबाद कचहरी में कार्य करते हैं। उनका चैंबर संख्या 773 है। शनिवार को हड़ताल के बावजूद चंद्रकांत शर्मा कार्य करते हुए पाए गए। उन्होंने बार एसोसिएशन के प्रस्ताव का उल्लंघन किया है। इस वजह से बार एसोसिएशन की छवि धूमिल हुई है।

**कोर्ट के मुख्य प्रवेश के गेट खुले**

शनिवार को कचहरी में मुख्य प्रवेश के गेट खुले रहे। कचहरी पुलिस चौकी के पास पुलिस बल तैनात रहा। सूत्रों के मुताबिक न्यायालय आने वाले वादकारियों को गेट पर न रोका जाए इसके लिए कोर्ट जाने वाले गेट खोले गए हैं। बार एसोसिएशन द्वारा हड़ताल स्थगित किए जाने का विरोध कर रहे अधिवक्ताओं ने लगातार तीन दिन मुख्य द्वार बंद कर दिए थे।

न्यायालय परिसर में शुक्रवार को आने से वादकारियों को रोकने और न्यायिक कार्य में बाधा डालने के मामले में अदालत के नाजिर ने वकीलों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। इसके बाद शनिवार को न्यायालय की सभी द्वार खोल दिए गए हैं।

7151 मामले शनिवार को कोर्ट में सुनवाई के लिए लगे हुए थे।

6536 केसों का निस्तारण कोर्ट ने अक्टूबर में किया था।

1,91,210 केस एक वर्ष से ज्यादा समय से कोर्ट में लंबित हैं।

# जीत और गठबंधन की मृगमरीचिका में आखिर कबतक भटकेगी कांग्रेस?

कांग्रेस एक पुरानी राजनीतिक पार्टी है, जिसका देशव्यापी जनाधार है। लेकिन वह 'जीत' और 'गठबंधन' की मृगमरीचिका में आखिर कबतक भटकेगी, यह एक यक्ष प्रश्न है? आखिर कमजोर 'सियासी बैशाखियों' के सहारे उसकी जीत कितना मुकम्मल कहलाएगी और स्थायी बन पाएगी, यह उससे भी ज्यादा विचारणीय पहलू है! वैसे भी जब कांग्रेस विभिन्न महत्वपूर्ण राज्यों में क्षेत्रीय दलों की वैशाखी ढूंढ़ती है या फिर मुद्दों के बियाबान में भटकती और फिर स्टैंड बदलती नजर आती है तो मुझे इसके रणनीतिकारों पर तरस आती है।

ऐसा इसलिए कि मैंने भू-जमींदारी देखी है, जहां पर लोग अपनी जमीनें ठेके या बंटाईदारी पर देकर अनाज और पैसे दोनों लेते हैं। ठीक उसी तरह से आज कांग्रेस के रसूखदार और धन्नासेठ नेता पार्टी संगठन में पद और चुनावी टिकट देने के वास्ते 'वोट' और 'पैसा' दोनों लेते/लिवाते हैं, यह जानते हुए भी कि सामने वाला न तो उनका जनाधार बढ़ा पाएगा और न ही चुनाव जीत/जीतवा पाएगा। ऐसा वो सिर्फ इसलिए करते हैं कि सामने वाला अमीर है, वफादार है, पिछलग्गू भर है या फिर निहित समीकरण वश किसी ने उसकी सिफारिश की है। बेशक कुछ अपवाद भी हो सकते हैं, लेकिन वही जिनके नेहरू-गांधी परिवार से ठीकठाक सम्बन्ध हैं।

अब बात पते की करते हैं। जैसे एक शातिर बंटाईदार अपने भूस्वामी की भूमि पर भी कब्जा कर लेता है और इसमें जब वह असफल होता है तो जमीन मालिक से कम कीमत में उसकी रजिस्ट्री करवाना चाहता है। अनुभवहीन भूस्वामियों को ऐसा करते हुए भी देखा सुना है। ठीक इसी प्रकार लालू प्रसाद और स्व. मुलायम सिंह यादव जैसे नवसियासी बटाईदारों ने कांग्रेस के साथ किया और आज क्षेत्रीय सियासी जमींदार बन बैठे हैं। ऐसा इसलिए सम्भव हो सका, क्योंकि निहित स्वार्थवश पीवी नरसिम्हाराव यही चाहते थे! उनके तिकड़म को सोनिया गांधी नहीं समझ सकीं!

वहीं, आज जब राहुल-प्रियंका गांधी की कांग्रेस की रीति नीति देखता हूँ तो इनकी राजनीतिक जमींदारी के हश्र को महसूस भी करता हूँ। कांग्रेस माने या न माने, लेकिन समाजवादी, वामपंथी और राष्ट्रवादी सियासी जमींदारों ने उसकी राजनीतिक जमींदारी को क्षत-विक्षत करने में अहम भूमिका निभाई है और हैरत की बात यह है कि वह समझ नहीं पाई और नादान बनी रही। जबकि इसके खिलाफ ठोस और जमीनी रणनीति बनानी चाहिए। जैसे कि उसके बाद जन्मी भाजपा ने किया है।

माना कि सत्ता प्राप्ति के लोभ में क्षेत्रीय दलों से गठबंधन यानी यूपीए/महागठबंधन की सोच तो सही है, लेकिन इनके इशारे पर कांग्रेस संगठन को हांकना कतई सही नहीं है। कांग्रेस इससे इंकार कर सकती है, लेकिन वह आज इसी की पूरी सियासी कीमत अदा कर रही है। आज वह सत्ता में नहीं है, फिर भी उन्हीं लोगों से सहारा ढूंढ रही है, जो उसकी सियासी पतन के लिए कसूरवार हैं। चूंकि मैंने एआईसीसी/बीजेपी/तीसरे मोर्चे को कवर किया है, इसलिए दावे के साथ कह सकता हूँ कि कांग्रेस के अंग्रेजी भाषी दलाल नेताओं ने उसके जमीनी नेताओं को भाजपा या क्षेत्रीय दलों में जाने के लिए अभिशप्त कर दिया।

चूंकि कांग्रेस के जमीनी नेताओं के पास रणनीति और जनाधार दोनों है, इसलिए वो अपने व्यक्तिवादी मिशन में सफल रहे, लेकिन कांग्रेस दिन ब दिन डूबती चली गई। राजनीतिक परिस्थिति वश कभी दो डग आगे तो चार कदम पीछे चलने को अभिशप्त हो गई। इस बात में कोई दो राय नहीं कि किसी भी स्थापित दल को चलाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और क्षेत्रीय लायजनरों की जरूरत पड़ती है, लेकिन इनके निहित स्वार्थों के ऊपर यदि ब्लॉक, जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर जनाधार रखने वाले नेताओं की उपेक्षा की जाएगी तो फिर वोट कहाँ से आएगा, यह सोचने की फुर्सत सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के पास नहीं होगी।

अतीत पर नजर डालें तो एक जमाना था जब गांव-गांव में कांग्रेस के मजबूत शुभचिंतक थे, लेकिन पार्टी की अव्यवहारिक रीति-नीति के चलते वह इससे दूर होते चले गए। दो टूक कहें तो भाजपा में या क्षेत्रीय दलों में शिफ्ट हो गए। ऐसे में आज कांग्रेस के पास सिर्फ उन 'धनपशुओं' की टोली बची है, जिनको दूसरी राजनीतिक पार्टियां कभी तवज्जो नहीं देतीं। इनका काम कांग्रेस की सत्ता और संगठन के बड़े नेताओं के शाही खर्चों का इंतजाम करना भर है और इसलिए इनके समर्थक ब्लॉक, जिला, राज्य व राष्ट्रीय संगठनों पर हावी हैं।

चूंकि इनका कोई जनाधार नहीं है और ये जनाधार वाले कार्यकर्ताओं को तवज्जो नहीं देते, इसलिए कांग्रेस खत्म होती चली गई। वहीं, जब से क्षेत्रीय कांग्रेस के नेता अस्तित्व रक्षा के लिए बिहार में राजद प्रमुख लालू प्रसाद व तेजस्वी यादव तथा उत्तरप्रदेश में सपा प्रमुख स्व. मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव जैसे मजबूत नेताओं के इशारे पर काम करने लगे, तब से पार्टी संगठन की स्थिति और अधिक दयनीय हो गई।

आलम यह है कि कांग्रेस जैसी राजनीतिक पार्टी, जिसे देश की आजादी का श्रेय प्राप्त है, जब जनजीवन व राष्ट्रीय हितों से इतर प्रमुख जातीय, सांप्रदायिक और क्षेत्रीय समीकरणों पर खेलने लगी, तो उसकी जोड़-तोड़ से सत्ता तो बदलती रही, परंतु जनाधार छीजता चला गया। क्योंकि उसके प्रति निष्ठावान रहे प्रतिभाशाली पेशेवर, कारोबारी, प्रशासक और समाजसेवी आदि उससे दूर होते चले गए। चूंकि पहले क्षेत्रीय दलों और उसके बाद भाजपा ने उन्हें तवज्जो दी, इसलिए वो सब इनके साथ जुड़ गए, जिससे इन्हें अप्रत्याशित मजबूती मिली और कांग्रेस को कमजोरी मुबारक हुई।

अब जब कांग्रेस की टू कॉपी भाजपा बनती जा रही है तो भी कांग्रेस के थिंक टैंक को असली मुद्दे समझ में नहीं आ रहे हैं। शायद उसकी इसी मनोवृत्ति पर चोट करते हुए पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा है कि कांग्रेस को पुराने ढर्रे की राजनीति बंद करनी होगी और नए ढर्रे बनाने होंगे। अन्यथा सियासी सफलता मुश्किल है। लिहाजा कांग्रेस की इसी कमजोरी को मजबूती में बदलने का आह्वान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने किया है।

हाल ही में हरियाणा और महाराष्ट्र में पार्टी और गठबंधन की हुई करारी हार के बाद हुई पहली कांग्रेस वर्किंग कमिटि की बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने दो टूक कहा कि अब पार्टी में जवाबदेही तय करने का वक्त आ गया है। क्योंकि इन दोनों ही राज्यों में महज चंद महीने पहले पार्टी का प्रदर्शन काफी संतोषजनक रहा था। लेकिन अब जो नई दुर्गति सामने आई है, वह हमें नए सिरे से सोचने पर मजबूर करती है।

बता दें कि 29 नवंबर 2024 शुक्रवार को हुई कांग्रेस के सर्वोच्च नीति निर्धारक इकाई की इस समीक्षा बैठक में खरगे के अलावा तमाम सीनियर नेता, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस की नवनिर्वाचित सांसद प्रियंका गांधी भी मौजूद थी। हालांकि बैठक खत्म होने से पहले ही राहुल और प्रियंका निकल गए। इसी मीटिंग में मल्लिकार्जुन खरगे ने पार्टी के नेताओं के सामने जहां एक ओर इस निराशाजनक प्रदर्शन के लिए तमाम वजहों को गिनाया, वही उन्होंने ईवीएम का मुद्दा भी उठाया।

खरगे का दो टूक कहना है कि पार्टी में अनुशासन की कमी और पुराने ढर्रे की राजनीति के जरिए जीत नहीं मिल सकती। क्योंकि कांग्रेस के भीतर आपसी गुटबाजी एक स्थायी भाव बन चुकी है। उन्होंने इस ओर इशारा करते हुए कहा कि आपसी एकता की कमी और एक-दूसरे के खिलाफ बयानबाजी हमें काफी नुकसान पहुंचाती है। जब तक हम एक हो कर चुनाव नहीं लड़ेंगे, आपस में एक-दूसरे के खिलाफ बयानबाजी बंद नहीं करेंगे, तब तक अपने विरोधियों को राजनीतिक शिकस्त नहीं दे पाएंगे। इसलिए हमें हर हाल में एकजुट रहना होगा।

वहीं, उन्होंने पार्टी में अनुशासन पर जोर देते हुए संकेत दिया कि पार्टी के लोग अपने स्तर पर अनुशासन में बंधें। वैसे तो पार्टी के पास अनुशासन का हथियार है, लेकिन हम नहीं चाहते कि अपने साथियों को किसी बंधन में डाले। वहीं, खरगे ने कांग्रेस की एक और बड़ी कमी की ओर इशारा करते हुए कहा कि पार्टी अपने पक्ष के माहौल को नहीं भुना पाती। उनका कहना था कि चुनावों में माहौल हमारे पक्ष में था। लेकिन केवल माहौल पक्ष में होना भर ही जीत की गारंटी नहीं होती। इसलिए अब पार्टी में जवाबदेही तय करने का वक्त आ गया है। क्योंकि पार्टी में अनुशासन की कमी है। पार्टी के भीतर आपसी गुटबाजी एक स्थायी भाव बन चुकी है।

सच कहूं तो लोकसभा चुनाव के बाद दो राज्यों में पार्टी की हुई करारी हार के बाद शुक्रवार को सीडब्ल्यूसी मीटिंग में खरगे द्वारा पार्टी की हार की वजहों का जिक्र कोई पहला मौका नहीं था, जब पार्टी ने अपनी कमियों की ओर इंगित किया हो। यह कड़वी सच्चाई है कि कांग्रेस समस्या जानती है, उसका निदान और उपचार भी जानती है, लेकिन इसके लिए जो इच्छा शक्ति की जरूरत होती है, वह पार्टी नेतृत्व में नजर नहीं आती। यही वजह है कि 2014 के आम चुनाव के बाद असेंबली चुनावों में पार्टी की हो रही लगातार हार के बाद 2016 में कांग्रेस के तत्कालीन महासचिव दिग्विजय सिंह ने पार्टी में मेजर सर्जरी की जरूरत बताई थी। लेकिन हुआ कुछ नहीं। उल्टे जी-23 में से ज्यादातर को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया।

इसलिए अब यह देखना दिलचस्प होगा कि खरगे द्वारा पार्टी की कमियों की ओर किया गया यह इशारा क्या वाकई पार्टी और नेताओं के भीतर कोई बदलाव लाएगा? क्या पार्टी अनुशासन की ब्लेड से मेजर सर्जरी कर पाएगी या फिर यह भी बस एक महज खानापूर्ति बन कर रह जाएगा? क्योंकि खरगे का यह सुझाव सही है कि हमें माहौल को नतीजों में बदलना सीखना होगा। उन्होंने जीत के लिए भरपूर मेहनत के साथ-साथ समयबद्ध तरीके से रणनीति बनाने और संगठन की मजबूती पर जो जोर दिया है, वह भी पते की बात है। उनका सुदीर्घ अनुभव इसमें झलकता है।उन्होंने सटीक आईना दिखाया है कि सिर्फ माहौल पक्ष में होना भर ही जीत की गारंटी नहीं होती। क्योंकि भाजपा इसे अपने पक्ष में करना जानती है। हरियाणा से लेकर महाराष्ट्र तक उसने यही किया है।

खरगे का कहना भी सही है कि हमें अपने संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करना होगा। हमें मतदाता सूची बनाने से लेकर वोट की गिनती तक रात-दिन सजग, सचेत और सावधान रहना होगा। हमारी तैयारी शुरू से लेकर मतगणना तक ऐसी होनी चाहिए कि हमारे कार्यकर्ता और सिस्टम मुस्तैदी से काम करें। वहीं उन्होंने राज्यों को भी अपना संगठन मजबूत करने पर जोर देते हुए कहा कि राष्ट्रीय मुद्दों और राष्ट्रीय नेताओं के सहारे राज्यों का चुनाव आप कब तक लड़ेंगे? उन्होंने प्रदेश संगठनों से कहा कि हाल के चुनावी नतीजों का संकेत यह भी है कि हमें राज्यों में अपनी चुनाव की तैयारी कम से कम एक साल पहले शुरू कर देनी चाहिए। उन्होंने यह कहते हुए राजनीतिक दूरदर्शिता दिखाई है कि हमारी टीम समय से पहले मैदान में मौजूद रहनी चाहिए। जो कि अपने प्रतिद्वंद्वी की तैयारियों पर नजर रखने में सक्षम हो।

– :सौजन्य :–

ईवी ड्राइव द फ्यूचर

EV

Drive the Future

# जनवरी 2025 में सचिवालय कर्मचारियों के लिए इलेक्ट्रिक वाहन प्रदर्शनी का आयोजन करेगा बेसकॉम

परिवहन विशेष न्यूज

इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने को प्रोत्साहित करने के लिए बैंगलोर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी लिमिटेड (बेसकॉम) ने शुक्रवार, 29 नवंबर को घोषणा की कि जनवरी 2025 में सचिवालय कर्मचारियों के लिए एक विशेष ईवी मेला आयोजित किया जाएगा।

बेसकॉम कार्यालय में एक बैठक के दौरान प्रबंध निदेशक महंतेश बिलगी ने कहा, ₹यह एक्सपो मुख्य सचिव शालिनी रजनीश के निर्देश पर आयोजित किया जा रहा है और ऊर्जा मंत्री केजे जॉर्ज और ऊर्जा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव गौरव गुप्ता की देखरेख में आयोजित किया जाएगा।₹ उनके अनुसार इस कार्यक्रम का उद्देश्य उपस्थित लोगों को पर्यावरण के अनुकूल ईवी के लाभों के बारे में शिक्षित करना और दोपहिया ईवी को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना है।

बिलगी ने कहा, "मेले के दौरान सरकारी कर्मचारियों, खासकर सचिवालय में कार्यरत लोगों को डीलर छूट भी दी जाएगी। प्रदर्शनी स्थल पर वाहनों के व्यावहारिक प्रदर्शन के अवसर भी होंगे।"

उन्होंने कहा कि सचिवालय कर्मचारियों को ईवी वाहन खरीदने के लिए बिना डाउन पेमेंट और कम ब्याज दर वाले ऋण का लाभ भी मिलेगा। प्रबंध निदेशक ने कहा, "ईवी कंपनियां भाग लेने के लिए उत्सुक हैं और प्रदर्शनी के बाद भी बिक्री जारी रहेगी।"

बिलगी ने कहा कि राज्य में विशेष रूप से बेंगलुरु में सबसे अधिक इलेक्ट्रिक वाहन का उपयोग होता है। उन्होंने कहा कि ऊर्जा विभाग ने इसके समर्थन के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा प्रदान किया है।

बिलगी ने कहा, "ईवी उपयोग को बढ़ावा देने में बेसकॉम के प्रयासों को 'चार्ज इंडिया 2024 एक्सीलेंस' पुरस्कार से मान्यता मिली है। यह पुरस्कार उत्कृष्ट चार्जिंग सुविधाएं स्थापित करने की हमारी प्रतिबद्धता का प्रमाण है। कर्नाटक में देश में सबसे अधिक सार्वजनिक इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन हैं, जिनकी कुल संख्या 5,765 है, जिनमें से 4,462 बेंगलुरु शहरी जिले में स्थित हैं।"

# भारत की नई नीति से मौजूदा कारखानों को भी मिलेगा बड़ा लाभ

परिवहन विशेष न्यूज

भारत सरकार ईवी विनिर्माण को प्रोत्साहित करने वाली नीति का विस्तार करने की योजना बना रही है। अब यह प्रोत्साहन उन ऑटोमोबाइल निर्माताओं को भी मिलेगा जो मौजूदा कारखानों में ईवी मॉडल बनाएंगे। पहले यह लाभ केवल नए कारखाने लगाने वालों को ही मिलता था।

सूत्रों के अनुसार यह नीति अभी अपने अंतिम रूप में है और शुरू में इसे अमेरिकी वाहन निर्माता टेस्ला को भारत में उत्पादन को स्थानीय बनाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए तैयार किया गया था, लेकिन टेले लिया।

टोयोटा और हुंडई जैसी अन्य विदेशी ऑटोमोबाइल कंपनियां भारत में मौजूदा और नए कारखानों में ईवी विनिर्माण में रुचि दिखा रही हैं। भारी उद्योग मंत्रालय के साथ बैठक के विवरण के अनुसार, सरकार को उम्मीद है कि इस नीति परिवर्तन से ये कंपनियां ईवी में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित होंगी।

मार्च में घोषित नीति के तहत कोई भी ऑटोमोबाइल निर्माता जो भारत में ईवी के निर्माण के लिए कम से कम $500 मिलियन (लगभग ₹4,000 करोड़) का निवेश करता है और 50% घटक स्थानीय रूप से प्राप्त करता है, उसे आयात कर में बड़ी छूट मिलेगी। 8,000 इलेक्ट्रिक कारों के आयात पर यह छूट 100% से घटाकर 15% कर दी जाएगी।

अब नई योजना के तहत मौजूदा कारखानों में ईवी निर्माण के लिए निवेश को भी मान्यता दी जाएगी। हालांकि, इसके लिए ईवी मॉडल को एक अलग उत्पादन लाइन पर बनाना होगा और स्थानीय घटकों का उपयोग अनिवार्य होगा।

नई फैक्ट्रियों के मामले में ईवी निर्माण के लिए मशीनरी और उपकरणों पर किया गया पूरा निवेश $500 मिलियन की आवश्यकता में गिना जाएगा, भले ही इन उपकरणों का उपयोग अन्य प्रकार की कारों के निर्माण के लिए भी किया जाता हो।

सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए एक न्यूनतम ईवी राजस्व लक्ष्य भी निर्धारित करेगी कि योजना के तहत अर्हता प्राप्त करने के लिए किसी संयंत्र या उत्पादन लाइन को इसे पूरा करना होगा।

यह नीति भारत में ईवी निर्माण को प्रोत्साहित करने और देश को ईवी उत्पादन का एक प्रमुख केंद्र बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

हाल ही में हुई एक बैठक के दौरान कई प्रमुख ऑटोमोबाइल कंपनियों ने सरकार के सामने अपनी चिंताएँ और सुझाव पटल पर रखे। बैठक में टोयोटा के अधिकारियों ने पूछा कि क्या ईवी नीति मौजूदा संयंत्र में एक अलग असेंबली लाइन में निवेश की अनुमति देगी जहाँ एक से अधिक पावरट्रेन का उत्पादन होता है। इसके अलावा उन्होंने यह जानने की कोशिश की कि क्या चार्जिंग स्टेशनों के निर्माण और स्थापना पर होने वाला खर्च 500 मिलियन डॉलर (₹4,000 करोड़) के निवेश मानदंड में शामिल होगा।

हुंडई ने नीति के तहत निवेश मानदंड में अनुसंधान और विकास (आरएंडडी) पर होने वाले खर्च को शामिल करने की अनुमति मांगी। सूत्रों के मुताबिक इसे 500 मिलियन डॉलर के निवेश में शामिल नहीं किया जाएगा। हुंडई मोटर इंडिया ने कहा कि वह अंतिम नीति और दिशा-निर्देश जारी होने का इंतजार कर रही है।

वोक्सवैगन ने निवेश समयसीमा में और ढील देने की मांग की। उन्होंने सुझाव दिया कि पांच साल की योजना के तहत 500 मिलियन डॉलर के निवेश का 75% पहले तीन वर्षों में ही करने की अनुमति दी जाए, बजाय इसके कि पहले तीन वर्षों में पूरे 100% निवेश की अनुमति दी जाए। साथ ही वोक्सवैगन ने पूछा कि क्या उनके आपूर्तिकर्ताओं द्वारा किए गए निवेश को भी इस मानदंड में गिना जाएगा।

वोक्सवैगन इंडिया ने कहा कि वह नई ईवी नीति का गहराई से "अध्ययन" कर रही है और इसके आधार पर भविष्य की रणनीति तय करेगी। एक बार नीति लागू हो जाने के बाद, यह देखना बाकी है कि सरकार इन सुझावों को कितनी प्राथमिकता देती है और क्या ये संशोधन भारत में ईवी क्षेत्र में बड़े निवेश और विस्तार को गति देंगे। (रॉयटर्स के इनपुटस सहित)

# मलेशिया ने इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए कर प्रोत्साहन की घोषणा की

मलेशिया ने इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए कर प्रोत्साहन की घोषणा की

परिवहन विशेष न्यूज

मलेशियाई सरकार ने स्थानीय ऑटोमोटिव उद्योग के विकास की दिशा का समर्थन करने के लिए स्थानीय कंपनियों को इलेक्ट्रिक वाहनों के निर्माण के लिए अपने प्रयासों को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए कई पहलों को लागू किया है।

निवेश, व्यापार और निवेश उप मंत्री लियु चिन टोंग के अनुसार सरकार द्वारा की गई पहलों या प्रयासों में 31 दिसंबर 2025 तक आयातित पूर्ण निर्मित इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए आयात और उत्पाद शुल्क में पूर्ण छूट तथा 31 दिसंबर, 2027 तक घरेलू स्तर पर उत्पादित इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए आयात और उत्पाद शुल्क और बिक्री कर में पूर्ण छूट शामिल है।

अन्य पहलों में ईवी और संबंधित महत्वपूर्ण घटकों सहित ऊर्जा कुशल वाहन बनाने वाली कंपनियों के लिए आयकर भत्ता या अग्रणी दर्जा, अगले साल के अंत तक ईवी उपयोगकर्ताओं के लिए सड़क कर में छूट, कर छूट के लिए कर प्रोत्साहन मानदंडों को पूरा करने वाले चार्जिंग प्वाइंट ऑपरेटरों को पांच साल के लिए 100% निवेश कर भत्ते के रूप में हरित निवेश कर भत्ता प्रदान करना शामिल है।

लियु चिन टोंग ने कहा कि ईवी चार्जिंग उपकरण बनाने वाली कंपनियों के लिए 2023 से 2032 तक वैधानिक आय पर आयकर छूट भी दी गई है और 2027 तक के आकलन वर्ष के लिए घर पर ईवी चार्जिंग सुविधाओं की स्थापना या सदस्यता के लिए 2,500 आरएम (607 यूएसडी) तक की व्यक्तिगत आयकर राहत भी दी गई है।

मलेशियाई सरकार ने भी ईवी उद्योग के विकास को समर्थन देने के लिए ईवी पारिस्थितिकी तंत्र के विकास हेतु कई पहल शुरू की हैं।

उदाहरण के लिए 2025 तक 10,000 ईवी चार्जिंग बे के लक्ष्य के साथ ईवी चार्जिंग सुविधाओं का प्रावधान, देश में ईवी परीक्षण और विकास को सुविधाजनक बनाने और लागत को कम करने के लिए एनएक्सजीवी परीक्षण केंद्र (ईवी इंटरऑपरेबिलिटी सेंटर) और राष्ट्रीय रिचार्जेबल बैटरी परीक्षण केंद्र का विकास, और ईवी उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए चार्जिंग सिस्टम, बैटरी निपटान गतिविधियों, बैटरी स्वैपिंग, वायरलेस चार्जिंग और अन्य मानकों जैसे संबंधित मानकों का विकास।

# कबीरा मोबिलिटी ने व्हीकल केयर के साथ बिक्री के बाद शुरू की सर्विस सेवा

परिवहन विशेष न्यूज

इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन निर्माता कबीरा मोबिलिटी ने व्हीकल केयर के साथ मिलकर केएम केयर कार्यक्रम शुरू किया है, जो बिक्री के बाद की सर्विस देने की पहल है। यह कार्यक्रम कबीरा मोबिलिटी के देशभर में फैले 500 से ज़्यादा सर्विस सेंटरों के नेटवर्क पर शुरू किया जाएगा, जिसका उद्देश्य अपने ग्राहकों के लिए बिक्री के बाद सर्विस के अनुभव को बेहतर बनाना है।

केएम केयर प्रोग्राम तीन सर्विस पैकेज प्रदान करता है, केएम केयर एसेंशियल, केएम केयर प्लस और केएम केयर मैक्स, प्रत्येक पैकेज को ग्राहकों की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तैयार किया गया है। पैकेज में कैशलेस सर्विसिंग, रोडसाइड असिस्टेंस और प्रीमियम मेंटेनेंस सपोर्ट के विकल्प शामिल हैं।

केएम केयर प्रोग्राम की मुख्य विशेषताओं में व्यापक कवरेज शामिल है, जो 12 महीने या 10,000 किलोमीटर के लिए वैध है, इसमें आवधिक रखरखाव सेवाएं, कैशलेस सर्विसिंग विकल्प और 24x7 सड़क किनारे सहायता शामिल है। अतिरिक्त लाभों में असली स्पेयर पार्ट्स पर 5% की छूट और प्रत्येक सर्विस विजिट के दौरान वाहन की मुफ्त धुलाई शामिल है। सर्विस सेंटर पर प्राथमिकता से हैंडलिंग और विस्तारित वारंटी विकल्प भी इसका हिस्सा हैं।

सेवा पैकेज में तकनीकी मानकों को बनाए रखा जाएगा, जैसे कि व्हीकल केयर द्वारा प्रमाणित सर्विस केंद्र, फैक्ट्री-प्रशिक्षित तकनीशियनों द्वारा रखरखाव तथा डायग्नोस्टिक उपकरणों और वास्तविक स्पेयर पार्ट्स का उपयोग।

कबीरा मोबिलिटी के सीईओ जयबीर सिवाच ने कहा, ₹व्हीकल केयर के साथ साझेदारी में विकसित केएम केयर कार्यक्रम, बिक्री के बाद भरोसेमंद सर्विस प्रदान करने पर हमारे फोकस को दर्शाता है। यह सहयोग इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन उपयोगकर्ताओं की बढ़ती जरूरतों को पूरा करने के लिए विस्तारित सर्विस नेटवर्क और तकनीकी विशेषज्ञता का लाभ उठाता है।₹

व्हीकलकेयर के साथ साझेदारी कबीरा मोबिलिटी के सर्विस नेटवर्क में उन्नत डायग्नोस्टिक्स उपकरण और सुव्यवस्थित प्रक्रियाएँ पेश करती है। इस पहल का उद्देश्य नियमित रखरखाव सर्विस के लिए 60 मिनट के टर्नअराउंड समय को लक्षित करके दक्षता में सुधार करना भी है। अपनी बिक्री के बाद की क्षमताओं को मजबूत करके, कबीरा मोबिलिटी इलेक्ट्रिक वाहन क्षेत्र की उभरती मांगों को पूरा करना चाहती है।

# जिम्बाब्वे ने मांग बढ़ाने के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों पर आयात शुल्क घटाने की बनाई योजना

परिवहन विशेष न्यूज

जिम्बाब्वे के वित्त मंत्री मथुली क्यूब

हरारे, (आईएएनएस) जिम्बाब्वे के वित्त मंत्री मथुली क्यूब ने पर्यावरण अनुकूल परिवहन को अपनाने को प्रोत्साहित करने के लिए जनवरी 2025 से इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) पर आयात शुल्क कम करने का प्रस्ताव रखा है।

समाचार एजेंसी सिन्हुआ के अनुसार संसद में 2025 का राष्ट्रीय बजट पेश करते हुए मथुली क्यूब ने खुलासा किया कि इलेक्ट्रिक वाहनों पर आयात शुल्क 40 प्रतिशत से घटकर 25 प्रतिशत हो जाएगा।

मथुली क्यूब ने कहा, ₹पर्यावरण अनुकूल वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, जिसके परिणामस्वरूप कार्बन उत्सर्जन कम होगा, मैं 1 जनवरी 2025 से इलेक्ट्रिक मोटर वाहनों पर सीमा शुल्क कम करने का प्रस्ताव करता हूं।₹

उन्होंने सौर ऊर्जा चालित ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए प्रयुक्त उपकरणों पर शुल्क छूट बढ़ाने का भी प्रस्ताव रखा, बशर्ते कि वे अनुमोदित ऑपरेटरों द्वारा आयातित हों, ताकि ईवी अपनाने को और अधिक प्रोत्साहित किया जा सके।

जलवायु परिवर्तन से निपटने की तात्कालिकता पर प्रकाश डालते हुए, मथुली क्यूब ने जलवायु संबंधी चुनौतियों से निपटने के लिए प्राकृतिक संसाधनों का लाभ उठाने वाले नवीन समाधानों के महत्व पर बल दिया।

प्रस्तावित नीति परिवर्तन जिम्बाब्वे में ईवी में बढ़ती रुचि के बीच आया है, जहां हितधारक इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को और अधिक आकर्षक बनाने के लिए उपाय करने की मांग कर रहे हैं।

लिथियम के उत्पादक के रूप में, जो इलेक्ट्रिक वाहनों को शक्ति प्रदान करने के लिए उपयोग की जाने वाली लिथियम-आयन बैटरियों का एक महत्वपूर्ण घटक है। जिम्बाब्वे का लक्ष्य 2030 तक इलेक्ट्रिक वाहनों के बाजार में 33 प्रतिशत की पैठ हासिल करना है।

# दो इंजन ऑप्शन के साथ लॉन्च होगी किआ सिरोस, जनवरी 2025 से डिलीवरी होने की संभावना

परिवहन विशेष न्यूज

किआ की नई एसयूवी बारतीय बाजार में 19 दिसंबर को लॉन्च होने जा रही है। इसे लॉन्च करने को लेकर कंपनी की तरफ से तैयारी भी कर ली गई है। एक रिपोर्ट्स के मुताबिक Kia Syros में दो इंजन ऑप्शन देखने के लिए मिलेंगे जो 1.5-लीटर डीजल और 1.0-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन होगा। इसकी डिलीवरी जनवरी 2025 से शुरू होने की संभावना है।

**नई दिल्ली।** किआ इंडिया 19 दिसंबर को अपनी नई कॉम्पैक्ट एसयूवी Kia Syros को पेश करने जा रही है। इसकी लॉन्चिंग को लेकर कंपनी की तरफ से पूरी तैयारी कर ली गई है। वहीं, कंपनी की तरफ से इसके अभी तक कुछ टीजर भी जारी किया जा चुका है। जिसमें इसका लुक एक बॉक्सी SUV जैसा दिखाई दिया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक, इसमें दो इंजन ऑप्शन देखने के लिए मिल सकता है। आइए जानते हैं कि Kia Syros किन खास फीचर्स के साथ लॉन्च होने वाली है।

### Kia Syros: मिलेंगे दो इंजन ऑप्शन

ज्यादातर कार निर्माता कंपनियां नए डीजल मॉडल पेश करने से कतरा रहे हैं। वहीं, किया इंडिया भारत में डीजल इंजन के साथ अपना पांचवां प्रोडक्ट लॉन्च करके इस चलन को तोड़ती दिख रही है। साइरोस में 1.5-लीटर डीजल इंजन के साथ आ सकती है, जिसका इस्तेमाल किआ और हुंडई के कई मॉडलों में इस्तेमाल किया जाता है। यह इंजन 115hp की पावर और 250Nm का टॉर्क जनरेट करेगा। भारतीय बाजार में सोनेट, वेन्यू, सेल्टोस, कैरेंस, क्रेटा और अल्काजार में इस्तेमाल किया जाता है। गियरबॉक्स ऑप्शन के लिए साइरोस डीजल 6-स्पीड मैनुअल और 6-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक के साथ आएगा।

1.5-लीटर डीजल इंजन के साथ ही इसे 1.0-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन ऑप्शन के साथ पेश किया जाएगा, जो 120 hp की पावर और 172Nm का टॉर्क जनरेट करता है। यह मैनुअल के साथ-साथ 7-स्पीड DCT ऑटोमैटिक गियरबॉक्स भी देखने के लिए मिलेगा। इसकी वजह से Kia Syros की शुरुआती कीमत अपेक्षाकृत अधिक हो सकती है।

### Kia Syros: लॉन्च और डिलीवरी टाइमलाइन

किआ साइरोस 19 दिसंबर को ग्लोबल लेवल पर डेब्यू किया जाएगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक, इसकी कीमतों का खुलासा जनवरी में किया जाएगा। वहीं, इसे भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो शो में एसयूवी को पहली बार आम जनता के लिए दिखाया जाएगा। इसके साथ ही जनवरी 2025 से इसकी डिलीवरी भी शुरू की जाएगी।

### Kia Syros: एक्सपेक्टेड फीचर्स

इसमें डुअल-टोन इंटीरियर थीम देखने के लिए मिल सकता है। साथ ही 2-स्पोक स्टीयरिंग व्हील भी हो सकती है। इसके साथ ही साइरस में डुअल-डिस्प्ले सेटअप, ऑटो एसी, पैनोरमिक सनरूफ, वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें और वायरलेस फोन चार्जर जैसे फीचर्स देखने के लिए मिल सकते हैं।

साइरस को पैसेंजर की सुरक्षा के लिए 6 एयरबैग, ISOFIX चाइल्ड सीट एंकरेज, रिवर्सिंग कैमरा और इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ESC) जैसे फीचर्स से लैस किया जा सकता है।

# पाठ्यक्रम में रचनात्मकता का महत्व

विजय गर्ग

शिक्षा में रचनात्मकता ज्ञान को नवाचार में बदलने, शिक्षार्थियों को सोचने, अन्वेषण करने और जुड़ने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए उत्प्रेरक है

जैसे-जैसे शिक्षा की दुनिया विकसित हो रही है, एक आम सहमति उभर रही है कि शिक्षा के भविष्य को परिभाषित करने के लिए रचनात्मकता आवश्यक है। पाठ्यपुस्तकों और मानकीकृत मूल्यांकनों पर भरोसा करने के बजाय, छात्रों की क्षमता को उजागर करने के साधन के रूप में पाठ्यक्रम के प्रति रचनात्मक दृष्टिकोण तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। रचनात्मकता न केवल एक कला है बल्कि एक संज्ञानात्मक क्षमता भी है जो कई विषयों तक फैली हुई है और छात्रों को महत्वपूर्ण सोच और समस्या-समाधान कौशल विकसित करने में सक्षम बनाती है। शिक्षक एक ऐसा वातावरण बना सकते हैं जो शैक्षिक पाठ्यक्रम में रचनात्मक तत्वों को शामिल करके शिक्षार्थियों को विभिन्न नवाचारों और कौशल पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित करता है। एक रचनात्मक पाठ्यक्रम विविध शिक्षण शैलियों और प्राथमिकताओं को समायोजित करता है। छात्रों को अपनी शैक्षिक यात्रा में स्वायत्तता और वैयक्तिकरण की भावना को बढ़ावा देते हुए, अपने हितों का पता लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। सभी कौशल मस्तिष्क से शुरू होते हैं। चाहे ब्रेस्टस्ट्रोक तैरना सीखना हो या किसी समीकरण को हल करना, यह सब मस्तिष्क के सही क्षेत्र में न्यूरॉन्स के बार-बार सक्रिय होने से शुरू होता है जब तक कि आप इसमें महारत हासिल नहीं कर लेते।

रचनात्मकता की सही मात्रा बच्चों को नई चीजें सीखने के लिए प्रेरित करती है और नवाचार को बढ़ावा देती है। नवोन्मेषी शैक्षिक वातावरण में छात्रों के सीखने के तरीके को महत्वपूर्ण रूप से बदलने और जो कुछ वे सीखते हैं उसे वास्तविक दुनिया में लागू करने की शक्ति होती है।

भावनात्मक और सामाजिक विकासः रचनात्मक गतिविधियों में अक्सर आत्म-अभिव्यक्ति और सहयोग शामिल होता है, जो भावनात्मक और सामाजिक कौशल विकास में योगदान देता है। छात्र खुद को आत्मविश्वास से व्यक्त करना और दूसरों के दृष्टिकोण को समझना सीखते हैं।

उन्नत आलोचनात्मक सोचः यह छात्रों को गंभीर रूप से सोचने, जानकारी का विश्लेषण करने और समस्या-समाधान कौशल विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करता है। इससे, बदले में, उनकी समग्र संज्ञानात्मक क्षमताओं में सुधार होता है। कौशल विकासः छात्रों में कौशल विकास की एक विस्तृत श्रृंखला है। एक बार रचनात्मक गतिविधियों में संलग्न होने के बाद अक्सर उनके संचार कौशल, सहयोग क्षमता और अनुकूलन क्षमता में वृद्धि होती है। बढ़ी हुई व्यस्तता और प्रेरणाः पाठ्यक्रम में रचनात्मक तत्व सीखने को अधिक मनोरंजक और छात्रों के हितों के लिए प्रासंगिक बनाते हैं। यह बढ़ी हुई व्यस्तता आंतरिक प्रेरणा को बढ़ावा देती है, जिससे प्रयास, भागीदारी और शैक्षणिक कार्यों के

प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण बढ़ता है।

वैयक्तिकृत शिक्षणः रचनात्मक गतिविधियों में शामिल होने से छात्रों को विविध शिक्षण शैलियों को पूरा करते हुए अभिव्यक्ति के विभिन्न रूपों को विकसित करने की अनुमति मिलती है। उदाहरण के लिए, जो छात्र पारंपरिक तरीकों से संघर्ष करते हैं, वे आगे बढ़ सकते हैं जब उन्हें खुद को रचनात्मक रूप से व्यक्त करने की अनुमति दी जाती है, जिससे सीखने का माहौल अधिक समावेशी और प्रभावी हो जाता है। धारण शक्तिः रचनात्मकता सूचना और ज्ञान की धारण क्षमता को बढ़ाती है। जब छात्र अकादमिक सामग्री को रचनात्मक परियोजनाओं या वास्तविक दुनिया के अनुप्रयोगों से जोड़ते हैं, तो उन्होंने जो सीखा है उसे याद रखने और लागू करने की अधिक संभावना होती है। पाठ्यक्रम में रचनात्मकता को शामिल करने से छात्रों के प्रदर्शन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। यह सीखने को एक गतिशील और सार्थक अनुभव बनाता है जो छात्रों को कक्षा और जीवन भर में सफलता के लिए तैयार करता है। एआई, रोबोटिक्स, 3डी प्रिंटिंग, एआर/वीआर और बायोटेक में तेजी से प्रगति के युग में, यह सवाल महत्वपूर्ण हैः क्या हमारे स्कूल वास्तव में हमारे बच्चों को इस भविष्य के लिए तैयार कर रहे हैं? भारत व्यक्तिगत शिक्षण अवधारणाओं को अपनाकर शिक्षा पारिस्थितिकी तंत्र को बदलने की कगार पर है। हमें आगे बढ़ने की जरूरत हैसमय के साथ और एक सीखने का पारिस्थितिकी तंत्र बनाएं जो भविष्य के पेशेवरों और नागरिकों को तैयार करे जो दुनिया में कहीं भी प्रतिस्पर्धा कर सकें और फल-फूल सकें। रचनात्मक पाठ्यक्रम में निवेश यह सुनिश्चित करता है कि छात्र विश्व मंच पर सार्थक योगदान देने के लिए सुसज्जित हैं। ऐसे पाठ्यक्रम को अपनाकर जो रचनात्मकता को महत्व देता है और उसका पोषण करता है, शिक्षक शिक्षा को बदल सकते हैं।

# प्रदेश का 21वां स्थान : चिंताएं और समाधान

शिक्षा में सुधार न केवल राज्य की प्रगति को तेज करेगा, बल्कि यहां के नागरिकों को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाएगा। शिक्षा का स्तर गिरना न केवल शैक्षिक दृष्टिकोण से, बल्कि आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए भी बड़ा खतरा है

शिक्षा किसी भी राज्य की प्रगति का आधार है। जब किसी राज्य की शिक्षा प्रणाली कमजोर होती है, तो इसका सीधा असर वहां के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विकास पर पड़ता है। लेकिन यह स्थिति बदली जा सकती है। उचित नीतियां, सामूहिक प्रयास और दृढ़ इच्छाशक्ति से किसी भी राज्य को शिक्षा के क्षेत्र में पीछे से शीर्ष तक लाया जा सकता है। इसके लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा सकते हैं।

हिमाचल प्रदेश, जिसे कभी देश के अग्रणी शिक्षित राज्यों में गिना जाता था, का शिक्षा स्तर 21वें स्थान पर खिसकना वास्तव में चिंताजनक है। यह स्थिति न केवल राज्य के शैक्षिक ढांचे की कमजोरियों को उजागर करती है, बल्कि प्रदेश की समग्र प्रगति के लिए भी एक बड़ा खतरा बन सकती है। यह समय है कि इस गिरावट के कारणों को पहचाना जाए और उन्हें सटीक सुधारात्मक कदमों के माध्यम से दूर किया जाए। शिक्षा की प्राथमिकता तय करने के लिए राजनीतिक और प्रशासनिक संकल्प होना बहुत जरूरी है। राज्य सरकार को शिक्षा को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल करना होगा। इसके लिए बजट में शिक्षा के लिए अधिक आवंटन सुनिश्चित करना होगा। साथ ही यह लक्ष्य निर्धारण हो कि राज्य को प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा में सुधार के लिए ठोस और समयबद्ध लक्ष्य तय करने चाहिए। गुणवत्तापूर्ण शिक्षकों की नियुक्ति और प्रशिक्षण हेतु योग्य शिक्षकों की भर्ती हो।

शिक्षकों की भर्ती में पारदर्शिता हो और योग्यता को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। साथ ही नियमित प्रशिक्षण के माध्यम से शिक्षकों को नई-नई शिक्षण पद्धतियों और तकनीकों का प्रशिक्षण देना जरूरी है। माननीय शिक्षा सचिव हिमाचल प्रदेश सरकार श्री राजेश कंवर का एक स्वागतयोग्य वक्तव्य है कि हिमाचल प्रदेश के हर स्कूल में पुस्तकालय और जिम जैसी वर्तमान आधारभूत सुविधा होनी चाहिए। अगर बुनियादी ढांचे का सुधार करना हो तो सबसे पहले है स्कूलों की स्थिति को सुधारना चाहिए। हर स्कूल में पक्की इमारत, शौचालय, स्वच्छ पेयजल, पुस्तकालय और विज्ञान प्रयोगशाला जैसी सुविधाएं होनी चाहिए। तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए स्मार्ट क्लासरूम का निर्माण आवश्यक है। डिजिटल शिक्षा का प्रसार भी होना चाहिए। डिजिटल उपकरण उपलब्ध कराना, छात्रों और शिक्षकों को टैबलेट, लैपटॉप या अन्य डिजिटल उपकरण उपलब्ध कराए जाएं। इंटरनेट के विस्तार के साथ ऑनलाइन पाठ्यक्रम को और रुचिकर बनाने के लिए छात्रों के लिए गुणवत्तापूर्ण ऑनलाइन पाठ्यक्रम और सामग्री विकसित की जाए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति (2020) के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु इसके तहत कौशल विकास, मूल्य आधारित शिक्षा और मातृभाषा में पढ़ाई को बढ़ावा दिया जाए। स्कूल ड्रॉपआउट और पलायन को रोकना आज एक चुनौती भी है। मूल्यांकन सुधार हेतु रटने की बजाय व्यावहारिक शिक्षा और कौशल आधारित मूल्यांकन प्रणाली लागू की जाए। परख कार्यक्रम भारत की शिक्षा प्रणाली में क्रांतिकारी बदलाव लाने की एक कोशिश है। यह छात्रों की क्षमताओं को सही तरीके से आंकने और उन्हें सही दिशा में मार्गदर्शन देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

यदि इसे प्रभावी रूप से लागू किया जाए तो यह न केवल भारत के शिक्षा मानकों को ऊंचा उठाएगा, बल्कि इसे एक वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक स्तर पर भी ले जाएगा। सामुदायिक भागीदारी और जागरूकता के माध्यम से अभिभावकों और शिक्षकों को बच्चों की पढ़ाई में सक्रिय भूमिका

निभाने के लिए प्रेरित किया जाए। हिमाचल जैसे पहाड़ी राज्य में शिक्षा के महत्व को लेकर ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में व्यापक जागरूकता अभियान चलाए जाएं। स्थानीय संगठनों की मदद से गैर-सरकारी संगठनों और पंचायतों को शिक्षा के प्रचार-प्रसार में शामिल किया जाए। पीएम श्री स्कूल और राजीव गांधी मॉडल स्कूल हिमाचल प्रदेश के शिक्षा तंत्र में सुधार के लिए मील का पत्थर साबित हो सकते हैं। ये न केवल शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाएंगे, बल्कि राज्य के बच्चों को भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार करेंगे। यदि इन योजनाओं को पूरी ईमानदारी और समर्पण से लागू किया जाए, तो हिमाचल प्रदेश शिक्षा के क्षेत्र में देश के अग्रणी राज्यों में फिर से अपनी जगह बना सकता है। इसके साथ ही छात्रवृत्ति, पुरस्कार और प्रोत्साहन जैसी योजनाएं शिक्षा के स्तर को और बढ़ा सकती हैं। आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चों को मुफ्त शिक्षा और वजीफे दिए जाएं। प्रतिभाशाली छात्रों के लिए विशेष पुरस्कार और उच्च शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराए जाएं। शिक्षक सम्मान के लिए कोई संस्था निगरानी करे, न कि शिक्षक खुद पुरस्कार पाने के लिए आवेदन करें। जो शिक्षक सच में इस सम्मान का हकदार है, वो शहर और गांव में कहीं भी हो सकता है। राज्य में शैक्षणिक परियोजनाओं को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए निजी कंपनियों और संस्थानों के साथ साझेदारी की जाए। क्षेत्रीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदान किया जाए।

इसके लिए पर्यटन और कृषि शिक्षा के तहत हिमाचल प्रदेश जैसे राज्य में पर्यटन, कृषि या हस्तशिल्प में जो समृद्ध है, तो इन क्षेत्रों में विशेषज्ञता आधारित पाठ्यक्रम बनाए जाएं। किसी भी राज्य को शिक्षा के क्षेत्र में नीचे से ऊपर लाना कठिन जरूर है, लेकिन असंभव नहीं। इसके लिए सरकार, शिक्षक, अभिभावक और समाज, सभी को मिलकर काम करना होगा। यदि योजनाओं को ईमानदारी और प्रतिबद्धता के साथ लागू किया जाए, तो वह दिन दूर नहीं जब राज्य शिक्षा के क्षेत्र में नए आयाम छू सकेगा। शिक्षा में सुधार न केवल राज्य की प्रगति को तेज करेगा, बल्कि यहां के नागरिकों को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाएगा। हिमाचल प्रदेश का शिक्षा का स्तर गिरना न केवल शैक्षिक दृष्टिकोण से, बल्कि आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए भी एक बड़ा खतरा है। यह समस्या तत्काल ध्यान और सुधारात्मक उपायों की मांग करती है। यदि शिक्षकों, अभिभावकों, सरकार और छात्रों का समन्वय हो, तो हिमाचल प्रदेश अपने पुराने गौरव को पुनः प्राप्त कर सकता है और शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी राज्य बन सकता है। अब ठोस पहल होनी चाहिए।

# कॅरिअर ग्रोथ के लिए कौशल हो आधार

विजय गर्ग

इन्फॉर्मेशन ऐज की दुनिया में कौशल ज्ञान के दायरे को बढ़ाना लगभग सभी पेशेवरों व युवाओं की मांग है। जिस दोगुनी गति से लोगों के लिए एवरग्रीन सेक्टर में नौकरी की संभावनाएं बढ़ रही हैं, उसे देखते हुए हमें एक बेहतर कॅरिअर निर्माण के लिए खुद को नई तकनीकों के अनुरूप ढालने व यूं कहे परिचित होने की नितांत आवश्यकता है। बेहतर कॅरिअर ग्रोथ के लिए लाजमी है कि आप स्वयं के लिए नए विकल्प तलाशें और खुद से प्रश्न करें कि कैसे आप जीवन में नए कौशलों से अपग्रेड हो सकते हैं।

**कॅरिअर पर प्रभाव डालने वाले कौशल**

अगर आप कॅरिअर के अभी शुरुआती दौर में हैं तो सबसे पहले आपको यह जानना होगा कि कौन से कौशल की इस डिजिटल दुनिया में अधिक मांग है और यह कैसे आपके दीर्घकालीन जीवन में प्रभाव डाल सकते हैं। दरअसल डिजिटल माहौल के तेजी से बदलते इस दौर में कौशल की मांग को पहचानने का यह पहला कदम है। जब आप स्वयं के विकास के लिए कौशल की पहचान कर लेते हैं, तब आप खुद के लिए आत्म-विकास की दिशा में सही कौशल का चुनाव कर पाने में भी कामयाब हो जाते हैं।

**मौजूदा कौशल व पसंदीदा कॅरिअर का मेल**

कौशल सेट को बढ़ाने के लिए आपको यह समझना भी बेहद जरूरी है कि आपके मौजूदा कौशल और अनुभव आपके पसंदीदा कॅरिअर के साथ मेल खाते हैं या नहीं। साथ ही क्या आपके पास उन कौशलों की कमी है जो आपके पसंदीदा कॅरिअर मार्ग के साथ मेल खाते हैं? अक्सर जब भी आप यह सवाल खुद से पूछते हैं तो आपको यह समझने में मदद मिलती है कि अभी किन कौशलों को विकसित करने की आवश्यकता है।

**विभिन्न स्रोतों से सीखें कौशल**

अपने कौशल ज्ञान के दायरे को बढ़ाने के लिए उपलब्ध स्रोतों की जांच करना आपके लिए बेहद जरूरी है। आपका यह मूल्यांकन करना भी जरूरी है कि कौन से ऑनलाइन कोर्स, वर्कशॉप या प्रमाणपत्र की मदद से आप भविष्य के लिए नए कौशल के अवसर का विकास कर सकते हैं।

**सही मेंटर का करें चुनाव**

किसी क्षेत्र के बारे में जानकारी लेनी हो या कॅरिअर ग्रोथ के लिए मशविरा एक मैटर दोनों ही परिस्थितियों में आपका साथ बखूबी निभाता है। मेंटर द्वारा दिए जाने वाले सुझाव आपके कॅरिअर का सही चुनाव कर बेहतर भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। इसलिए अगर आप सही मॅटर का चुनाव करते हैं तो यह न केवल आपको भविष्य में नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में मदद करता है, बल्कि आपका व्यक्तिगत विकास करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

# दफन हो चुके मुद्दों को भुलाना जरूरी

आश्चर्य की बात यह है कि एक तरफ भारत विश्व को नेतृत्व देने की तरफ कदम बढ़ा रहा है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता की मांग कर रहा है। देश की तरक्की को पंख लगाने की दलील दी जा रही है। अर्थव्यवस्था पैर पसार रही है। इसके बावजूद मंदिर-मस्जिद के विवादित मुद्दों से पीछा नहीं छुड़ा पा रहा है। ऐसे विवादित मुद्दों से बचने के लिए जरूरी है कि पूजा स्थल कानून को और सशक्त बनाया जाए

आजादी के 77 सालों में देश ने बहुत तरक्की की है। विश्व में भारत ने कई क्षेत्रों में अपना परचम लहराया है। भारत विश्व की पांचवीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया। अब चौथी और तीसरी बनने की तरफ तेजी से अग्रसर है। इसके बावजूद कुछ बुनियादी झंझटों से भारत मुक्त नहीं हो सका। इसके जिम्मेदार हैं देश के राजनीतिक दलों के नेता। नेताओं ने अपने चुनावी फायदे के लिए देश को कई बार सांप्रदायिकता की आग में झोंका है। ऐसी समस्याओं से न सिर्फ सामाजिक समरसता में विघ्न पड़ा है, बल्कि देश की तरक्की के रास्ते में बाधा पड़ी है। उत्तर प्रदेश के संभल में मंदिर-मस्जिद विवाद से हिंदू-मुस्लिम एकता में फिर से दरार पड़ी है। ऐसे विवाद देश में लगातार बने हुए हैं। संभल की जामा मस्जिद में मंदिर होने के प्रमाण के अदालत के सर्वे के बाद हिंसा भड़क उठी। भीड़ ने पुलिस पर पथराव किया। पुलिस ने फायरिंग की जिसमें 5 लोग मारे गए। इस मुद्दे को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने के बजाय इस पर जम कर वोटों की राजनीति की गई। मस्जिदों के स्थान पर मंदिर होने का मुद्दा नया नहीं है। इतिहास में ऐसे दफन हो चुके मुद्दों को उठाने से देश की एकता-अखंडता प्रभावित हो रही है। इसकी किसी को चिंता नहीं है। हकीकत में नेताओं को धार्मिक भावनाओं की नहीं, धुरवीकरण करके वोट बटोरने की आकांक्षा ज्यादा है। इन मुद्दों से सिवाय वोटों के फायदे के कुछ हासिल नहीं होगा। इससे तरक्की की रफ्तार पर लगाम जरूर लगती है। देश के नेता तो मानो ऐसे ज्वलनशील मुद्दों की तलाश में रहते हैं। बस उन्हें सिर्फ मौका मिलना चाहिए। सांप्रदायिकता की आग को बुझाने के बजाय उसमें घी डाल कर राजनीतिक हित साधने का नेताओं का रवैया पुराना है।

संभल की घटना ने एक बार फिर पूजा स्थल अधिनियम 1991 पर सवाल खड़े कर दिए हैं। इस कानून को इस तरह की सांप्रदायिक हिंसा को रोकने के लिए पारित किया गया था। यह अधिनियम धार्मिक स्थलों के स्वरूप में किसी भी प्रकार के परिवर्तन को प्रतिबंधित करता है और यह प्रावधान करता है कि 15 अगस्त 1947 को धार्मिक स्थलों का जो स्वरूप था, उसे बनाए रखा जाएगा। इस अधिनियम में दिए गए कुछ अपवादों को न्यायालयों ने अपने-अपने हिसाब से व्याख्यायित किया है। यही कारण है कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय के दो फैसलों से निकलकर आए एक नए अपवाद ने इस अधिनियम को लगभग अप्रभावी बना दिया है। उपासना स्थल अधिनियम इस हद तक कमजोर हो चुका है कि भारत में बाबरी-अयोध्या जैसे नए विवादों की बाढ़ आ सकती है। संभल की इस मस्जिद के पहले इस तरह के आदेश पहले वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद और मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद के लिए भी दिए गए थे। पूजा स्थल विधेयक को लेकर 2019 में सुप्रीम कोर्ट की पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने अयोध्या राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद विवाद पर अपने फैसले में कहा था कि ऐतिहासिक गलतियों को कानून हाथ में लेकर ठीक नहीं किया जा सकता। सार्वजनिक उपासना स्थलों के स्वरूप को बनाए रखते हुए संसद ने स्पष्ट रूप से यह सुनिश्चित किया है कि इतिहास और उसकी गलतियों का उपयोग वर्तमान और भविष्य को दबाने के लिए उपकरण के रूप में नहीं किया जाएगा। यह टिप्पणी पूजा स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1991 का संदर्भ देती है, जो 15 अगस्त 1947 के बाद से किसी भी धार्मिक स्थल के स्वरूप को बदलने की मांग को प्रतिबंधित करता है और ऐसा प्रयास करने वाले व्यक्ति को दंडित करने का प्रावधान करता है। 1991 में यह अधिनियम पारित हुआ और 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने इसके महत्व को दोहराया।

अदालत ने 1991 के अधिनियम से एक अपवाद के रूप में स्वीकार किया क्योंकि यह 1947 से पहले की कानूनी प्रक्रिया से जुड़ा था। इससे लगा कि देश को सांप्रदायिक जहर से मुक्त कर दिया है। पर ऐसा हो नहीं सका। मौजूदा हालात ये हैं कि हर महीने कहीं न कहीं से खबर आती है कि यह मस्जिद पहले मंदिर या यह शिवाला था। इसमें बहुत सारे मामले कोर्ट में भी पहुंच चुके हैं। पूजा स्थल अधिनियम में मौजूद अपवाद और इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा पेश किया गया नया अपवाद, ढेर सारे विवादों को कानूनी और सामाजिक रूप से बढ़ावा दे रहा है। अयोध्या में राममंदिर का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट से हल होने और मंदिर बन जाने के बाद लगा था कि भारत धार्मिक और सांप्रदायिक सौहार्द के एक नए युग में प्रवेश कर रहा है। इसके बावजूद यह मुद्दा सच्चाई नहीं बन सका। अब देश में अलग-अलग स्थानों पर मंदिर-मस्जिद का मुद्दा सुलग रहा है। वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद के मामले में कुछ समय पहले हिंदू पक्ष के वकील ने दावा किया था कि देश में केवल काशी और मथुरा की मस्जिदें ही विवादित नहीं हैं, बल्कि इनकी संख्या कहीं ज्यादा है। ज्ञानवापी मस्जिद मामले में हिंदू पक्ष का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील ने अदालत में कहा था कि भारत भर में विवादित मस्जिदों और स्मारकों की संख्या लगभग 50 है। इनमें कुछ प्रमुख ऐसी हैं जहां भविष्य में कभी भी विवाद बढने के आसार बन सकते हैं। अयोध्या के राम मंदिर में रामलला की प्राण-प्रतिष्ठा के मौके पर संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा था कि अब पुरानी बातों को भूलने का वक्त है। उन्होंने कहा था कि रामलला के साथ भारत का गौरव लौट कर आया है। इसके अलावा हमें सबको साथ लेकर चलना है, अब विवादों से बचना होगा। इसके बावजूद मथुरा में शाही मस्जिद, धार (मध्यप्रदेश) में भोजशाला परिसर, दिल्ली में कुतुब मीनार, लखनऊ में टीली वाली मस्जिद, अजमेर में मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह, मध्य प्रदेश में कमाल-उद-दीन मस्जिद, वाराणसी की धरहरा मस्जिद, बंदायूं की शाही इमाम मस्जिद सहित देश में और कई स्थानों पर विवादों को हवा देने में कसर नहीं छोड़ी जा रही है।

ऐतिहासिक धार्मिक स्थलों पर ऐसे विवादों के मद्देनजर कई बार पूजा स्थल अधिनियम में बदलाव की मांग की जा चुकी है, ताकि इस तरह के दफन हो चुके मुद्दों को फिर से नहीं उठाया जाए। नेताओं ने इस मांग को अनसुना कर दिया। इसके विपरीत भाजपा पूजा स्थल अधिनियम 1991 को खत्म किए जाने की मांग कर चुकी है, ताकि देश में बहुत से धार्मिक स्थलों को मुक्त कराया जा सके। भाजपा नेता और राज्यसभा सांसद हरनाथ सिंह यादव ने पूजा स्थल कानून 1991 को तत्काल समाप्त करने की मांग उठाई थी। राज्यसभा में उन्होंने आरोप लगाया था कि यह कानून संविधान के तहत प्रदान किए गए हिंदुओं, सिखों, जैनियों और बौद्धों के धार्मिक अधिकारों का अतिक्रमण करता है। इससे जाहिर है कि कम से कम भाजपा इस कानून में संशोधन करने या इसे समाप्त करने के पक्ष में है। आश्चर्य की बात यह है कि एक तरफ भारत विश्व को नेतृत्व देने की तरफ कदम बढ़ा रहा है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता की मांग कर रहा है। देश की तरक्की को पंख लगाने की दलील दी जा रही है। अर्थव्यवस्था पैर पसार रही है। इसके बावजूद मंदिर-मस्जिद के विवादित मुद्दों से पीछा नहीं छुड़ा पा रहा है। ऐसे विवादित मुद्दों से बचने के लिए जरूरी है कि पूजा स्थल कानून को और सशक्त बनाया जाए। यदि ऐसा संभव नहीं है तो इस कानून को समाप्त कर दिया जाए। इतिहास में समा चुके सांप्रदायिक लिहाज से बेहद संवेनदशील मुद्दों को फिर से खोदा जाएगा, तो देश की छवि कलंकित होती रहेगी।

## ● ठंड पर बयान

नेताजी का बयान आया है। यह बयान भ्रष्टाचार पर नहीं आया है। महंगाई पर भी नहीं आया है। राजनीतिक सूरते हाल पर भी नहीं आया है। बयान ठंड पर आया है। इस बार जल्दी ठंड क्यों आ गई और इस ठंड में नेताजी की कंपकंपी क्यों छूट रही है, इस बारे नेताजी बयान दे रहे हैं। अब नेताजी बयान दे रहे हैं और विपक्ष वाले नेता जी के बयान पर ध्यान दे रहे हैं। नेताजी कह रहे हैं कि हमने ठंड से निपटने के पूरे इंतजाम किए थे। चाक चौबंद व्यवस्था की थी। जगह-जगह नाके लगाए थे। नाकों पर अपने बंदे भी बिठाए थे। ठंड की ऐसी तैसी फेरने में हमने कोई प्रयास बाकी नहीं रखे थे। लेकिन इसके बावजूद ठंड ने सुरक्षा चक्र भेद दिया तो इसके पीछे दो ही बातें हो सकती हैं। विदेशी शक्तियों का हाथ भी हो सकता है और विपक्ष की खुराफात भी हो सकती है। इनमें विपक्ष पर मुझे ज्यादा शक है। विपक्ष के नेता आए दिन अपने आलाकमान के पास जाते रहते हैं। साजिश वहीं रची गई होगी। वैसे भी विपक्ष के पास कोई पॉजिटिव एजेंडा नहीं है। सरकार को डंडा देना ही विपक्ष का एकमात्र एजेंडा है। पहले विपक्ष ने सरकार गिराने का षड्यंत्र रचा और अब विपक्ष ठंड का माहौल पैदा करके सरकार को ठंडी करना चाहता है। विपक्ष चाहता है कि मैं ठंड से कांप कांप कर घुटने टेक दूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। जल्दी ही सदन में इस बारे एक अध्यादेश लाया जाएगा। ठोस कानून बनाया जाएगा। इस बार तो ठंड ने अपना करतब दिखा दिया। लेकिन अगली बार से ऐसा नहीं होने दिया जाएगा, यह मैं पब्लिक को पूरा भरोसा दिलाता हूं। अभी इधर नेताजी का बयान टेलीकास्ट हुआ ही था कि विपक्ष भी अपने अस्त्र-शस्त्र लेकर ठंड में कूद गया। दूसरा बयान विपक्ष के नेता का आ गया। विपक्ष के नेता का कहना था कि सरकार की तमाम योजनाएं ठंडे बस्ते में पड़ी हैं। सारे वायदे ठंडे बस्ते में पड़े हैं। कर्मचारी और पेंशनरों के एरियर भुगतान के बिल ठंडे बस्ते में पड़े हैं।

सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार के इरादे ही ठंडे पड़े हैं। ठंड यहीं से शीतलहर में बदली है। इसके लिए नेताजी खुद जिम्मेदार हैं और उनकी सरकार जिम्मेदार है। हम तो हमेशा माहौल गर्म रखते हैं। कोई दिन ऐसा नहीं जाता जब मीडिया में हमारा गरमा गरम बयान नहीं आता। लेकिन सरकार मृत्यु शैया पर पड़ी है। एकदम से ठंडी पड़ी है। जान प्राण काम होते जा रहे हैं। सत्तारूढ़ दल के अपने ही नेता अपने बिस्तरों से निकलकर हमारे दल में आ रहे हैं और अलाव ताप रहे हैं। हम अपने अलाव कभी ठंडा नहीं होने देते। जब हमारी सरकार होती है, तब हम लोगों के चूल्हे ठंडे नहीं होने देते। हम लोगों की उम्मीदें ठंडी नहीं होने देते। हम एक से एक गरमा गरम योजनाएं लाते हैं। इन योजनाओं पर फिर हम रोटियां सेंकते हैं। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि एक ठंडी सरकार सत्ता में आई है और चारों तरफ ठंड और धुंध का माहौल बना दिया है। कुछ भी आर-पार नहीं दिख रहा। सरकार दिशाहीन हो गई है। सरकार का अपने अधिकारियों पर कोई नियंत्रण नहीं रहा। इसलिए ठंड बेकाबू हो गई है। इसमें हमारा कोई हाथ नहीं है। हमने वैसे भी हाथों में दस्ताने पहन रखे हैं। हमने गले में मफलर लपेट रखा है। हम अपने शरीर को गर्म रखने के लिए कई तरह की चीजें खाते और पीते हैं। लेकिन सरकार सिर्फ और सिर्फ मुल्क को खाने में लगी है। यहां के संसाधनों को बेचने में लगी है। माफिया को बढ़ावा देने में लगी है। सत्तारूढ़ दल का ध्यान लूट खसूट की तरफ है। सरकार सत्ता के नशे में है। और मौके का फायदा उठाकर ठंड ने हमला बोल दिया है। सरकार के मुखिया ने जनता को उसके हाल पर छोड़ दिया है। लेकिन हम चुप नहीं बैठेंगे। पब्लिक को ठंड से मरने नहीं देंगे। हम एक बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे। जगह-जगह हमारे कार्यकर्ता नारे लगाएंगे। नारे लगाने से गर्मी पैदा होती है। माहौल गर्म होता है। हम बैरिकेड तोड़ेंगे। चैनलों पर इसे दिखाया जाएगा। माहौल गर्म करने में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। सरकार से ठंड दूर नहीं हो रही। हम ठंड दूर करके दिखाएंगे। नई सरकार लेकर आएंगे। हम अलग से कानून बनाएंगे। ठंड में कभी घुटने नहीं टेकेंगे। बहरहाल ठंड को लेकर दोनों तरफ से बयानबाजी जारी है और उधर ठंड का प्रकोप भी जारी है।

# परिजन की मृत्यु के बाद उनके आईडी प्रूफ का क्या करें? कैंसिल या सरेंडर करना रहेगा सही

परिवहन विशेष न्यूज

मृत्यु अटल है उसे टाला नहीं जा सकता है। यह जानने के बाद भी हमें सबसे ज्यादा खौफ मृत्यु से लगता है। सिर्फ इस ख्याल से ही हमारी रूह कांप जाती है। अगर परिवार में किसी सदस्य की मृत्यु हो जाती तो यह समय इमोशनली चैलेंजफुल होता है। किसी भी व्यक्ति के मृत्यु के बाद उनके ऑफिशियल डॉक्यूमेंट जैसे आईडी प्रूफ का क्या करना चाहिए? इस आर्टिकल में जानते हैं।

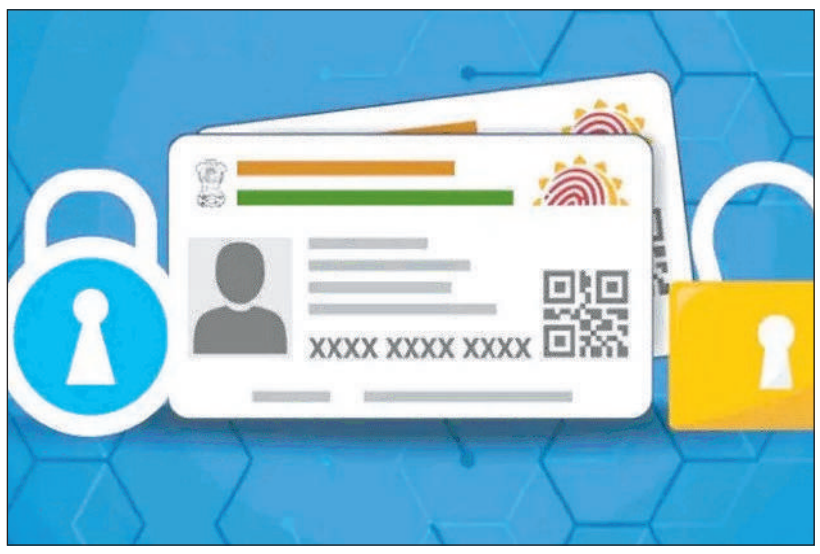

**नई दिल्ली।** हमारे परिवार में अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो वह इमोशनली काफी चैलेंज भरा रहता है। किसी व्यक्ति के दूर जाने की सोचभर से ही हम घबरा जाते हैं। ऐसे में सच में किसी के मृत्यु हो जाने पर हम स्तब्ध हो जाते हैं।

इस चुनौती भरे सफर में हमेशा एक सवाल आता है कि आखिर उस व्यक्ति के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स यानी आईडी प्रूफ का क्या करें? इन डॉक्यूमेंट्स को रहने दे या फिर सरेंडर करें, इस तरह का कन्फ्यूजन बनी रहती है। हम आपको बताएंगे कि किसी व्यक्ति के मृत्यु हो जाने के बाद आपको इन डॉक्यूमेंट्स का क्या करना चाहिए।

**आधार कार्ड का क्या करें?**

आधार कार्ड (Aadhaar Card) का इस्तेमाल कई सरकारी और गैर-सरकारी कामों में किया जाता है।आधार कार्ड पर मौजूद यूनिक आईडेंटिफिकेशन नंबर का इस्तेमाल कई काम जैसे- एलपीजी सब्सिडी, स्कॉरशिप और ईपीएफ अकाउंट में होता है। ऐसे में अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो इस कार्ड का क्या करें?

वर्तमान में आधार कार्ड जारी करने वाला संस्थान यूनिक आईडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (UIDAI) ने आधार डिएक्टिवेशन को लेकर कोई नियम नहीं बनाया है। इसका मतलब है कि आप आधार कार्ड को डिएक्टिवेट नहीं करवा सकते हैं। इसके अलावा आप व्यक्ति के मृत्यु हो जाने पर इसे अपडेट नहीं कर सकते हैं। इस स्थिति में आपको इस कार्ड को संभालकर रखना होगा ताकि कोई इस कार्ड का गलत इस्तेमाल न कर पाएं।

**पैन कार्ड**

पैन कार्ड (Pan Card) इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (Income Tax Department) द्वारा जारी किया जाता है। इसका इस्तेनमाल अधिकतर इनकम टैक्स रिटर्न (ITR), बैंक अकाउंट (Bank Account) को ऑपरेट और डीमैट अकाउंट (Demat Account) को ऑपरेट करने के लिए किया जाता है। इसका मतलब है कि वित्तीय लेनदेन के लिए पैन कार्ड की आवश्यकता होती है।

व्यक्ति के मृत्यु हो जाने के बाद आपको पैन कार्ड को सरेंडर करवाना चाहिए। आयकर विभाग ने पैन कार्ड सरेंडर करने का ऑप्शन दिया है। पैन कार्ड सरेंडर हो जाने के बाद कोई भी व्यक्ति उस कार्ड या पैन नंबर का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा।

**कैसे करें पैन कार्ड सरेंडर (Pan Card Surrender Process)**

लोकल इनकम टैक्स असेसिंग ऑफिसर को पैन सरेंडर का आवेदन लिखकर दें।

इस आवेदन में आपको व्यक्ति का नाम, डेट ऑफ बर्थ की जानकारी देनी होगी।

इसके अलावा आपको डेथ सर्टिफिकेट (death certificate) भी अटैच करना होगा।

पैन कार्ड को सरेंडर करना अनिवार्य नहीं है। लेकिन सभी वित्तीय मामले सेटलडॉउन हो जाएं इसके लिए आपको इस सरेंडर करना चाहिए।

**वोटर आईडी कार्ड**

वोटर आईडी कार्ड (Voter ID) का इस्तेमाल केवल वोट करने के लिए ही नहीं होता है। कई जगह पर आईडी प्रूफ के तौर पर भी आप अपना वोटिंग कार्ड जमा करवा सकते हैं। व्यक्ति के मृत्यु हो जाने के बाद आपको वोटिंग कार्ड कैंसिल करवाना होता है। निर्वाचक पंजीकरण नियम, 1960 के तहत वोटर आईडी कैंसिल हो सकता है।

वोटर आईडी को कैंसिल करने के लिए आपको अपने लोकल इलेक्शन ऑफिस जाना होगा। यहां जाकर आपको फार्म-7 सबमिट करना होगा। इस फार्म के साथ आपको डेथ सर्टिफिकेट भी अटैच करना होगा। यह फार्म जमा करने के बाद वोटर लिस्ट से नाम हटा दिया जाएगा।

**पासपोर्ट**

किसी व्यक्ति के मृत्यु हो जाने के बाद उसके पासपोर्ट (  ) को कैंसिल या सरेंडर करने की आवश्यकता नहीं होती है। दरअसल, पासपोर्ट जैसे ही एक्पायर होता है वह ऑटोमैटिकली अमान्य हो जाता है। वैसे एक्सपायर पासपोर्ट का भी इस्तेमाल कई जगह पर वेरिफिकेशन के लिए किया जाता है। ऐसे में आपको इस बात का ध्यान रखना है कि कोई दूसरा व्यक्ति इसका गलत इस्तेमाल न करें।

**ड्राइविंग लाइसेंस**

ड्राइविंग लाइसेंस (Driving License) को लेकर हर राज्य में अलग नियम होते हैं। ऐसे में आपको यह जरूर ध्यान देना चाहिए कि आपके राज्य में ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर क्या नियम है। वैसे केंद्र में ड्राइविंग लाइसेंसे के सरेंडर को लेकर कोई प्रावधान नहीं है। ऐसे में आपको लाइसेंस सरेंडर करने के लिए रिजानल ट्रांसपोर्ट ऑफस (RTO) से संपर्त करना होगा।

आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जिन डॉक्यूमेंट जैसे- आधार कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस को सरेंडर या कैंसिल नहीं करवा सकते हैं तो आपको इन डॉक्यूमेंट्स को ध्यान से रखना चाहिए। इसके अलावा जिन डॉक्यूमेंट्स को सरेंडर किया है उनको भी संभाल कर रखें ताकि भविष्य में जरूरत पड़ने पर यह काम में आ जाएं।

# कहीं जाने की नहीं जरूरत, ई-मेल पर फ्री में मिल जाएगा QR कोड वाला पैन कार्ड; स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस

Pan 2.0 Project को मंजूरी मिलने के बाद कई लोगों के मन में इसको लेकर कन्फ्यूजन हो रही है। कई लोगों का मानना है कि न्यू पैन कार्ड आने के बाद पुराना पैन कार्ड अमान्य हो जाएगा। हालांकि आयकर विभाग ने साफ कर दिया है कि पुराना कार्ड मान्य रहेगा। हम आपको इस आर्टिकल में बताएंगे कि आप कैसे ई-मेल पर न्यू पैन कार्ड पा सकते हैं।

**नई दिल्ली।** इस हफ्ते 25 नवंबर 2024 (सोमवार) को केंद्र सरकार के कैबिनेट बैठक में पैन 2.0 प्रोजेक्ट (PAN 2.0 Project) को मंजूरी मिल गई थी। इस मंजूरी के बाद लोगों के मन में इस प्रोजेक्ट को लेकर कई सवाल आएं। इसके अलावा इस प्रोजेक्ट को लेकर कई फर्जी खबरें भी फैल रही है।

**क्या पुराना पैन कार्ड नहीं रहेगा मान्य**

कई लोगों के मन में सवाल रहता है कि नया पैन कार्ड आने के बाद पुराना पैन कार्ड खराब या अमान्य हो जाएगा। इसको लेकर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बताया कि पुराने पैन कार्ज जिसमें क्यू आर कोड नहीं है वह भी वैध है। इसके अलावा पैन कार्डधारक बिना कोई शुल्क के आसानी से पैन कार्ड में करेक्शन या अपग्रेडेशन करवा सकते हैं। आपको बता दें कि न्यू पैन कार्ड यानी क्यू आर कोड के साथ आने वाले पैन कार्ड के लिए आपको कोई अतिरिक्त शुल्क देने की आवश्यकता नहीं है। पैन कार्ड होल्डर अपने ई-मेल आईडी पर यह कार्ड मंगवा सकते हैं।

हम आपको बताने वाले हैं कि आप कैसे ई-मेल आईडी पर क्यू आर कोड वाला पैन कार्ड मंगवा सकते हैं। आपको बता दें कि इस कार्ड को ई-पैन कार्ड (e-Pan Card) भी कहा जाता है। आइए, इसका प्रोसेस जानते हैं-

**क्या है प्रोसेस**

- सबसे पहले इस लिंक https://www.onlineservices.nsdl.com/paam/requestAndDownloadEPAN.html पर क्लिक करें।
- अब आपको अपना पैन नंबर, आधार नंबर, डेट ऑफ बर्थ भरना होगा।
- इसके बाद एप्लीकेबल बॉक्स पर टिक करें और सबमिट करें।
- अब न्यू स्क्रीन पर आपको शो हो जाएगा। इसमें अपने सभी डिटेल्स को चेक करके सबमिट करें।
- इसके बाद आपको ओटीपी मिलेगा। ओटीपी को दर्ज करें और आगे बढ़ें पर क्लिक करें।
- अब आपको पेमेंट मोड सेलेक्ट करना है और प्रोसीड पर क्लिक करें।
- पेमेंट अमाउंट कन्फर्म करने के बाद आपको कंटिन्यू को सेलेक्ट करना है।
- इसके बाद आपके मेल आईडी पर ई-पैन आ जाएगा।

**पुराने कार्ड से कितना अलग न्यू पैन कार्ड**

केंद्र मंत्री ने अश्विनी वैष्णव ने बताया कि नए पैन कार्ड में क्यू आर कोड होगा। इस कोड में पैनधारक की सभी जरूरी जानकारी शामिल होगा। यह कार्ड पूरी तरह से पेपरलेस और ऑनलाइन प्रणाली पर आधारित है। आपको बता दें कि पैन 2.0 के लागू होने के बाद पैन डाटा वॉल्ट सिस्टम भी लागू हो जाएगा।

# एटीएम जैसे कार्ड से निकलेगा पीएफ का पैसा, जानिए क्या है ईपीएफओ 3.0 और कर्मचारियों को मिलेंगे कौन-कौन से लाभ

परिवहन विशेष न्यूज

ईपीएफओ 3.0 पैन 2.0 प्रोजेक्ट (Pan 2.0 Project) के बाद सरकार ईपीएफओ 3.0 प्रोजेक्ट लागू कर सकती है। इस प्रोजेक्ट के लागू होने के बाद कर्मचारियों की कई परेशानी दूर हो जाएगी। यह प्रोजेक्ट कर्मचारियों को सुविधा देने के लिए शुरू किया गया है। हम आपको इस आर्टिकल में बताएंगे कि ईपीएफओ 3.0 प्रोजेक्ट के तहत कौन-से नियमों में बदलाव हो सकता है।...

**नई दिल्ली।** रिटायरमेंट के बाद ऊी इनकम जारी रहे इसके लिए कर्मचारियों के पास ऑप्शन होता है कि वह जॉब के साथ ईपीएफओ (EPFO) में निवेश करें। ईपीएफओ में निवेश राशि में से एक हिस्सा रिटायरमेंट के बाद पेंशन को तौर पर मिलता है। अब ईपीएफओ के नियमों में बदलाव किया जा सकता है। यह बदलाव हो जाने के बाद से निवेशकों को काफी लाभ होगा।

जी हां, सरकार ईपीएफओ 3.0 (EPFO 3.0) लाने की योजना बना रही है। इसके लागू होने के बाद से ईपीएफओ के नियमों में काफी बदलाव हो जाएगा। इन बदलाव के बाद निवेशकों को प्रोविडेंट फंड (Provident Fund) से निकासी और निवेश करने में और सुविधा मिल जाएगी।

**क्या है ईपीएफओ 3.0? (What is EPFO 3.0)**

सरकार ने हाल ही में पैन 2.0 प्रोजेक्ट (Pan 2.0 Project) का एलान किया था। अब माना जा रहा है कि सरकार ईपीएफओ 3.0 प्रोजेक्ट की घोषणा कर सकती है। इस प्रोजेक्ट में ईपीएफओ को और सुविधाजनक बनाने के लिए सरकार कई नियमों को बदल सकती है। इन नियमों के बदल जाने के बाद निवेशकों की कई परेशानी दूर हो जाएगी। इसका मतलब है कि ईपीएफओ 3.0 से निवेशकों को कई तरह से लाभ मिलेगा।

हम आपके बताने वाले हैं कि ईपीएफओ 3.0 प्रोजेक्ट से कर्मचारियों को किस प्रकार लाभ होगा।

**योगदान राशि में होगी बढ़ोतरी**

वर्तमान में कर्मचारी ईपीएफ (EPF) में केवल अपनी सैलरी 12 फीसदी हिस्सा ही निवेश कर सकते हैं। मीडिया रिपोर्टेस के अनुसार अगर ईपीएफओ 3.0 प्रोजेक्ट लागू होता है तो कर्मचारी अपने योगदान हिस्सेदारी को बढ़ा भी सकता है। इसका मतलब है कि वह 12 फीसदी से ज्यादा का निवेश भी कर सकते हैं।

कई कर्मचारी ईपीएफओ 12 फीसदी से ज्यादा का निवेश करना चाहते थे, पर एक लिमिट होने के कारण वह ऐसा नहीं कर पाते थे। हालांकि, ईपीएफओ 3.0 आने के बाद वह अपने अनुसार निवेश कर सकते हैं।

**एटीएम से निकाल सकेंगे पैसे**

कर्मचारी ने बताया कि उन्हें प्रोविडेंट फंड से आंशिक निकासी करने में दिक्कत होती है। ऐसे में इस परेशानी को दूर करने के लिए ईपीएफओ 3.0 लागू होने के बाद कर्मचारी एटीएम के जरिये प्रोविडेंट फंड से पैसे निकाल सकते हैं। यह नियम लागू होने के बाद पीएफ अकाउंट (PF Account) से पैसे निकालने में आसानी हो जाएगी। माना जा रहा है कि यह नियम मई-जून 2025 से लागू हो सकता है।

# आखिरी मौका आज! बिना भूले जमा करें लाइफ सर्टिफिकेट, वरना रुक जाएगी पेंशन

परिवहन विशेष न्यूज

पेंशनर्स को साल में एक बार लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना होता है। लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने की एक डेडलाइन होती है। इस साल 30 नवंबर जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की आखिरी तारीख है। अगर आपने अभी तक लाइफ सर्टिफिकेट जमा नहीं किया है तो हम आपको ऑनलाइन लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने का प्रोसेस और लाइफ सर्टिफिकेट के स्टेटस चेक करने का तरीका बताएंगे।

**नई दिल्ली।** लाइफ सर्टिफिकेट (Life Certificate) जमा करने की आखिरी तारीख आ गई है। जी हां, लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने की डेडलाइन 30 नवंबर 2024 यानी आज है। अगर आपने अभी तक लाइफ सर्टिफिकेट जमा नहीं किया है तो आपको आज यह काम निपटा लेना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपकी पेंशन रुक सकती है।

हम आपको बताएंगे कि आप किन तरीकों से लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं।

**बैंक जाकर जमा करें लाइफ सर्टिफिकेट**

पेंशनर्स बैंक जाकर लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि शनिवार के कारण बैंक बंद है तो बता दें कि रविवार और केवल दूसरे-चौथे शनिवार को बैंक की छुट्टी रहती है। आज नवंबर महीना का पांचवां शनिवार है। इसका मतलब है कि आज बैंक खुले रहेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के हॉलिडे लिस्ट (Bank Holiday List) के अनुसार आज किसी त्योहार के कारण बैंक बंद नहीं है।

**ऑनलाइन कैसे सबमिट करें लाइफ सर्टिफिकेट**

आप ऑनलाइन भी लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं। ऑनलाइन लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने के लिए आपको Google Play Store से 'आधार फेस आरडी' ऐप डाउनलोड करने होंगे। लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने का प्रोसेस (Process to Submit Life Certificate) यह रहा-

- अपने स्मार्टफोन में 'आधार फेस आरडी' को ओपन करें।
- अब ऐप में 'ऑपरेटर ऑथेंटिकेशन' के ऑप्शन पर क्लिक करना चाहिए।
- इसके बाद आप आधार नंबर, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दर्ज करें।
- अब आधार बॉक्स को टिक करें, फिर सबमिट पर क्लिक करें।
- इसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा। इस ओटीपी को दर्ज करें।
- अब आपको फेस स्कैन करने के लिए अपने मोबाइल को कैमरा एक्सेस के लिए परमिशन देना होगा।
- ओटीपी वेरिफिकेशन के बाद आपको फेस स्कैन करना होगा।
- सक्सेसफुल फेस स्कैन हो जाने के बाद आपको सबमिट पर क्लिक करना होगा।

आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपके फोन में लेटेस्ट वर्जन (3.6.3) का आधार फेस आरडी ऐप इंस्टॉल होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो आपको लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करने में दिक्कत आ सकती है।

**कही रिजेक्ट को नहीं हो गया लाइफ सर्टिफिकेट**

अगर आपने लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर दिया है तो आपको एक बार लाइफप सर्टिफिकेट का स्टेटस (Life Certificate Status) चेक करना चाहिए। इस स्टेटस से आपको पता चल जाएगा कि आपका लाइफ सर्टिफिकेट रिजेक्ट तो नहीं हो गया है।

- स्टेटस चेक करने के लिए आप https://jeevanpramaan.gov.in/ppouser/login पर जाएं।
- अब अपना आधार नंबर की मदद से लॉग-इन करें।
- लॉग-इन करने के बाद आपको स्क्रीन पर स्टेटस शो हो जाएगा।

अगर आपका लाइफ सर्टिफिकेट रिजेक्ट हो जाता है तो आपका तुरंत पेंशन जारी करने वाले एजेंसी से संपर्क करना चाहिए।

**नहीं जमा किया सर्टिफिकेट तो क्या होगा**

अब सवाल आता है कि अगर लाइफ सर्टिफिकेट जमा नहीं किया जाता है तो उससे क्या होगा। नियमों के अनुसार पेंशनर्स को साल में एक बार लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना होता है। अगर पेंशनर्स समयसीमा के भीतर यह जमा नहीं करते हैं तो पेंशन रुक सकती है।

लाइफ सर्टिफिकेट एक डिजिटल प्रमाण पत्र है। इससे पता चल जाता है कि पेंशनर्स जीवित है और उसे ही पेंशन का लाभ मिलता है।

# मौजूदा वित्त वर्ष में अब तक कितना है राजकोषीय घाटा, क्यों घट रहा है विदेशी मुद्रा भंडार?

परिवहन विशेष न्यूज

सरकार ने आम बजट में चालू वित्त वर्ष 2024-25 में राजकोषीय घाटे को सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 4.9 प्रतिशत तक लाने का अनुमान लगाया है। इस तरह सरकार का लक्ष्य चालू वित्त वर्ष के दौरान राजकोषीय घाटे को 1613312 करोड़ रुपये पर सीमित रखना है। वित्त वर्ष 2024-25 के पहले सात महीनों के लिए शुद्ध कर राजस्व लगभग 13 लाख करोड़ रुपये था।

**नई दिल्ली।** केंद्र का राजकोषीय घाटा वित्त वर्ष 2024-25 के पहले सात महीनों में पूरे साल के लक्ष्य के 46.5 प्रतिशत तक पहुंच गया। लेखा महानियंत्रक (सीजीए) के आंकड़ों के अनुसार अप्रैल-अक्टूबर की अवधि के दौरान राजकोषीय घाटा 7,50,824 करोड़ रुपये था। सरकार के व्यय और राजस्व के बीच के अंतर को राजकोषीय घाटा कहते हैं। वित्त वर्ष 2023-24 की समान अवधि में घाटा बजट अनुमान का 45 प्रतिशत था।

सरकार ने आम बजट में चालू वित्त वर्ष 2024-25 में राजकोषीय घाटे को सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 4.9 प्रतिशत तक लाने का अनुमान लगाया है। इस तरह, सरकार का लक्ष्य चालू वित्त वर्ष के दौरान राजकोषीय घाटे को 16,13,312 करोड़ रुपये पर सीमित रखना है। वित्त वर्ष 2024-25 के पहले सात महीनों के लिए केंद्र सरकार के राजस्व-व्यय के आंकड़ों के मुताबिक शुद्ध कर राजस्व लगभग 13 लाख करोड़ रुपये या चालू वित्त वर्ष के बजट अनुमान का 50.5 प्रतिशत था।

इससे पिछले वित्त वर्ष के लिए सितंबर 2023 के अंत में शुद्ध कर राजस्व संग्रह 55.9 प्रतिशत था। इस साल अक्टूबर तक सात महीनों में केंद्र सरकार का कुल व्यय 24.7 लाख करोड़ रुपये या बजट अनुमान का 51.3 प्रतिशत रहा। एक साल पहले की इसी अवधि में व्यय बजट अनुमान का 53.2 प्रतिशत था। कुल व्यय में 20 लाख करोड़ रुपये राजस्व खाते में और 4.66 लाख करोड़ रुपये पूंजी खाते में थे।

**1.31 अरब डॉलर घटा विदेशी मुद्रा भंडार**

22 नवंबर को समाप्त सप्ताह में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 1.31 अरब डालर घटकर 656.582 अरब डॉलर रह गया। 15 नवंबर को समाप्त सप्ताह में विदेशी मुद्रा भंडार 17.761 अरब डॉलर घटकर 657.892 अरब डालर के स्तर पर आ गया था। सितंबर के अंत में विदेशी मुद्रा भंडार 704.885 अरब डालर के सर्वकालिक उच्चस्तर पर था। मुद्रा भंडार पिछले कई सप्ताह से घट रहा है।

इस दौरान विदेशी मुद्रा आस्तियां 3.043 अरब डॉलर घटकर 566.791 अरब डालर रह गईं। डॉलर के संदर्भ में विदेशी मुद्रा आस्तियों में भंडार में रखे गए यूरो, पाउंड और येन जैसी गैर अमेरिकी मुद्राओं की वृद्धि और उनका मूल्यह्रास शामिल होता है।

आरबीआई ने कहा कि इस दौरान स्वर्ण भंडार 1.828 अरब डॉलर बढ़कर 67.573 अरब डॉलर हो गया। विशेष आहरण अधिकार (एसडीआर) 7.9 करोड़ डॉलर घटकर 17.985 अरब डालर रह गए। आईएमएफ के साथ भारत की आरक्षित स्थिति भी 1.5 करोड़ डॉलर घटकर 4.232 अरब डॉलर रह गई।

# प्रौद्योगिकी के नए युग में बच्चों पर पढ़ने वाले मानसिक शारीरिक व भावनात्मक प्रभावों को रेखांकित करना ज़रूरी

एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानी

**गोंदिया** - विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत में संसद के शीतकालीन सत्र 2024 की शुरुआत 25 नवंबर 2024 से हुई जिसमें उद्योगपति मामले में हंगामें के चलते 29 नवंबर 2024 तक यानें चार दिन में मात्र 40 मिनट ही कार्यवाही चली औसतन प्रतिदिन 10 मिनट तक कार्यवाही चली, अब दोनों सदनों की कार्यवाही सोमवार 2 दिसंबर 2024 तक स्थगित कर दी गई है, इस बीच राज्यसभा में सभापति ने कहा, यह करनी लोकहित केंद्रित नहीं हैं, ये लोगों में पद के बिल्कुल प्रतिकूल हैं, हम अप्रासंगिक होते जा रहे हैं और लोग हमारा उपहास कर रहे हैं, हम वस्तुतः हंसी का पात्र बन गए हैं, इसलिए वे राज्यसभा सांसदों से कृपा कर सदन के कामकाज में सुचारू रूप से भाग लेने की अपील करते हैं, सदन के सामान्य कामकाज में व्यवधान उत्पन्न किए जाने से उन्हें गहरी पीड़ा और दुख हुआ है। हम बहुत खराब मिसाल कायम कर रहे हैं। हम देश के लोगों का अपमान कर रहे हैं और उम्मीदों पर खरे नहीं उतर रहे हैं, क्योंकि जनता से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दे बिल व सवाल बाधित हो रहे हैं आज यह विषय हम इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि 29 नवंबर 2024 को राज्यसभा में ऑनलाइन गेमिंग से बच्चों पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव से जुड़े एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर इलेक्ट्रॉनिक व सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री ने सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की लिखित जानकारी दी (बता दें वर्तमान प्रौद्योगिकी और डिजिटल युग में अत्यंत तीव्रता से हम एक नए भारत की ओर बढ़ रहे हैं, हमारे देश पर हमें गर्व है लगभग हर क्षेत्र में मानवीय शारीरिक श्रम को आधुनिक प्रौद्योगिकी की सहायता से कंप्यूटर, रोबोट, विभिन्न एप्स की भाषा में तब्दील कर घंटों का काम सेकंडों में करने की राह तेजी पकड़ती जा रही है, और हम तेजी से एक नए भारत की ओर बढ़ रहे हैं इसे देखकर ऐसा लग रहा है कि हम विज़न 2047 को अपने टारगेट के कई साल पहले ही प्राप्त कर लेंगे। परंतु इससे हमारे भविष्य के नेतृत्व बच्चों पर काफी दुष्प्रभाव पड़ने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।

साथियों बात अगर हम तीव्र गति से प्रौद्योगिकी विकास की करें तो बड़े बुजुर्गों का कहना है रजाई जितनी पानी में भीगेगी उतनी ही भारी होती जाएगी बिल्कुल ठीक,हमें बड़े बुजुर्गों द्वारा कहे एक एक शब्द सत्य साबित होते हैं यही बात, हमें इस आधुनिक प्रौद्योगिकी में भी देखनी होगी कि जितनी हम सुविधाएं प्राप्त कर रहे हैं उनके कुछ साइड इफेक्टस भी होते हैं, जिनकी अत्यंत सूक्ष्मता से हमें सावधानी भी बरतनी होगी।

साथियों बात अगर हम इस नई प्रौद्योगिकी के बच्चों पर प्रभाव की करें तो आज के युग में हम देख रहे हैं कि बच्चों के हाथ में मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर की आदत तीव्रता से बढ़ गई है क्योंकि महामारी के प्रकोप से लॉकडाउन और स्कूल बंद के कारण उसे समय की आदतों से ऑनलाइन क्लासेस से इसकी जरूरत और आदतें दोनों बढ़ गई है जिसका खाली समय में प्रयोग में अक्सर ऑनलाइन गेमिंग, अन्य गेम, अश्लीलता के कुछ अंश इत्यादि का क्रेज बढ़ गया है जिसकी ओर हम सभी अभिभावकों माता-पिता, शिक्षकों को इस दिशा में तेजी से ध्यान देखकर अतिकठोर सावधानी बरतना होगा ताकि हमारे कल के भविष्य बच्चों को आत्म संयमता का मंत्र देकर हम उनका भविष्य सुरक्षित कर सकें।

साथियों बात अगर हम ऑनलाइन गेमिंग में सुरक्षा के लिए संसदीय शीतकालीन सत्र में भारत सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का लिखित उत्तर पेश करने की करें तो सरकार ऑनलाइन गेमिंग से होने वाले खतरों और लत जैसे संभावित नुकसानों से अवगत है। भारत सरकार की नीतियों का उद्देश्य अपने उपयोगकर्ताओं के लिए सुरक्षित, विश्वसनीय और जवाबदेह इंटरनेट सुनिश्चित करना है। ऑनलाइन गेम की लत जैसी विभिन्न सामाजिक आर्थिक चिंताओं को दूर करने के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने संबंधित हितधारकों के साथ व्यापक परामर्श के बाद, आईटी अधिनियम के तहत दी गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यस्थ दिशा-निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 (आईटी नियम, 2021) को अधिसूचित किया है। आईटी नियम, 2021 ने सोशल मीडिया मध्यस्थों सहित विभिन्न मध्यस्थों पर उस सूचना के संबंध में विशिष्ट सावधानी बरतने के दायित्व डाले हैं, जिसे प्लेटफ़ॉर्म पर होस्ट, प्रदर्शित, अपलोड, प्रकाशित, प्रसारित, संग्रहीत या साझा नहीं किया जाना है। मध्यस्थों से अपेक्षा की जाती है कि वे किसी भी ऐसी सूचना को होस्ट, संग्रहीत या प्रकाशित न करें जो वर्तमान में लागू किसी भी कानून का उल्लंघन करती हो। मध्यस्थों को अपनी जवाबदेही सुनिश्चित करने की आवश्यकता होती है, जिसमें आईटी नियम, 2021 के तहत वर्गीकृत गैरकानूनी सूचना को हटाने की दिशा में उनकी त्वरित कार्रवाई या किसी भी ऐसी सूचना के खिलाफ प्राप्त शिकायतों के आधार पर कार्रवाई शामिल है, जो अन्य बातों के अलावा, बच्चों के लिए हानिकारक है या जो मनी लॉन्ड्रिंग या जुए से संबंधित या प्रोत्साहित करती है। इसके अलावा, शिक्षा मंत्रालय ने 27 सितंबर, 2021 को ऑनलाइन गेमिंग के नुकसानों पर काबू पाने के लिए अभिभावकों और शिक्षकों के लिए एक एडवाइजरी जारी की है। इसके बाद, शिक्षा मंत्रालय ने 10 दिसंबर, 2021 को बच्चों के सुरक्षित ऑनलाइन गेमिंग पर अभिभावकों और शिक्षकों को एक एडवाइजरी जारी की है। एडवाइजरी में संकेत दिया गया है किऑनलाइन गेम खेलने से गंभीर गेमिंग की लत लग जाती है जिसे गेमिंग डिसऑर्डर माना जाता है। इसने आगे चेतावनी दी है कि बिना किसी प्रतिबंध और आत्म-सीमा के ऑनलाइन गेम खेलने से कई खिलाड़ी आदी हो जाते हैं और अंततः गेमिंग डिसऑर्डर का निदान किया जाता है अभिभावकों और शिक्षकों को एडवाइजरी को व्यापक रूप से प्रसारित करने और बच्चों को मानसिक और शारीरिक तनाव से जुड़े सभी ऑनलाइन गेमिंग नुकसानों पर काबू पाने में प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई के लिए उन्हें शिक्षित करने की सिफारिश की गई है।इसके अतिरिक्त, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने 4 दिसंबर, 2020 को सभी निजी सैटेलाइट टेलीविजन चैनलों को ऑनलाइन गेम्स, फैंटेसी स्पोर्ट्स आदि पर विज्ञापन के बारे में एक एडवाइजरी भी जारी की है, जिसमें सभी प्रसारकों को सलाह दी गई है कि भारतीय विज्ञापन मानक परिषद द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन किया जाए और टेलीविजन पर प्रसारित विज्ञापनों में भी उन्हीं का पालन किया जाए। दिशा- निर्देशों का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है (1) किसी भी गेमिंग विज्ञापन में 18 वर्ष से कम आयु के किसी व्यक्ति को नहीं दिखाया जाना चाहिए। (2) ऐसे प्रत्येक गेमिंग विज्ञापन में प्रिंट/स्टेटिक तथा ऑडियो/वीडियो फॉर्म में एएससीआई कोड के अनुरूप डिस्कलेमर होना चाहिए, जिसमें यह दर्शाया गया हो कि इस गेम में वित्तीय जोखिम शामिल है तथा यह व्यसनकारी हो सकता है। (3) विज्ञापनों में गेम को वैकल्पिक रोजगार के रूप में प्रस्तुत नहीं किया जाना चाहिए। (4) उन्हें यह भी नहीं दर्शाना चाहिए कि गेमिंग गतिविधि करने वाला व्यक्ति किसी भी तरह से सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने 21 मार्च, 2024 को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सहित मीडिया को एक एडवाइजरी भी जारी की है, जिसमें ऑनलाइन सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म और/या इन प्लेटफॉर्म को छद्म तरीके से दर्शाने वाले किसी भी ऐसे उत्पाद/सेवा के विज्ञापनों को प्रकाशित या प्रसारित करने से परहेज करने को कहा गया है। ऑनलाइन विज्ञापन बिचौलियों को भी सलाह दी गई है कि वे ऐसे विज्ञापनों को भारतीय दर्शकों को ध्यान में रखकर न दिखाएं।गृह मंत्रालय ने साइबर अपराधों से व्यापक और समन्वित तरीके से निपटने के लिए कानून प्रवर्तन एजेंसियों के लिए एक ढांचा और पारिस्थितिकी तंत्र प्रदान करने के लिए भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र की स्थापना की है। एमएचए ने सभी प्रकार के साइबर अपराधों की रिपोर्ट करने में जनता को सक्षम बनाने के लिए राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल भी लॉन्च किया है।इस पोर्टल पर रिपोर्ट की गई साइबर अपराध की घटनाओं को कानून के प्रावधानों के अनुसार आगे की कार्यवाही के लिए संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की कानून प्रवर्तन एजेंसी को भेजा जाता है। पोर्टल में महिलाओं/बच्चों से संबंधित अपराधों और वित्तीय धोखाधड़ी के खिलाफ शिकायत दर्ज करने के लिए अलग-अलग तंत्र हैं।ऑनलाइन साइबर शिकायत दर्ज करने में सहायता प्राप्त करने के लिए एक टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर 1930 चालू किया गया है।यह जानकारी इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री श्री जितिन प्रसाद ने आज राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में दी।

अतः अगर हम उपरोक्त पूरे विवरण का अध्ययन कर उसका विश्लेषण करें तो हम पाएंगे कि ऑनलाइन गेमिंग से बच्चों पर दुष्प्रभाव-मामले की संसदीय शीतकालीन सत्र में गूंज-भारत सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का लिखित उत्तर पेशप्रौद्योगिकी के नए युग में बच्चों पर पढ़ने वाले मानसिक शारीरिक व भावनात्मक प्रभावों कोरेखांकित करना ज़रूरी।शिक्षा मंत्रालय द्वारा ऑनलाइन गेमिंग पर शिक्षकों वअभिभावकों के लिए जारी एडवाइजरी 2021व सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2021 को सख़्ती से क्रियान्वयन करना समय की मांग है।

# खंडहर पड़े मोहल्ला क्लीनिक की झूठ की रेवड़ी की सच्चाई जनता के सामने है, स्वास्थ्य मॉडल भी ढह गया है-देवेंद्र यादव

सुषमा रानी

**नई दिल्ली।** दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेन्द्र यादव ने दिल्ली न्याय यात्रा के दौरान आज अरविन्द केजरीवाल के स्वास्थ्य मॉडल की सच्चाई को जानने के लिए मौहल्ला क्लीनिक में गए, वहां लोगों से मिले। लोगों ने अपनी परेशानी सांझा की, बताया कि मौहल्ला क्लीनिक में न डॉक्टर है, न दवाइयां है, न टेस्ट होते है और मौहल्ला क्लीनिक के इर्द गिर्द गंदगी के ढेर लगे है। उन्होंने कहा कि दिल्ली की स्वास्थ्य व्यवस्था इतनी चरमरा चुकी है कि जब किसी गरीब परिवार में कोई बीमार होकर सरकारी अस्पताल जाता है, उसका इलाज न करके उसे प्राईवेट अस्पताल रेफर कर दिया जाता है, जहां इलाज कराने के लिए उसके पास पैसा नही है। केजरीवाल के शासन में गरीब चौतरफा मर रहा है। उन्होंने बताया कि केजरीवाल दिल्ली में जो झूठ की रेवड़ी दे रहे है उसकी सच्चाई लोगों के सामने आ चुकी है लोगों को मौहल्ला क्लीनिक की सच्चाई पता चल गई है। 200 टेस्ट मुफ्त करने का वादा था, पूरा नही किया। उन्होंने कहा कि केजरीवाल सरकार बताए कि 1000 मोहल्ला क्लीनिक खोलने के वादे किया था, लेकिन आज आधे मोहल्ला क्लीनिक भी नही शुरु किए है जो सुचारु रुप से कार्य तक नही कर रहे है।



यादव ने कहा कि केजरीवाल सरकार ने कांग्रेस शासनकाल में सुचारु रुप से चल रही 1396 डिस्पेंसरियों में से अधिकतर बंद करके मौहल्ला क्लीनिक पर काम किया जबकि इन डिस्पेंसरियों में सरकारी कर्मचारी कार्यरत थे और मौहल्ला क्लीनिक आम आदमी पार्टी के वालियंटरों के घरों में परिचालन हो रहा है, इनमें असुविधाओं के कारण दिल्ली के गरीब लोग परेशान है। कोविड महामारी के दौरान केजरीवाल सरकार की स्वास्थ्य व्यवस्था का मॉडल की पोल पहले खुल चुकी है जब लोगों सांसों के लिए तरस रहे थे और दिल्ली कोविड से मरने वालों की गिनती में सबसे उपर रहा।

उन्होंने कहा कि मुफ्त की रेवड़ी स्वास्थ्य व्यवस्था की सच्चाई लोग जानते है। क्योंकि दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में डाक्टरों को कुछ सीमित दवाएं लिखने के लिए मजबूर किया जा रहा है और वो भी अस्पताल में उपलब्ध नही होती। ऑपरेशन होना बंद हो गए है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस शासन काल में अस्पतालों में 19571 बेड जोड़े गए जबकि केजरीवाल सरकार के शासन काल में केवल 9590 बेड जोड़े गए। केजरीवाल सरकार बताए कि दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में मरीजों के लिए 30,000 अतिरिक्त बेड मुहैया कराने के वादे का क्या हुआ?

# अप्रसांगिकता की ओर बढ़ती भारतीय संसद

(राकेश अचल -विभूति फीचर्स)

भारतीय लोकतंत्र सबसे पुराना है।इसकी रिवायतें भी पुरानी हैं लेकिन इसी लोकतंत्र की रक्षा के लिए बनी हमारी संसद आजकल चल नहीं पा रही । लोकसभा अध्यक्ष हों या राज्य सभा अध्यक्ष वे अपने-अपने सदनों को सुचारु रूप से चलाने में नाकाम साबित हुए है ।राज्यसभा के सभापति को तो यहां तक कहना पड़ रहा है कि हम अप्रसांगिकता की ओर बढ़ने लगे हैं। सरकार और विपक्ष के बीच का गतिरोध टूटने का नाम ही नहीं ले रहा है। देश की राजधानी दिल्ली प्रदूषण की चपेट में है और देश की संसद हंगामे में डूबी है। संसद को हंगामे से उबारने की कोई गंभीर कोशिश नजर नहीं आ रही। संसद को देखकर लगता है कि -'नौ दिन चले अढ़ाई कोस' वाली कहावत शायद इसके लिए ही बनी है।

इस बार संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत 25 नवंबर को हुई थी। दोनों सदनों में 4 दिन में सदन की कार्यवाही सिर्फ 40 मिनट चली ।हर दिन औसतन दोनों सदन (लोकसभा और राज्यसभा) में करीब 10-10 मिनट तक कामकाज हुआ। अब संसद 2 दिसंबर के बाद ही बैठेगी। लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष ने अदाणी और संभल का मुद्दा उठाया। विपक्षी सांसद कार्यवाही के दौरान लगातार हंगामा करते रहे।स्पीकर ने कई बार उन्हें बिठाने की कोशिश की, मगर विपक्ष शांत नहीं हुआ।

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा- सहमति-असहमति लोकतंत्र की ताकत है।मैं आशा करता हूं सभी सदस्य सदन को चलने देंगे। देश की जनता संसद के बारे में चिंता व्यक्त कर रही है। सदन सबका है, देश चाहता है संसद चले। लेकिन संसद नहीं चली और लोकसभा के साथ ही राज्यसभा की कार्यवाही सोमवार 2 दिसंबर तक स्थगित कर दी गई।बिरला साहब ने सदन चलाने कि लिए क्या कोशिश की ये किसी को नहीं पता ,क्योंकि उन्होंने शायद कोई कोशिश की होती तो उसका कुछ न कुछ नतीजा जरूर निकलता। वे सदन चलने से ज्यादा सदन की कार्रवाई स्थगित करने में दक्ष दिखाई देते हैं। यही बात राज्य सभा में माननीय धनकड़ साहब पर लागू होती है।



मुझे लगता है कि संसद हंगामे की वजह से नहीं बल्कि सत्तापक्ष और विपक्ष के आपसी अहंकार की वजह से नहीं चल रही ।सत्तापक्ष संसद को चलाना ही नहीं चाहता,यदि सत्तापक्ष की मंशा संसद को चलाने की होती तो सत्तापक्ष दरियादिली दिखाता और विपक्ष जिन मुद्दों पर बहस की मांग कर रहा है,उन सभी मुद्दों पर बहस करता,लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। विपक्ष भी सत्ता पक्ष के सामने अड़कर खड़ा हुआ है। सदन चलाने के लिए जिम्मेदार लोग कायदे-क़ानून से ज्यादा अपनी प्रतिष्ठा को लेकर अड़े हुए हैं, अन्यथा सदन का संचालन करने वाले और संसद के माननीय सदस्य चाहें तो सदन चल सकता है।

दुर्भाग्य ये है कि संसद का संचालन पीठासीन अधिकारियों के विवेक से नहीं बल्कि निर्देशों से चलाने की कोशिश की जा रही है ,और यही समस्या की असल जड़ है। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को अपनी हठधर्मी आज नहीं तो कल छोड़ना पड़ेगी।सवाल ये है कि विपक्ष द्वारा उठाये जाने वाले मुद्दों पर बातचीत करने से कौनसा पहाड़ टूटने वाला है? नेताओं को चाहे वे सत्ता पक्ष के हों या विपक्ष के ,जो सदन में कहना है वो सब वे आम सभाओं में कह रहे है। नेताओं का ये आचरण उनकी अहमन्यता का प्रतीक है । वे सदन के चलते विवादित मुद्दों पर सदन के बाहर बोलकर सदन की अवमानना कर रहे हैं,लेकिन उन्हें समझाये कौन ? सदन के पीठासीन अधिकारियों में से किसी में इतना नैतिक या कानूनी साहस नहीं है कि वो माननीय सदस्यों को सदन में विवादित मुद्दों पर बोलने के लिए कहे ।सदन में स्पीकर के लिए चाहे प्रधानमंत्री हो या एक सामान्य सांसद सब बराबर हैं। हैरानी की बात ये है कि संसद को लेकर सभी पक्षों का आचरण एक जैसा है । इधर संसद स्थगित होती है उधर प्रधानमंत्री हों या विपक्ष के नेता आम सभाएं करने निकल पड़ते हैं और उन्हें जो बातें सदन में करना चाहिए वे ही बातें वे आमसभाओं में करते हैं । प्रधानमंत्री जी भुवनेश्वर में गरज रहे हैं तो राहुल गांधी वायनाड में।

राज्यसभा में विपक्षी सांसदों की लगातार नारेबाजी के बीच सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा, इसे जायज नहीं ठहराया जा सकता। हम बहुत खराब मिसाल कायम कर रहे हैं। हमारे काम जनता-केंद्रित नहीं हैं।हम अप्रासंगिकता की ओर बढ़ रहे हैं।गनीमत ये है कि अभी धनकड़ साहब केवल सदन की कार्रवाई स्थगित कर रहे है। उन्होंने किसी सदस्य को डांटा-फटकारा या निलंबित नहीं किया है ,अन्यथा वे जब चाहे तब ऐसा कर सकते हैं। यही हाल लोकसभा अध्यक्ष माननीय ओम बिरला साहब का है। वे सदस्यों की आँखों में आँखें डालकर बात करने के बजाय दिशा निर्देशों के लिए इधर उधर ताकते नजर आते हैं।

आपको बता दें कि संसद की कार्रवाई पर प्रति घंटे डेढ़ करोड़ रुपया खर्च होता है ,लेकिन ये पैसा जनधन है इसलिए किसी को इसकी बर्बादी की फ़िक्र नहीं है।संसद के सामने शीतकालीन सत्र के दौरान कुल 16 विधेयक पेश किए जाने हैं।इनमें से 11 विधेयक चर्चा के लिए रखे जाएंगे। जबकि 5 कानून बनने के लिए मंजूरी के लिए रखे जाएंगे। ' वन नेशन, वन इलेक्शन ' के लिए प्रस्तावित विधेयकों का सेट अभी सूची का हिस्सा नहीं है, हालांकि कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया है कि सरकार इसे इसी सत्र में ला सकती है। लोकसभा से पारित एक अतिरिक्त विधेयक भारतीय वायुयान विधेयक राज्यसभा में मंजूरी के लिए लंबित है लेकिन ये सब काम तो तब निबटे जब सदन में हंगामा बंद हो। सरकार तो अंतोगत्वा ये सब काम सदन में आखरी दिन ध्वनिमत से करा ही लेगी लेकिन एक स्वस्थ लोकतंत्र में ऐसा होना संसदीय मर्यादाओं और स्वस्थ लोकतंत्र के लिए किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं कहा जा सकता।

# एशिया में चीन के सैन्य प्रभुत्व से उत्पन्न चुनौतियाँ

भारत अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करते हुए और क्षेत्रीय स्थिरता को बढ़ावा देते हुए एशिया में चीन के सैन्य प्रभुत्व का जवाब कैसे दे सकता है। जैसे-जैसे वैश्विक शक्ति की गतिशीलता बदलती है, भारत जैसे देशों को क्षेत्रीय स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए राजनयिक और रक्षात्मक उपायों में संलग्न रहना जारी रखना चाहिए। रणनीतिक साझेदारी, रक्षा क्षमताओं के आधुनिकीकरण और राजनयिक जुड़ाव के सही संयोजन के साथ, भारत शांतिपूर्ण और स्थिर एशिया में योगदान करते हुए अपने हितों को सुरक्षित कर सकता है।

-प्रियंका सौरभ



एशिया में चीन के बढ़ते सैन्य प्रभुत्व ने क्षेत्रीय सुरक्षा परिदृश्य को काफ़ी बदल दिया है, जिससे उसके पड़ोसियों में चिंता पैदा हो गई है। उन्नत सैन्य क्षमताओं, रणनीतिक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं और मुखर क्षेत्रीय दावों के साथ, चीन ने पूरे हिंद-प्रशांत क्षेत्र में अपना प्रभाव बढ़ाया है। इसने क्षेत्रीय स्थिरता के लिए गंभीर चुनौतियाँ खड़ी कर दी हैं, जिससे भारत जैसे देशों को अपने हितों की रक्षा करने और शांति बनाए रखने के लिए रणनीतिक प्रतिक्रिया की आवश्यकता है।

एशिया में चीन के सैन्य प्रभुत्व द्वारा उत्पन्न चुनौतियाँ क्षेत्रीय विवाद और विस्तारवाद हैं। एशिया में चीन के सैन्य प्रभुत्व से उत्पन्न चुनौतियाँ दक्षिण चीन सागर और भारत-चीन सीमा पर चीन के क्षेत्रीय दावे क्षेत्रीय स्थिरता को चुनौती देते हैं, जिससे अक्सर सैन्य टकराव होते रहते हैं। दक्षिण चीन सागर में चीन के नाइन-डैश लाइन के दावे के कारण कई दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ विवाद पैदा हो गया है, जिससे नेविगेशन की स्वतंत्रता और क्षेत्रीय शांति कमजोर हो गई है। चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (बीआरआई) ने प्रमुख क्षेत्रों में सैन्य संपत्तियों के निर्माण की अनुमति दी है, जिससे पड़ोसी देशों के पास उसकी सैन्य उपस्थिति बढ़ गई है। जिबूती में एक सैन्य अड्डे और श्रीलंका और पाकिस्तान में रणनीतिक बंदरगाहों के निर्माण से हिंद महासागर क्षेत्र में चीन का प्रभाव बढ़ता है, जिससे भारत की सुरक्षा चिंताएँ प्रभावित होती हैं। चीन का नौसैनिक विस्तार और सैन्य आधुनिकीकरण इंडो-पैसिफिक में शक्ति संतुलन के लिए सीधी चुनौती है, जहाँ जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत जैसे देश चिंतित हैं। इंडो-पैसिफिक में चीन की बढ़ती नौसैनिक उपस्थिति और ताइवान स्ट्रेट और मलक्का स्ट्रेट के पास लगातार सैन्य अभ्यास ने क्षेत्रीय सुरक्षा के बारे में चिंता बढ़ा दी है। चीन की सैन्य ताकत अक्सर उसके आर्थिक प्रभाव के साथ-साथ चलती है, जिसका उपयोग वह क्षेत्रीय प्रभुत्व को सुरक्षित करने और छोटे देशों की रणनीतिक स्वायत्तता को सीमित करने के लिए करता है। श्रीलंका में चीन की ऋण-जाल कूटनीति, हिंद महासागर में इसकी सैन्य उपस्थिति के साथ मिलकर, इस बात पर प्रकाश डालती है कि कैसे आर्थिक निर्भरता सैन्य उत्तोलन में तब्दील हो सकती है। चीन का सैन्य निर्माण उसके पड़ोसियों के लिए एक निवारक के रूप में कार्य करता है, जिससे वे चीनी आक्रामकता का सामना करने में झिझकते हैं, जो क्षेत्रीय सुरक्षा को बाधित कर सकता है। भारत और चीन के बीच 2017 का डोकलाम गतिरोध क्षेत्रीय दावों पर ज़ोर देने के लिए चीन द्वारा सैन्य मुद्रा का उपयोग करने का उदाहरण है, जिससे अपने क्षेत्रीय पड़ोसियों के साथ भारत के सम्बंधों पर असर पड़ा।

चीन के सैन्य प्रभुत्व के प्रति भारत की प्रतिक्रिया राष्ट्रीय हितों की रक्षा करते हुए रणनीतिक गठबंधनों को मज़बूत कर रही है। भारत ने विशेष रूप से भारत-प्रशांत क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव का मुकाबला करने के लिए रणनीतिक गठबंधन बनाने पर ध्यान केंद्रित किया है। अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ क्वाड (चतुर्भुज सुरक्षा वार्ता) में भारत की भागीदारी सैन्य सहयोग को मज़बूत करती है और चीन के मुखर व्यवहार के लिए सामूहिक प्रतिक्रिया सुनिश्चित करती है। भारत को चीनी आक्रामकता को प्रभावी ढंग से रोकने के लिए अपनी रक्षा क्षमताओं को बढ़ाना चाहिए, खासकर साइबर युद्ध, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और मिसाइल रक्षा जैसे क्षेत्रों में। रूस से भारत की एस-400 मिसाइल प्रणाली की खरीद और ब्रह्मोस मिसाइल विकास चीन की बढ़ती मिसाइल और वायु शक्ति के खिलाफ इसकी रक्षा को मज़बूत करता है। आर्थिक आत्मनिर्भरता और रणनीतिक साझेदारी भारत को राष्ट्रीय सुरक्षा को बढ़ावा देने, चीन के आर्थिक उत्तोलन के प्रति अपनी भेद्यता को कम करने में मदद कर सकती है। आत्मनिर्भर भारत पहल भारत को महत्त्वपूर्ण रक्षा प्रौद्योगिकियों के लिए चीन पर निर्भरता कम करते हुए स्वदेशी रक्षा उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित करती है। हिंद महासागर में चीन की बढ़ती नौसैनिक उपस्थिति का मुकाबला करने के लिए अपनी समुद्री सीमाओं को सुरक्षित करने और नौसैनिक क्षमताओं को बढ़ाने पर भारत का ध्यान महत्त्वपूर्ण है। भारत ने चीन के प्रभाव का मुकाबला करने के लिए हिंद महासागर और दक्षिण चीन सागर में नेविगेशन की स्वतंत्रता पर ध्यान केंद्रित करते हुए जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के साथ नौसैनिक सहयोग को मज़बूत किया है। भारत को दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ सम्बंधों को मज़बूत करने के लिए सॉफ्ट पावर का उपयोग करते हुए चीन की विस्तारवादी नीतियों के खिलाफ क्षेत्रीय सहमति बनाने के लिए राजनयिक प्रयासों में भी शामिल होना चाहिए। आसियान मंचों पर भारत की सक्रिय भूमिका और इसकी एक्ट ईस्ट नीति दक्षिण पूर्व एशिया के साथ घनिष्ठ सम्बंधों को बढ़ावा देती है, जिससे क्षेत्र में चीन के आर्थिक और सैन्य प्रभुत्व का मुकाबला होता है।

चीन के सैन्य प्रभुत्व के प्रति भारत की प्रतिक्रिया क्षेत्रीय स्थिरता को बढ़ावा देते हुए बहुपक्षीय सहयोग को प्रोत्साहित कर रही है। भारत को क्षेत्रीय सुरक्षा चिंताओं को दूर करने और भारत-प्रशांत देशों के बीच बातचीत को प्रोत्साहित करने के लिए बहुपक्षीय ढांचे को बढ़ावा देना चाहिए। पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन और शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) में भारत की भागीदारी चीन के प्रभाव का मुकाबला करने सहित सुरक्षा मुद्दों पर सहयोग को बढ़ावा देती है। भारत बाहरी दबावों के खिलाफ अपनी संप्रभुता का दावा करने में छोटे देशों का समर्थन करके क्षेत्रीय स्वायत्तता और आत्मनिर्भरता को मज़बूत कर सकता है। एमजीसी (मेकांग-गंगा सहयोग) जैसी परियोजनाओं के माध्यम से चीनी आर्थिक प्रभाव का विरोध करने में श्रीलंका और नेपाल को भारत का समर्थन स्वायत्तता को बढ़ावा देने का उदाहरण है। भारत को क्षेत्रीय तनाव कम करने के लिए रक्षा ख़र्च और सैन्य गतिविधियों में पारदर्शिता के महत्त्व पर ज़ोर देना चाहिए। भारत का खुला रक्षा बजट और संयुक्त राष्ट्र शांति मिशनों में भागीदारी क्षेत्रीय विश्वास में योगदान करती है और संघर्ष के जोखिम को कम करती है। समावेशी आर्थिक विकास को बढ़ावा देकर और समान विकास सुनिश्चित करके, भारत चीन की आर्थिक जबरदस्ती का मुकाबला कर सकता है और अधिक स्थिर क्षेत्रीय सम्बंध बना सकता है। बुनियादी ढांचे में सुधार और आसियान देशों के साथ व्यापार को बढ़ावा देने पर भारत का ध्यान चीनी परियोजनाओं पर उनकी निर्भरता को कम करता है। भारत को क्षेत्र में स्थिरता बनाए रखने के लिए राजनयिक चैनलों के माध्यम से शांतिपूर्ण संघर्ष समाधान तंत्र को सक्रिय रूप से बढ़ावा देना चाहिए। भारत-चीन सीमा वार्ता में भारत की भागीदारी और दक्षिण चीन सागर विवादों पर आसियान के नेतृत्व वाली बातचीत का समर्थन क्षेत्रीय शांति के प्रति उसकी प्रतिबद्धता का उदाहरण है।

जैसे-जैसे वैश्विक शक्ति की गतिशीलता बदलती है, भारत जैसे देशों को क्षेत्रीय स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए राजनयिक और रक्षात्मक उपायों में संलग्न रहना जारी रखना चाहिए। रणनीतिक साझेदारी, रक्षा क्षमताओं के आधुनिकीकरण और राजनयिक जुड़ाव के सही संयोजन के साथ, भारत शांतिपूर्ण और स्थिर एशिया में योगदान करते हुए अपने हितों को सुरक्षित कर सकता है।

# पन्नू के नाम से एक रुढ़िवादी पत्रकार को धमकी भरा मेल

मनोरंजन सासमल , स्टेट हेड ओड़िशा

**भुबनेस्वर्:** खालिस्तानी आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू को वरिष्ठ रूढ़िवादी पत्रकार अक्षय साहू को धमकी भरा मेल मिला। मेल में फिर से डीजीपी कॉन्फ्रेंस को निशाना बनाते हुए धमकी दी गई है। पन्नू ने डीजीपी कॉन्फ्रेंस में खालिस्तानी झंडा फहराने पर 25 लाख रुपये का इनाम देने की घोषणा की है।भुवनेश्वर एयरपोर्ट को भी निशाना बनाया गया है. मेल में रविवार को भुवनेश्वर से उड़ान न भरने की चेतावनी दी गई है। हालांकि, अभी तक यह स्पष्ट नहीं है कि ईमेल पन्नू ने खुद भेजा था या उसकी ओर से किसी और ने भेजा था। गौरतलब है कि डीजीपी कॉन्फ्रेंस शुरू होने से पहले ही पन्नू ने एक वीडियो संदेश जारी कर कॉन्फ्रेंस को बाधित करने की धमकी दी थी। उन्होंने कहा कि यह डीजीपी कॉन्फ्रेंस हिंदुत्व की विचारधारा के तहत हो रही है। खालिस्तान सिख समर्थकों, कश्मीरी लड़ाकों, आतंकवादियों और उग्रवादियों को मारने की योजना बना रहा है। इसमें कहा गया कि मोदी-शाह-डोभाल भुवनेश्वर के लिए बड़ा खतरा पैदा कर रहे हैं। पन्नून ने सम्मेलन को बाधित करने के लिए खालिस्तानियों को भेष बदलकर आने और भुवनेश्वर के मंदिरों और होटलों में छिपने के लिए बुलाया।



# वन नेशन- वन सब्सक्रिप्शन स्कीम से 18% कम हो जाएगा रिसर्च खर्च, IIM मुंबई की रिपोर्ट में हुआ खुलासा

केंद्र सरकार ने हाल ही में वन नेशन-वन सब्सक्रिप्शन योजना की शुरुआत की है। इस योजना का लाभ लगभग डेढ़ करोड़ छात्रों को मिलेगा। अब भारतीय प्रबन्धन संस्थान (IIM) मुंबई के एक आकलन में यह तथ्य सामने आया है कि इस योजना की वजह से अनुसंधान (रिसर्च) का खर्च 18% तक कम हो जाएगा।

**मुंबई।** केंद्र सरकार ने हाल ही में वन नेशन-वन सब्सक्रिप्शन योजना की शुरुआत की है। इस योजना का लाभ लगभग डेढ़ करोड़ छात्रों को मिलेगा। अब भारतीय प्रबन्धन संस्थान (IIM) मुंबई के एक आकलन में यह तथ्य सामने आया है कि इस योजना की वजह से अनुसंधान (रिसर्च) का खर्च 18% तक कम हो जाएगा। वन नेशन-वन सब्सक्रिप्शन योजना के माध्यम से छात्र के एक क्लिक पर 13 हजार से अधिक रिसर्च पेपर्स उनके स्क्रीन पर होंगे। आईआईएम मुंबई के डायरेक्टर प्रो. मनोज कुमार तिवारी के मुताबिक किसी भी अनुसंधान की सफलता उसके तथ्यों और एकत्र आकड़ों के आधार पर होती हैं। इस आधार को मजबूती देने में शोधकर्ता की तकनीकी विशेषज्ञता के अलावा ऐसे कई कारक हैं, जो अनुसंधान के बुनियादी ढांचों को मजबूती देते हैं। इन सभी कारकों में शोधकर्ताओं के समय, उपकरण और उपभोग सामग्रियों की लागत और अनुसंधान सहायता सेवाओं की लागत भी शामिल होती है। तिवारी ने आगे कहा कि अनुसंधान परियोजनाओं में पैसे की कमी शोधकर्ताओं के लिए कई चुनौतियां पैदा करती हैं। अपने शोध एवं अनुसंधान की वैधता एवं विश्वसनीयता को मजबूती देने के लिए सभी संस्थाएं अब तक पृथक- पृथक तौर पर कई अंतरराष्ट्रीय शोध पत्रिकाओं की सदस्यता लेते रहे हैं।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक एवं संपादक संजय कुमार बाटला द्वारा इम्प्रेशंस प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग लिमिटेड, सी-18,19,20 सेक्टर 59, नोएडा (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित एवं 3, प्रियदर्शनी अपार्टमेंट ए-4, पश्चिमी विहार, नई दिल्ली- 110063 से प्रकाशित। सम्पर्क : 9212122095, 9811902095. newstransportvishesh@gmail.com
(इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी) किसी भी कानूनी विवाद की स्थिति में निपटारा दिल्ली के न्यायालय के अधीन होंगे। RNI No :- DELHIN/2023/86499. DCP Licensing Number F.2 (P-2) Press/2023